R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

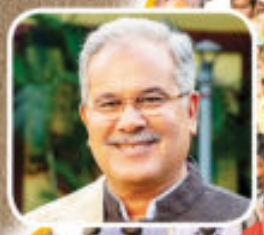

वर्ष : 20 । अंक : 21
01 से 15 अगस्त 2022
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

मुफ्त की रेवड़ियों पर लगाम कब...?

प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट भी

मुफ्तखोरी के खिलाफ

चुनावी सौगातों के कारण कंगाली के कगार पर

देश के आधे राज्य

"2007 में हमने लाड़ली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की, ताकि समाज का नजरिया बदले, इसलिए हमने योजना बनाई कि मध्यप्रदेश की धरती पर बेटी जन्म ले तो वह लखपति हो। मेरा संकल्प है कि मेरी बेटियां सशक्त होकर आगे बढ़ें, मैंने लाड़ली लक्ष्मी योजना शुरू की, आज प्रदेश में 42 लाख से अधिक लाड़ली लक्ष्मी बेटियां हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटियां प्रशासनिक अधिकारी, प्राध्यापक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर बन प्रदेश का नाम रोशन करें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी बेटियों पर अपने आशीष की वर्षा करना।"

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में लाड़ली आगे बढ़ रही... नाम रोशन कर रही...

लाड़ली लक्ष्मी योजना

स्वावलंबी बालिका, सशक्त समाज का आधार

बेटियों के प्रति समाज की नकारात्मक सोच, लड़कों के मुकाबले उनकी कम होती संख्या, बालिका शिक्षा की कमजोर स्थिति, बेटियों को जल्दी ब्याहना जैसी समस्याओं के निदान एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल, 2007 से प्रारंभ की गई। लाड़ली लक्ष्मी योजना से मिलने वाले लाभ को स्थायी बनाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई, 2018 को मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, 2018 लागू किया गया। यह अधिनियम प्रत्येक बालिका को मिलने वाली राशि की गारन्टी प्रदान करता है।

पात्रता एवं शर्तें

1. 1 जनवरी 2006 अथवा उसके बाद जन्मी बालिकाएं।
2. अनाथ या दत्तक बालिकाएं।
3. माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
4. बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो।
5. माता-पिता आयकर दाता न हों।
6. केवल दो संतान हेतु।
7. द्वितीय संतान के जन्म पर परिवार नियोजन अपनाना अनिवार्य।

योजना के लाभ

लाड़ली लक्ष्मी योजना में बालिका को-

1. रुपये 1,18,000/- का आश्वासन प्रमाण पत्र।
2. कक्षा 6वीं में प्रवेश पर छात्रवृत्ति रुपये 2,000/-
   कक्षा 9वीं में प्रवेश पर छात्रवृत्ति रुपये 4,000/-
   कक्षा 11वीं में प्रवेश पर छात्रवृत्ति रुपये 6,000/-
   कक्षा 12वीं में प्रवेश पर छात्रवृत्ति रुपये 6,000/-
3. 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1 लाख की राशि, बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण न होने व कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने की शर्त पर ई-पेमेंट के माध्यम से प्राप्त होगी।

आवेदन करें

- पात्र हितग्राही लोक सेवा केन्द्र/ इंटरनेट कैफे / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- जनसामान्य एवं प्रशासनिक सुविधा हेतु विभाग द्वारा ladlilaxmi.mp.gov.in वेबसाइट संचालित की जा रही है।

श्योपुर जिले के मेनपुरा ग्राम की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली **गौरी** की आगे की पढ़ाई बंद कराने का निर्णय ले लिया गया था। गौरी को कक्षा 9वीं की पढ़ाई करने के लिए अपने गांव से बाहर जाना था। गांव की काफी लड़कियों की पढ़ाई इसी कारण छूट गई थी, परन्तु गौरी आगे पढ़ना चाहती थी। इसलिये उसने अपने साथ गांव के बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिये अपनी दो सहेलियों को तैयार किया। उनके घर वालों से बात करके आंगनवाड़ी दीदी को बताया कि हम आगे पढ़ना चाहते हैं। गौरी के पिता हरिराम एवं माता दुलारी दोनों मजदूरी करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दीदी ने गौरी के माता-पिता से बात की, उन्हें बताया कि गौरी लाड़ली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत है। उसे कक्षा 9वीं में रुपये 4000/- की छात्रवृत्ति मिलेगी। फिर कक्षा 11वीं और 12वीं में रुपये 6000/- की छात्रवृत्ति मिलेगी। यदि पढ़ाई बीच में छोड़ दी तो लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ 1 लाख की राशि नहीं मिलेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने सुझाव दिया कि जिस स्कूल में गांव की लड़कियां पढ़ रही हैं, उसी में गौरी भी पढ़ सकती है। गौरी के माता-पिता इस बात पर सहमत हो गये और उसका कक्षा 9वीं में एडमिशन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हजारेश्वर में करा दिया। इस तरह लाड़ली लक्ष्मी योजना **गौरी** की पढ़ाई में मददगार बनी।

लाड़ली लक्ष्मी योजना के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं...

उपलब्धियां

मध्यप्रदेश के 52 जिलों के 313 विकासखण्डों के 52,117 गांवों में योजनान्तर्गत अब तक 42 लाख से अधिक बालिकाओं का पंजीयन किया जा चुका है एवं लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि में रुपए 10,654 करोड़ की राशि जमा की गई है। योजना प्रारंभ से अब तक कक्षा 6वीं, 9वीं, 11वीं एवं 12वीं में प्रवेशित कुल 9 लाख से अधिक बालिकाओं को राशि रुपए 231.07 करोड़ की छात्रवृत्ति का वितरण किया जा चुका है।

NHFS-5 के अनुसार

मध्यप्रदेश में बाल विवाह में **9.3%** की कमी आई है।

जन्म के समय लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हो चुका है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0

बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए विभाग ने लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 तैयार कर प्रारंभ की है। इसमें बालिकाओं को उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुनिश्चितता का प्रावधान किया गया है।

लाड़ली e-संवाद

लाड़लियों से माननीय मुख्यमंत्री जी के संवाद हेतु लाड़ली मोबाइल एप तैयार किया गया है। Google Play Store से यह एप download किया जा सकता है।

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crisp.ladlilaxmiyojna

माँ तुझे प्रणाम

इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित 178 लाड़ली बालिकाओं को देश की सीमा "बाघा बार्डर" का भ्रमण कराया गया।

मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद

"लाड़ली लक्ष्मी" योजना और "माँ तुझे प्रणाम" योजना हमें प्रभावित करती है आगे बढ़ने के लिए। हमारे भविष्य को साकार करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

कु. एंजेल जैन, लाड़ली लक्ष्मी, मंडला

बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए दृढ़ संकल्पित मध्यप्रदेश सरकार

D-19283/22

इस अंक में

राजपाट

9 | **महिलाएं ही शक्ति**

देश में महिला राष्ट्रपति के चुने जाने के बाद फिर से नारी सशक्तिकरण की बातें की जाने लगी हैं। मप्र में हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनावों में भी महिलाओं का वर्चस्व बढ़ा है। बात करें प्रदेशभर के 16 नगर...

राजपथ

10-11 | **सेमीफाइनल में भाजपा अव्वल**

2023 में सत्ता के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले हुए सेमीफाइनल में मप्र की जनता ने पंचायत और निकाय चुनाव में भाजपा पर विश्वास जताकर यह संकेत दे दिया है कि देश के हृदय प्रदेश को शिव'राज' ही पसंद है।

चौसर

13 | **अब मिशन 2023 की रणनीति**

विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के जो परिणाम हैं वे भाजपा और कांग्रेस के लिए रणनीति बनाने का आधार बनेंगे। इन चुनावों के नतीजे विधानसभा चुनाव का आईना हैं। अत: पार्टियां इसी के आधार पर मिशन...

उपलब्धि

15 | **बुरहानपुर बना प्रेरणा**

जल जीवन मिशन के तहत मप्र के बुरहानपुर ने अपना झंडा गाड़ दिया है। बुरहानपुर देश का एकमात्र जिला है, जहां 100 फीसदी घरों में नल से जल पहुंच रहा है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत देश के 110 जिलों में प्राथमिकता के तौर पर नल से जल पहुंचाने का अभियान शुरू...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का सिलसिला अब विकराल रूप ले चुका है। इससे लोकतंत्र की गरिमा को आघात पहुंच रहा है। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुफ्त की बंदरबाट पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन भारत में ऐसी कोई प्रमुख पार्टी नहीं है, जिसने चुनावों के दौरान मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की सियासत न की हो। इसी प्रचार पर फोकस रखा जाता है-'मुफ्त ले लो, पर वोट हमें दे दो।'

राजनीति

30-31 | **कांग्रेस की राह आसान नहीं**

2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस की कोशिश है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वह भाजपा के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरे, लेकिन पार्टी के हालात देखकर साफ लग रहा है कि कांग्रेस के लिए आगे की राह...

महाराष्ट्र

35 | **अब शिवसेना के लिए रार...**

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी के बाद अब पार्टी (शिवसेना) पर घमासान तेज हो गया है। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी की पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर दी गई। शिंदे गुट ने इसके साथ ही नई कार्यकारिणी का ऐलान भी...

बिहार

39 | **8वीं अनुसूची में शामिल होगी...**

पिछले पांच दशक से भोजपुरिया समाज भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग कर रहा है। लेकिन आज तक इस मांग पर कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई है। हर बार नियमों का हवाला देकर इस मांग को खारिज कर दिया जाता है।

6-7	अंदर की बात
29	मुद्दा
41	अध्यात्म
43	कहानी
44	खेल
45	फिल्म
46	व्यंग्य

अपनी बात

हमसे आगे कोई नहीं...!

अदा जाफरी का एक शेर है

मैं आंधियों के पास तलाश-ए-सबा में हूं
तुम मुझसे पूछते हो मिरा हौंसला है क्या

शायर की यह पंक्तियां देश की वर्तमान राजनीति पर बड़ा व्यंग्य है। यानी इस समय जिस तरह साम-दाम, दंड-भेद की राजनीति चल रही है, उस संदर्भ में शायर ने ठीक ही कहा है कि लोग अपने अंदर झांकने की बजाय दूसरों पर तोहमत लगाते फिरते हैं। मप्र तो इस मामले में सबसे आगे है। देश के किसी भी कोने में कोई अनैतिक कार्य होता है तो मप्र में उसके खिलाफ सबसे पहले एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। राजनीति से प्रेरित होने वाली इन एफआईआर से वैसे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन सबसे आगे रहने की होड़ में अपनी ही पुलिस पर भार लाद दिया जाता है। हाल ही में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 'राष्ट्रपत्नी' के रूप में संबोधित करने पर बिना सोचे-समझे प्रदेश सरकार में मंत्री रहे एक माननीय ने आव देखा न ताव और डिंडौरी में एफआईआर दर्ज करा दिया। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा मां काली पर विवादित बयान देने के कारण एफआईआर दर्ज करा दी गई। ऐसे ही कई फिल्मी हस्तियों, नेताओं और न जाने किन-किन पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। यही नहीं दो साल में प्रदेश में राजद्रोह के 10 केस दर्ज किए गए हैं। केस दर्ज कराने से पहले किसी ने यह तनिक भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। पहले से ही हमारे थानों और अदालतों में केस की भरमार है। ऐसे में राजनीति से प्रेरित केस दर्ज कराकर हम क्या दर्शाना चाहते हैं। अगर वर्तमान संदर्भ को देखें तो अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 'राष्ट्रपत्नी' कहना इतना बड़ा अपराध नहीं है, जिसे तूल दिया जा रहा है। अधीर रंजन के संवाद को देखकर साफ लग रहा है कि उन्होंने दुर्भावना से ग्रसित होकर राष्ट्रपत्नी शब्द का उपयोग नहीं किया है। उनकी क्षेत्रीय भाषा का असर हो सकता है कि उन्होंने राष्ट्रपत्नी शब्द का उपयोग कर दिया। लेकिन जिस तरह इस मामले को तूल दिया जा रहा है, इससे साफ दिख रहा है कि इसमें राजनीति का खेल है। जब यूपीए ने 2007 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान की पूर्व राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को मैदान में उतारने का फैसला किया, तो इस मुद्दे पर कुछ चर्चा और अटकलें थीं। यह पहली बार था कि भारत में एक महिला राष्ट्रपति होगी और इस बारे में उत्सुकता थी कि राष्ट्र उनके पद के नामकरण पर कैसे बातचीत करेगा। दिए गए सुझावों में 'राष्ट्रपत्नी' भी शामिल था, हालांकि इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं और नारीवादियों ने 'राष्ट्रमाता' जैसी अभिव्यक्तियों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि संवैधानिक पद के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल 'पितृसत्ता' और 'लिंग-भेद' को बढ़ावा देता है। संवैधानिक विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि राष्ट्रपति शब्द, जिसे संविधान सभा में चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया गया था, को केवल इसलिए नहीं बदला जाना चाहिए क्योंकि भारत में एक महिला राष्ट्रपति है। क्योंकि इस शब्द का कोई लिंग अर्थ नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि 'प्रेसिडेंट' का हिंदी तर्जुमा 'राष्ट्रपति' के रूप में होता है। संवैधानिक विशेषज्ञों ने तब बताया कि संविधान में अन्य पुलिंग शब्दों वाले नामकरण हैं, लेकिन इसे पितृसत्तात्मक या लिंग असंवेदनशीलता के रूप में नहीं देखा जा सकता है। कांग्रेस सांसद ने राष्ट्रपत्नी शब्द कहने पर माफी मांग ली है, इसलिए मामले को तूल देने की जरूरत नहीं है।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 20, अंक 21, पृष्ठ-48, 1 से 15 अगस्त, 2022

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी
फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,
फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,
भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर,
मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

aksnews.com

मेट्रो का काम तेजी पर

राजधानी भोपाल और इंदौर में मेट्रो का काम तेजी से किया जा रहा है। आने वाले कुछ सालों में दोनों महानगरों में मेट्रो दौड़ने लगेगी। तैयार हो रही मेट्रो रेल के ट्रैक पर अत्याधुनिक फ्रांसिसी मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। इस मेट्रो ट्रेन परियोजना से लाखों लोगों को सुविधा मिलेगी।

● **प्रिया सोनी,** इंदौर (म.प्र.)

सख्त कार्यवाही हो

सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी मप्र में रेत, गिट्टी का अवैध उत्खनन नहीं रुक रहा है। मप्र की शिवराज सरकार को इस अवैध उत्खनन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। शासन-प्रशासन को माफियाओं के खिलाफ और अधिक सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

● **महेंद्र जाटव,** भोपाल (म.प्र.)

जंगल माफिया पर नकेल

एक समय मप्र हरियाली प्रदेश के नाम से ख्यात था, लेकिन आज वन माफिया जहां सागौन के जंगल साफ कर रहे हैं वहीं पेड़ काटने के बाद जंगल की जमीन पर अतिक्रमण भी करवा रहे हैं। प्रदेश सरकार को इन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए कड़ी कार्यवाही करनी होगी।

● **कुणाल शर्मा,** सीहोर (म.प्र.)

विपक्षी एकता कमजोर

देश की राजनीति में विपक्षी एकता कमजोर नजर आ रही है। इसका नजारा राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिला, जहां एनडीए की उम्मीदवार को भरपूर वोट मिले, वहीं यूपीए के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। बड़े-बड़े दिग्गजों की एकता भी यूपीए के उम्मीदवार को जिता नहीं पाई। विपक्ष के एक दल शिवसेना ने ममता बनर्जी की अगुवाई में खड़े किए गए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का साथ छोड़ दिया था। इसके पहले कई अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी एनडीए का समर्थन किया। वहीं राष्ट्रपति चुनाव वाले दिन भी क्रॉस वोटिंग की गई। जिससे एनडीए उम्मीदवार का जीतना लगभग तय हो ही गया था। क्या विपक्षी एकता इतनी कमजोर हो गई है, यह सोच का विषय है।

● **आशीष वर्मा,** नई दिल्ली

भाजपा की रणनीति

परिवारवादी पार्टियों के नेताओं का सामंतवादी रवैया और रहन-सहन दूसरी पीढ़ी आते-आते आम लोगों को खटकने लगता है। मोदी और भाजपा को समझ में आ गया है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सुशासन (केंद्रीय योजनाओं का असर) और सामाजिक गठजोड़ एक सीमा के बाद असर नहीं डालता। मतदाता लोकसभा चुनाव में दूसरी तरह मतदान करता है और वह मोदी के साथ खड़ा नजर आता है, पर विधानसभा चुनावों में भाजपा का मत प्रतिशत गिर जाता है। इसलिए अब भाजपा नई रणनीति बना रही है।

● **सुभाष सिंह,** ग्वालियर (म.प्र.)

विधायकों का वेतन भत्ता

मप्र सरकार हजारों करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी है। बैठकों और भाषणों में सरकारी खर्चों में कटौती की बात की जाती है, लेकिन फिजूलखर्ची के मामले में सरकार अभी भी पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। और तो और विधायकों ने भी अपना वेतन भत्ता बढ़वाने की मांग उठा रखी है। सरकार चाहे तो ये पैसा बचा सकती है। ये भत्ते तब दिए जाते थे जब मंत्रियों और विधायकों का वेतन बहुत कम था। लेकिन वर्तमान में विधायकों को कई भत्ते दिए जाते हैं।

● **आमीन शेख,** गुना (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

प्रतिष्ठा की लड़ाई

छोटा राज्य होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बना हुआ है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह प्रदेश होने की वजह से पार्टी के सामने हर हाल में अपनी सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस भाजपा से सत्ता छीनने के लिए दांव आजमा रही है। सारा दारोमदार सामाजिक समीकरणों पर है और दोनों दल इनको साधने में जुट गए हैं। हिमाचल प्रदेश की 68 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल भाजपा सत्ता में है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए भी यह चुनाव काफी अहम हैं क्योंकि पिछली बार भाजपा ने चुनाव प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में लड़ा था, लेकिन वह चुनाव हार गए, जिसकी वजह से जयराम ठाकुर को कमान सौंपी गई थी। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की सारी कमान उनके हाथों में ही रहेगी। राज्य के सामाजिक समीकरणों में लगभग आधी आबादी सवर्ण जाति की है। उसमें भी राजपूत वर्ग का बाहुल्य है। लगभग 32 फीसदी आबादी राजपूत है, जबकि दूसरे नंबर पर दलित समुदाय हैं, जिसकी आबादी 25 फीसदी है। इसके बाद ब्राह्मण 18 फीसदी व अन्य पिछड़ा वर्ग 14 फीसदी है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग साढ़े पांच फीसदी है।

मिशन 2023 के लिए आरएसएस का चिंतन शिवर

अगले साल 2023 में होने वाले लगभग एक दर्जन राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता एक चिंतन शिविर का आयोजन कर सकते हैं। माना जा रहा है कि यह कार्यक्रम इसी महीने कर्नाटक के बेंगलुरू शहर में हो सकता है। इस चिंतन शिविर में सूबे के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और भाजपा के राज्य इकाई के प्रमुख नलिन कुमार कटील भी शामिल हो सकते हैं। इससे पहले 30 जून को भाजपा चीफ की मुलाकात मुकुंद और सुधीर सरीखे वरिष्ठ संघ प्रचारकों के साथ हुई थी। बेंगलुरू स्थित संघ मुख्यालय केशवकृपा में इनके बीच करीब 45 मिनट तक मंथन चला था। सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है कि संघ इन चुनावों में भाजपा की जीत को लेकर चिंतित है। संघ की इस चिंता के संकेत ऐसे वक्त पर देखने को मिल रहे हैं, जब देश में 'हिजाब' और 'हलाल' सरीखे मुद्दे छाए हुए हैं। यही नहीं, संघ उन विपक्षी नेताओं से भी परेशान है, जो लगातार उस पर हमले बोल रहे हैं। यह चिंता इसलिए भी मायने रखती है और बढ़ जाती है, क्योंकि पूर्व में भाजपा के नेता कांग्रेस के सिद्धारमैया के हमलों पर जवाब देने में नाकामयाब रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस आयोजन में विभिन्न मसलों पर चर्चा की जा सकती है।

सिद्धारमैया, शिवकुमार, कांग्रेस, कर्नाटक

कर्नाटक कांग्रेस में हाल के दिनों में अंदरूनी कलह के चलते पार्टी में दरार बढ़ने लगी है। पार्टी के दो टॉप नेता पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख डीके शिवकुमार एक-दूसरे के आमने-सामने आ चुके हैं। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि संयुक्त मोर्चा बनाने की पार्टी की संभावना कम हो गई है, जिससे आगामी चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को हराना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। जानकारों के मुताबिक जिला स्तर के नेताओं से परामर्श किए बिना दूसरे दलों के वर्तमान और पूर्व विधायकों सहित अन्य नेताओं को पार्टी में शामिल करने से दरार बढ़ी है। साथ ही पार्टी के भीतर गुटबाजी भी बढ़ती जा रही है। इन दो दिग्गज नेताओं के मध्य असल मुद्दा यह है कि मुख्यमंत्री प्रत्याशी के तौर पर किसकी घोषणा होगी और पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो अंत में किसे यह कुर्सी सौंपी जाएगी। इस विवाद को खत्म करने के लिए पार्टी आलाकमान दोनों नेताओं को पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर काम करने का निर्देश दे सकती है। गौरतलब है कि जनता दल सेक्युलर के विधायक श्रीनिवास गौड़ा हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिन्होंने 10 जून के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी।

भाजपा में शामिल होंगे आनंद शर्मा

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की खबरों को खारिज किया जा चुका है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि जल्द ही आनंद शर्मा भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। इस तरह की अटकलों को लेकर पार्टी असहज है। पार्टी मानती है कि इस तरह की अटकलों से हिमाचल प्रदेश चुनाव में राजनीतिक नुकसान हो सकता है। क्योंकि आनंद शर्मा विधानसभा चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। इन अटकलों को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि आनंद शर्मा कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं की फेहरिस्त में शामिल हैं। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें हरियाणा या किसी अन्य प्रदेश से उम्मीदवार बना सकती है। मगर पार्टी ने राज्यसभा के लिए टिकट नहीं दिया। हालांकि उनकी नाराजगी को कम करने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ कई बैठकें हुई हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस तरह की अटकलों से चुनाव पर असर पड़ सकता है।

बैकफुट पर गुजरात कांग्रेस

गोवा कांग्रेस में बगावत फिलहाल थम गई है। लेकिन कांग्रेस की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। पार्टी को डर है कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में उसके कई विधायक पाला बदल सकते हैं। इसके लिए पार्टी सभी विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में जुट गई है। गुजरात में कांग्रेस के वर्तमान में 64 विधायक हैं। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 77 सीट मिली थी, मगर पिछले दो साल में 14 विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी के पार्टी में शामिल होने से यह आंकड़ा 64 पर पहुंचा है। पार्टी इन विधायकों को हर हाल में अपने साथ बरकरार रखना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि महाराष्ट्र और गोवा की तरह भाजपा गुजरात में भी कांग्रेस विधायकों से संपर्क कर रही है। भाजपा की कोशिश है कि चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर कांग्रेस विधायकों को पार्टी में शामिल किया जाए, ताकि वह चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बना सके।

भ्रष्टाचार की जांच पड़ी भारी

प्रदेश में एक तरफ सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों पर गाज गिराने में तनिक भी देरी नहीं की जा रही है। अभी हाल ही में प्रदेश के एक बड़े महकमे में तैनात 2011 बैच की एक महिला आईएएस अधिकारी को इसलिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि मैडम एक बड़े भ्रष्टाचार की जांच कर रही थीं और मामले की तह तक पहुंच गई थीं। भ्रष्टाचार की परतें खुलतीं इससे पहले ही मैडम को अपात्र बताकर विभाग से चलता कर दिया गया। दरअसल, मैडम जिस विभाग से बदली गई हैं, उस विभाग में कार्य कर चुके एक पूर्व अधिकारी द्वारा की गई फर्जी नियुक्ति की जांच कर रही थीं। बताया जाता है कि जांच में पूर्व अधिकारी द्वारा फर्जी तरीके से नियुक्ति देने और मनमाने तरीके से वेतन बढ़ाने की बात सामने आई है। साथ ही मामले में अपराधिक मामला दर्ज करने की अनुशंसा कर दी। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में मैडम पर दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने वरिष्ठों की भी नहीं सुनी। जिसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही मैडम ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किए जाने के मामले को महिला अधिकारियों के वॉट्सएप ग्रुप में लिखा था। बताया जाता है कि इसके पीछे भी उपरोक्त जांच ही थी, जिसकी आंच में अब मैडम की विभाग से रवानगी हो गई है।

दो नेताओं की जुगलबंदी

राजधानी में इन दिनों दो नेताओं की जुगलबंदी चर्चा में है। यहां बता दें कि अलग-अलग विचारधारा की पार्टी से होने के बावजूद चुंबकीय गुण के कारण इन दोनों नेताओं की दोस्ती इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इनमें से एक सरकार में हैं और राजधानी में इनका दबदबा है। वहीं दूसरे नेता भी शहर के युवाओं में अच्छी पैठ रखते हैं। इनका शहर में शिक्षा का कारोबार है। ये भी विधानसभा चुनाव लड़े थे और हार गए। बताया जाता है कि एक ही जाति-बिरादरी के होने के कारण इन दोनों नेताओं की पिछले कुछ सालों से नजदीकी इस कदर बढ़ गई है कि अक्सर ये साथ-साथ देखे जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि एक नेताजी के पास जिस विभाग की कमान है, उससे संबंधित कारोबार में दूसरे नेताजी लगे हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों नेता मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। बता दें कि राजधानी में तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। सूत्रों का कहना है कि ऐसे में दोनों नेताओं की कोशिश हो सकती है कि तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अनूठी पहल की जाए। असल में इन दोनों नेताओं की जुगलबंदी की असली वजह क्या है, यह तो यही बता सकते हैं लेकिन प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

प्रभारी सब पर भारी

प्रदेश के दो बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली इसलिए लागू की गई थी कि लोगों को त्वरित और आसानी से न्याय मिल सके। साथ ही योग्य अफसरों के हाथ में कानून व्यवस्था की कमान रहे। लेकिन देखा यह जा रहा है कि राजधानी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को नेताओं की सांठगांठ ने ठेंगा दिखा दिया है। इसका असर यह है कि राजधानी में थाना प्रभारी ही सब पर भारी पड़ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी की सीमाओं पर स्थित दो थानों के थाना प्रभारी सब पर भारी पड़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दोनों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। एक थाना प्रभारी तो ऐसे हैं जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली के नियमों को दरकिनार कर पदस्थ किए गए हैं। यानी ये साहब 2016 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं, लेकिन इन्हें राजधानी के सबसे बड़े प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले थाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। बताया जाता है कि इन पर संगठन के बड़े पदाधिकारी का ही वरदहस्त है। वहीं एक थाने के थानेदार ऐसे हैं जो अपने आपको रॉबिनहुड समझते हैं। ये अपने थानाक्षेत्र में फिल्मी स्टाइल से काम करते हैं। साहब पर एक मंत्री का हाथ है। इसका असर यह हो रहा है कि साहब को कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है। इसका असर यह हो रहा है कि साहब अपने थानाक्षेत्र में एक विवादित जमीन पर अपना मकान बनवा रहे हैं और इसके लिए ईंट, गिट्टी, पत्थर सब जबर्दस्ती वसूल रहे हैं। शिकायतें ऊपर तक गई हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है।

चोरी का माल सब कोई खाए

यह कहावत आपने सुनी ही होगी कि चोरी का माल सब कोई खाए, चोर की जान अकारथ जाए। यह कहावत प्रदेश के कई नौकरशाहों पर सटीक बैठती है। दरअसल, राजधानी में कुछ प्रभावशाली लोग ऐसे हैं, जो नौकरशाहों की काली कमाई को संभालकर रखते हैं। ऐसे में कई नौकरशाह दिवंगत हो गए और इन लोगों ने उनकी संपत्ति हड़प ली। ऐसे ही 1985 बैच के एक आईएएस का देहांत लंबी बीमारी के बाद मार्च में हो गया। इनकी भी काली कमाई शहर के दो प्रभावशाली लोगों के पास रखी थी। इन्होंने उसे अपने शागिर्दों में बांट रखी थी। लेकिन विगत दिनों एक ऐसी घटना सामने आई, जिसमें जिस प्रॉपर्टी की पावर ऑफ एटॉर्नी किसी और के पास थी उसे एक महिला ने बेच दिया। उक्त महिला दिवंगत साहब से लंबे समय से जुड़ी थी। यह बात प्रभावशाली लोगों को नागवार गुजरी और उन्होंने उक्त महिला पर एफआईआर दर्ज करवा दी। मजे की बात यह है कि दिवंगत साहब की धर्मपत्नी जिंदा है और दूसरी महिला उनकी संपत्ति बेचकर चली गई। अब लोग इस रहस्य को समझने में लगे हुए हैं।

अब किसी काम के नहीं...

कुछ समय पहले तक सरकार की नाक के बाल रहे एक आईपीएस अधिकारी अब किसी काम के नहीं रह गए हैं। शायद यही वजह है कि कमाऊ विभाग में रहे इन साहब को तबादले के बाद अभी तक कोई काम नहीं दिया गया है। गौरतलब है कि 1989 बैच के उक्त आईपीएस अधिकारी को सरकार ने प्रदेश के सबसे कमाऊ विभाग की जिम्मेदारी दे रखी थी। बताया जाता है कि साहब ने विभाग का दुधारू गाय की तरह दोहन किया। साहब की अंधाधुन कमाई की शिकायत कई स्तरों पर पहुंची। लेकिन साहब आंख बंद कर कमाने में इस कदर लगे रहे कि उन्हें किसी की फिकर नहीं रही। शिकायतों और विवादों के बाद भी साहब की लालसा कम होता न देख उन्हें सरकार ने विभाग से चलता कर दिया। अब आलम यह है कि साहब को विभाग से हटे पखवाड़ा भर समय हो गया है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। यही नहीं साहब ने अपने जिस राजनीतिक आका के दम पर कमाऊ कुर्सी पाई थी, उन्होंने भी उनसे मुंह मोड़ लिया है। अब देखना है साहब को नया काम कब मिलता है।

हमने पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर 3-4 पीढ़ियों के लिए काफी कमाया है। अब बलिदान का समय आ गया है। अगर हम उन कर्जों को चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मुझे डर है कि हम जो खाना खाएंगे उसमें कीड़े लग जाएंगे।

● **रमेश कुमार**

अफसर ने धार्मिक कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया है कनपटी पर बंदूक नहीं रखी। स्वेच्छा है पुण्य कार्यक्रम में आप आना चाहते हैं या नहीं। किसी को कार्यक्रम में रहना है या नहीं यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। जब हम किसी को निमंत्रण देते हैं तो उसकी स्वेच्छा पर छोड़ते हैं। कार्यक्रम में कुछ लोग पहुंचते हैं और कुछ नहीं पहुंचते।

● **रेखा आर्य**

अगर मुझे उनके साथ महज 20 मिनट मिल जाएं तो मैं विराट कोहली को वे बातें बता पाऊंगा जो उन्हें फॉर्म में वापसी करा सकती हैं। इतना ही नहीं, मैं उनकी ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंदों पर आउट होने की समस्या को पूरी तरह खत्म कर सकता हूं। ओपनर के नाते उस लाइन से परेशान होने के कारण कुछ चीजें हैं, जो आप करते हैं।

● **सुनील गावस्कर**

मैं देशभर में अपना संदेश देने के लिए रात-दिन काम करूंगा। मेरे मूल्य थैचराइट हैं। मैं कड़ी मेहनत, परिवार और अखंडता में विश्वास करता हूं। मैं थैचराइट हूं, मैं थैचराइट के रूप में चल रहा हूं और मैं थैचर के रूप में शासन करूंगा। मैं राष्ट्रीय संप्रभुता में विश्वास करता हूं।

● **ऋषि सुनक**

खूबसूरती की तारीफ करना गलत नहीं है, लेकिन खुशी होगी अगर टैलेंट की बात भी की जाए और एक दिन यह होगा भी। धीरे ही सही, पर बदलाव आएगा। हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जी रहे हैं। इसलिए अपने काम पर ध्यान दें। कई लोग अब भी यही मानते हैं कि औरतें सिर्फ गृहस्थी संभाल सकती हैं। अब जब वे और भी बहुत कुछ कर रही हैं तो तकलीफ हो रही है। मेरे पिता पुलिस ऑफिसर रहे हैं। मेरी बहन आर्मी में है। मेरी परवरिश में ही मुझे ऐसी मानसिकता से डरना घबराना सिखाया ही नहीं गया है। मैं ऐसे लोगों को इग्नोर ही करती हूं, लेकिन जवाब देने का मौका आया तो करारा जवाब भी दूंगी।

● **दिशा पाटनी**

वाक्युद्ध

पश्चिम बंगाल में मंत्री पार्थ बनर्जी की करीबी के यहां मिले 20 करोड़ रुपए इस बात का संकेत है कि राज्य में भ्रष्टाचार किस चरम पर है। भ्रष्टाचार के खिलाफ दम भरने वाली ममता बनर्जी की शह पर युवाओं के साथ धोखाधड़ी कर यह राशि अर्जित की गई है। यह तो सिर्फ नमूना है, प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहरी हैं।

● **अधीर रंजन चौधरी**

मैं हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। पार्थ बनर्जी मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी दोषी पाया जाता है, उसे आजीवन सजा मिलनी चाहिए। जांच में गड़बड़ी निर्दोष को सजा दिला सकती है। मैं हमेशा चाहती हूं कि दोषी व्यक्ति को सजा मिले। मेरे राज्य में भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे जो कोई हो।

● **ममता बनर्जी**

महिलाएं ही शक्ति

देश में महिला राष्ट्रपति के चुने जाने के बाद फिर से नारी सशक्तिकरण की बातें की जाने लगी हैं। मप्र में हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनावों में भी महिलाओं का वर्चस्व बढ़ा है।

बात करें प्रदेशभर के 16 नगर निगमों की, तो इसमें 9 महापौर अब महिलाएं हो गई हैं। वहीं इन्हीं नगर निगमों की बात करें तो 884 पार्षद पदों में से करीब 450 पर महिलाओं का कब्जा है।

बता दें कि भोपाल में मालती राय, ग्वालियर में शोभा सिकरवार, सिंगरौली में रानी अग्रवाल, बुरहानपुर में माधुरी पटेल, सागर में संगीता तिवारी, खंडवा में अमृता यादव, कटनी में प्रीति सूरी, मुरैना में शारदा सोलंकी, देवास में गीता अग्रवाल चुनी गई हैं। इनमें रानी अग्रवाल ने नारी शक्ति का मान और ऊंचा किया है, क्योंकि उन्होंने मुकाबले में प्रदेश की दो दमदार पार्टियों के पुरुष प्रत्याशियों को मात दी है। आज हम बात करते हैं इन्हीं 9 महापौर की, कैसे ये राजनीति में आईं, कैसा संघर्ष रहा और अपनी मेहनत से नगर सरकार की प्रमुख बन गईं।

नगरीय निकाय चुनाव के जो परिणाम आए हैं, उसके अनुसार 16 नगर निगमों में से 9 नगर निगमों की महापौर महिलाएं बनी हैं। ऐसे में अब यह देखना है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अपने नगर निगम को किस तरह चलाती हैं।

(सिंगरौली) रानी अग्रवाल- सिंगरौली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल चुनकर आई हैं। वे 9352 वोटों से जीती हैं। रानी अग्रवाल भाजपा से जुड़ी रही हैं। उन्होंने 2014 में बरगवां क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य के रूप में अपनी किस्मत आजमाई थी और चुनाव भी भारी मतों से जीती थीं। वे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। उन्होंने 2018 में भी आप से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, पर तीसरे नंबर पर रहीं। लगातार सक्रिय रहीं। आने वाले समय में पार्टी इन्हें सांसद का उम्मीदवार भी बना सकती है।

(भोपाल) मालती राय- भोपाल में मालती राय महापौर के लिए चुनी गई हैं। उन्होंने करीब 98000 वोटों से जीत हासिल की है। मालती 1985 से भाजपा की सक्रिय सदस्य रही हैं। वे पहले अशोका गार्डन वार्ड से पार्षद रह चुकी हैं। वे दो बार पार्षद का चुनाव हार भी चुकी हैं। विश्वास सारंग की सिफारिश पर उन्हें महापौर का टिकट मिला था।

(ग्वालियर) शोभा सिकरवार- ग्वालियर की नगर सरकार पर 57 साल बाद कांग्रेस ने जीत हासिल की है। शोभा सिकरवार ने 28805 वोटों जीत हासिल की है। शोभा सिकरवार का पूरा परिवार राजनीति में है, उनके पति, ससुर, देवर सभी लोग राजनीति में काफी सक्रिय हैं और भाजपा का हिस्सा रह चुके हैं। शोभा सिकरवार ने तीन बार पार्षद और एक बार एमआईसी की सदस्य का चुनाव जीता है। उनका राजनीतिक कैरियर साल 2004 से शुरू हुआ, जब उन्होंने ग्वालियर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 40 से पार्षद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद, 2009 में वार्ड 56 और 2014 में वार्ड क्रमांक 45 से चुनाव लड़ा और फिर पार्षद बनीं।

(बुरहानपुर) माधुरी पटेल- बुरहानपुर में बड़ा नजदीकी मुकाबला रहा था। भाजपा की माधुरी पटेल 342 वोटों से जीती हैं। वे दूसरी बार महापौर बनी हैं। इससे पहले 2010 के चुनाव में भी वे जीती थीं। माधुरी लंबे समय से भाजपा से जुड़ी रही हैं। इनके पति भी महापौर रह चुके हैं। माधुरी जिला उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं।

(सागर) संगीता तिवारी- सागर से महापौर चुनी गईं संगीता तिवारी ने 12,665 वोटों से जीत हासिल की। संगीता तिवारी फिल्म अभिनेता मुकेश तिवारी की भाभी हैं। उन्होंने इनके लिए काफी प्रचार किया। संगीता के पति सुशील तिवारी पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से दो बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके है, लेकिन दोनों ही चुनावों मे उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

(खंडवा) अमृता यादव- खंडवा महापौर बनीं अमृता यादव ने ये चुनाव 19,763 वोटों से जीता है। अमृता यादव के पति अमर यादव न केवल पार्षद रहे हैं, बल्कि वे नगर निगम में सभापति भी रहे हैं। अमृता की जेठानी ने भी महापौर पद के लिए दावेदारी जताई थी, पर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया।

(कटनी) प्रीति सूरी- कटनी महापौर चुनी गईं निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी करीब 5 हजार मतों से जीती हैं। उन्होंने भाजपा से बगावत कर चुनाव लड़ा था। प्रीति सूरी लक्ष्मीबाई वार्ड से 2009 और 2014 में लक्ष्मीबाई वार्ड से पार्षद रहीं। उस समय यह भाजपा की टिकट पर ही पार्षद रही थीं। 2004 में इनके पति संजीव सूरी इसी वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते थे।

(मुरैना) शारदा सोलंकी- कांग्रेस की शारदा राजेंद्र सोलंकी 14,631 वोट से जीतकर मुरैना की पहली महिला महापौर बन गई हैं। शारदा पिछले निगम चुनावों में भी कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरी थीं। हालांकि शारदा को पिछले चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। शारदा के जेठ बाबूलाल सोलंकी मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। पति राजेंद्र सोलंकी व बेटा सौरभ सोलंकी कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। शारदा का परिवार दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का करीबी माना जाता है।

(देवास) गीता अग्रवाल- देवास महापौर की कुर्सी पर भाजपा प्रत्याशी गीता अग्रवाल ने 45,884 वोटों से कब्जा कर लिया। ऐन वक्त पर इनका टिकट तय किया गया था। गीता अग्रवाल एक गृहिणी हैं। गीता के पति दुर्गेश अग्रवाल पूर्व में देवास विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और विधायक गायत्री राजे पवार के विधायक प्रतिनिधि भी रहे हैं। गीता अग्रवाल पति के साथ अग्रवाल समाज के अलावा अन्य समाजों के धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अक्सर नजर आती हैं।

● **राजेश बोरकर**

2023 में सत्ता के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले हुए सेमीफाइनल में मप्र की जनता ने पंचायत और निकाय चुनाव में भाजपा पर विश्वास जताकर यह संकेत दे दिया है कि देश के हृदय प्रदेश को शिव 'राज' ही पसंद है। पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को जीत मिली है, वहीं नगरीय निकाय चुनावों में भी भाजपा के 90 प्रतिशत प्रत्याशी जीते हैं। हालांकि भाजपा 16 नगर निगमों में से 9 के ही महापौर पद जीत पाई है, लेकिन हर जगह भाजपा की ही परिषद बनेगी।

सेमीफाइनल में भाजपा अव्वल

इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के सामने कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम, निर्दलीय चुनौती के रूप में खड़े थे, लेकिन मप्र के मतदाताओं ने सबको दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्यों पर मुहर लगाते हुए यह संकेत दे दिया है कि मिशन 2023 में वह भाजपा के साथ है। हालांकि नगरीय निकाय चुनाव में 90 फीसदी जीत के बाद भी भाजपा के सामने यह चुनौती है कि चुनाव के दौरान जो खामियां आई हैं, उन्हें दूर किया जाए। वहीं कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसके अस्तित्व के लिए एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी खतरा बनकर सामने आ रही हैं। इन दोनों नई नवेली पार्टियों ने निकाय चुनाव में अपनी जबर्दस्त धमक दिखाई है।

कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव में मतदाताओं का मन मोहने के वे तमाम जतन किए, जो भाजपा कर रही थी। इसके बावजूद चुनाव परिणाम का संदेश साफ है। प्रदेशवासियों को शिव 'राज' ही पसंद है। नगरीय निकायों में कार्यकाल खत्म होने से पिछले दो वर्षों से कोई जनप्रतिनिधि नहीं था, इसलिए चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर भी नहीं था। इस परिस्थिति में भाजपा अपनी मौजूदा, जबकि कांग्रेस अपनी पिछली राज्य सरकार के कामकाज पर चुनाव लड़ रही थी। इसी वजह से इसे मिशन-2023 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा था। मतदाताओं ने शिवराज सिंह सरकार के कामकाज पर अपनी पसंद की मुहर लगाकर कांग्रेस को मायूस कर दिया। हालांकि चुनावों में कुछ जगह हार से भाजपा को सबक भी मिला है। इसको लेकर सत्ता, संगठन और संघ सब तत्पर हो गए हैं और समीक्षा के बाद रणनीति बनाकर काम करने की कवायद में लग गए हैं।

पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब शिवराज सरकार मिशन 2023 की तैयारियों में जुटेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 अगस्त के बाद विभागीय समीक्षा की शुरुआत करेंगे। इसके लिए सभी विभागों से हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी मांगी गई है। साथ ही सितंबर 2023 तक 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक राशि के शिलान्यास और लोकार्पण योग्य कामों की सूची भी मांगी गई है। समीक्षा में मंत्रियों के साथ विभागीय अधिकारी उपास्थित रहेंगे। प्रदेश में नवंबर-दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आचार संहिता प्रभावित हो सकती है। इसे देखते हुए सरकार ने अपने स्तर पर विधानसभा चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री 15 अगस्त के बाद विभागीय समीक्षा करेंगे। इसमें आत्मनिर्भर मप्र की कार्ययोजना की पूर्ति की स्थिति, हितग्राहीमूलक योजनाओं की प्रगति, लोक सेवा गारंटी कानून के अंतर्गत लाई जाने वाली सेवाओं में वृद्धि के प्रस्ताव, निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे कार्य और अधोसंरचना विकास के कामों की समीक्षा की जाएगी। विभागों से सितंबर 2023 तक 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक लागत के शिलान्यास और लोकार्पण योग्य कामों की सूची मांगी गई है ताकि कार्यक्रम तय किए जा सकें। इसके साथ ही सितंबर 2023 तक सिंगल क्लिक के माध्यम से एक बार में 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक राशि के हितग्राहियों को हितलाभ वाली योजनाओं की जानकारी मांगी गई है। सूत्रों का कहना है कि बैठक के बाद प्रतिमाह के कार्यक्रम तय होंगे। यह अलग-अलग जिलों में आयोजित होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे।

मुख्यमंत्री जल्द ही रोजगार से जुड़े कार्यक्रमों

भाजपा को घर दुरुस्त करना होगा

ऐसा पहली बार होगा, जब निकाय चुनाव के ठीक एक साल बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। निकाय चुनाव के नतीजे बताते हैं कि भले ही कांग्रेस की तुलना में भाजपा ने ज्यादा निकायों पर कब्जा किया है। बावजूद इसके भाजपा को अपने घर को दुरुस्त करना होगा। ग्वालियर और रीवा जैसी जगहों पर पार्टी के पिछड़ने का बड़ा कारण नेताओं के बीच मतभेद रहा। कटनी और रीवा में उम्मीवारों के चयन में स्थानीय कार्यकर्ताओं व नेताओं की अनदेखी कर फैसला महंगा पड़ गया। ग्वालियर में अंतिम समय तक उम्मीदवार को लेकर असमंजस की स्थिति रही। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्थानीय भाजपा नेताओं के बीच टकराव देखने को मिला। नतीजे बताते हैं कि मालवा-निमाड़ और बुंदेलखंड में भाजपा का प्रभाव बरकरार है। सागर, रतलाम, उज्जैन, देवास और उज्जैन नगर निगम के अलावा नगर परिषद और नगर पालिकाओं में भाजपा का बहुमत है। यानी अभी ये इलाके भाजपा का गढ़ बने हुए हैं। यदि 2015 के चुनाव से तुलना करें तो ऑवर ऑल भाजपा को फायदा हुआ है। पिछले चुनाव में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों में भाजपा के कुल 158 महापौर-अध्यक्ष जीते थे, जबकि कांग्रेस के खाते में 75 निकाय आए थे।

की समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के साथ शहरी और ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शासकीय विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी इसी वर्ष प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से स्वीकृत, भरे और रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। इसके आधार पर भर्ती के कार्यक्रम तय किए जाएंगे।

नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा 16 नगर निगमों में से 9 में ही अपने महापौर प्रत्याशी को जिता पाई, लेकिन ओवरऑल भाजपा 90 प्रतिशत तक चुनाव जीती है। जहां कांग्रेस के महापौर हैं वहां भी भाजपा का बहुमत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि नगरीय निकाय और नगर परिषदों में हमने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। जिस प्रकार भाजपा के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं नीचे स्तर तक पहुंची है और जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, नगरीय निकाय में भाजपा की जीत जनता के विश्वास की जीत है। प्रदेश की जनता के हम आभारी हैं। हम संकल्प व्यक्त करते हैं कि जनता के विश्वास को टूटने नहीं देंगे। सबके साथ मिलकर बेहतर से बेहतर काम करेंगे और मप्र को और आगे ले जाएंगे।

मुख्यमंत्री का कहना है कि निकाय चुनाव में भाजपा ने इतिहास रचा है। मैं वर्ष 1985 से पार्टी में काम कर रहा हूं। इतनी अच्छी सफलता पहले कभी नहीं मिली। उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया और चुनकर आए जनप्रतिनिधियों, भाजपा के पदाधिकारियों, विधायक-सांसद, कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता के कल्याण और नगरों के विकास में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

मुख्यमंत्री का कहना है कि नगर निगम के परिणाम भाजपा के लिए संतोषजनक हैं। 16 में से भाजपा के 9 महापौर जीते हैं। एक में हमारी ही कार्यकर्ता जीती हैं। जिन नगर निगमों में हमारे महापौर नहीं जीत पाए, वहां भी भाजपा के पार्षद ज्यादा हैं। कांग्रेस की जीत तो अधूरी है। नगर पालिका की बात करें तो 76 में से 65 में भाजपा अपना अध्यक्ष बनाने जा रही है और कांग्रेस ने सिर्फ 11 में सफलता पाई है। नगर परिषद में तो भाजपा ने कांग्रेस को पूरी तरह साफ कर दिया है। 255 परिषद में चुनाव हुआ है। इसमें से 185 में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला। जबकि 46 में कांग्रेस से काफी आगे हैं। यानी 231 नगर परिषद में भाजपा को सफलता मिली है। वहीं कांग्रेस 24 में जीती है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2014 में संपन्न नगरीय निकाय चुनाव से तुलना करते हुए बताया कि इस बार हमें 30 से 32 प्रतिशत अधिक सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि 2014 में 98 नगर पालिकाओं में चुनाव हुआ था। इसमें से 54 में भाजपा जीती थी, जो 55 प्रतिशत होता है। इस बार जीत का प्रतिशत 85 हो गया है। ऐसे ही 264 नगर परिषद के चुनाव में से भाजपा को 154 में सफलता मिली थी, जो 58.3 प्रतिशत होता है और इस बार 90 प्रतिशत में सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि रायसेन, राजगढ़, सागर, जबलपुर, सिवनी, देवास, सीहोर, नरसिंहपुर, रीवा, मुरैना जिलों की नगर परिषदों और विदिशा, सीहोर, सागर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर जिलों की नगर पालिकाओं में भाजपा का प्रदर्शन शत-प्रतिशत रहा है।

● **कुमार राजेन्द्र**

भाजपा की जीत का विवरण

- 16 नगर निगम में से 9 पर विजयी।
- कांग्रेस 5 नगर निगमों में महापौर भले ही जीती हो लेकिन पार्षद भाजपा के ज्यादा जीते हैं। रीवा में 18 पार्षद भाजपा और 16 कांग्रेस, 11 अन्य। मुरैना में नगर निगम परिषद में बहुमत न भाजपा का है, न कांग्रेस का है। 14 भाजपा, 19 कांग्रेस एवं 14 सपा, बसपा, अन्य।
- ग्वालियर में 66 में से 36 भाजपा और कांग्रेस के केवल 19 पार्षद जीते हैं।
- जबलपुर में 79 में से 39 भाजपा और कांग्रेस के केवल 30 पार्षद जीते हैं।
- सिंगरौली में 45 में से 23 भाजपा और कांग्रेस के केवल 13 पार्षद हैं।
- कटनी नगर निगम के 45 वार्डों में से भाजपा के 27 व कांग्रेस, 15 व 3 अन्य पार्षद जीते हैं।
- 76 नगर पालिका में 50 में भाजपा को स्पष्ट बहुमत, 15 में स्थिति अच्छी है। (कुल 65), कांग्रेस 76 नगर पालिका में से कुल 11 सीट जीत पाई है।
- 255 नगर परिषद में से 185 में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है, 46 में स्थिति अच्छी है। कुल (231), कांग्रेस को 24 में जीत मिली है।
- वर्ष 2014 में 98 नगर पालिकाओं के चुनाव में भाजपा 54 सीटों पर विजयी हुई थी, कुल 55 प्रतिशत, इस वर्ष 76 नगर पालिकाओं के चुनाव में भाजपा 65 सीटों पर अपना अध्यक्ष बनाने जा रही है, जीत का प्रतिशत 85 प्रतिशत रहा है।
- वर्ष 2014 में 264 नगर परिषद के चुनाव में भाजपा 154 सीटों पर विजयी हुई थी। कुल 58 प्रतिशत, इस वर्ष 255 नगर परिषद के चुनाव में भाजपा 231 सीटों पर अपना अध्यक्ष बनाने जा रही है। जीत का प्रतिशत 90.58 प्रतिशत रहा है।
- कटनी, रायसेन, राजगढ, सागर, जबलपुर, सिवनी, देवास, सीहोर, नरसिंहपुर, रीवा, मुरैना इन जिलों की नगर परिषदों में भाजपा का प्रदर्शन लगभग शत-प्रतिशत रहा है।
- विदिशा, छिंदवाडा, सीहोर, सागर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर इन 5 जिलों की नगर पालिकाओं में भाजपा शत-प्रतिशत जीती है।
- छिंदवाडा जिले की तीनों नगर पालिकाओं (अमरवाड़ा, चौरई और परासिया) में भाजपा जीती है।
- जबलपुर में 8 में से 6 नगर परिषद में भाजपा विजयी हुई है।
- मुरैना में 5 में से 4 नगर परिषद में भाजपा विजयी हुई है।
- रीवा में 12 में से 11 नगर परिषद में भाजपा विजयी हुई है।
- ग्वालियर में सभी 5 नगर परिषदों में कांग्रेस की अपेक्षा भाजपा का प्रदर्शन बेहतर है।
- कटनी में 3 नगर परिषद में से 3 में भाजपा विजयी हुई है।
- 16 नगर निगम के 884 वार्डों में से 491 वार्डो में भाजपा विजयी रही। सिर्फ 274 स्थानों पर कांग्रेस और अन्य पर 109 पार्षद विजयी रहे।
- 76 नगर पालिकाओं के 1795 वार्डों में से 975 वार्डों में भाजपा विजयी रही। 571 स्थानों पर कांग्रेस और 249 पर अन्य पार्षद विजयी रहे।
- 255 नगर परिषदों के 3828 वार्डों में 2002 वार्डों में भाजपा विजयी रही। 1087 स्थानों पर कांग्रेस और 739 पर अन्य पार्षद विजयी रहे।

इंदौर को 2300 करोड़ की सौगात

इंदौर और आसपास के क्षेत्र अब विकास के पथ पर तेजी से दौड़ेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 1 अगस्त को इंदौर में 2300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए भूमिपूजन करेंगे। इंदौर को आसपास के क्षेत्रों से जोड़ने वाले विभिन्न मार्गों और फ्लाईओवर की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। अब यह सभी आकार लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के तहत इन सभी विकास कार्यों का शुभारंभ कुछ माह पहले होना था, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने से यह आयोजन टल गया था। जिन विकास कार्यों का शुभारंभ होगा, उनमें इंदौर और खंडवा के बीच फोरलेन सड़क का काम प्रमुख है। खंडवा रोड की हालत खराब होने से यहां से गुजरने वाले वाहन चालक परेशान होते हैं। तेजाजी नगर से बलवाड़ा के बीच भी सड़क की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहां मौजूद सड़क की मरम्मत भी होना है, वहीं नई सड़क भी बनेगी। इसके बाद यह मार्ग भी वाहन चालकों के लिए सुगम होगा।

इंदौर-बैतूल मार्ग पर इंदौर से हरदा के बीच बेहतर सड़क की लंबे समय से मांग हो रही है। प्रस्तावित योजना में इस मार्ग को फोरलेन बनाया जाना है। यह सड़क 1,011.29 करोड़ रुपए में बनना है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इंदौर को **बेहतर कनेक्टीविटी** देने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कई सड़कों और अन्य विकास योजनाओं की मांग की थी, जिन्हें उन्होंने स्वीकार किया है। इंदौर को मिलने वाली करीब 2,300 करोड़ की सौगातों से आवाजाही सुधरेगी, लोगों को जाम और हादसों से मुक्ति मिलेगी। इससे इंदौर तथा आसपास के क्षेत्रों का तेज गति से विकास होगा। शहर में विकास की कुछ योजनाओं पर काम हो रहा है। इनमें पश्चिमी रिंग रोड, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी योजनाएं प्रमुख हैं। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनीष असाटी के अनुसार पश्चिमी रिंग रोड की डीपीआर तैयार की जा रही है। यह महत्वाकांक्षी योजना है और पिछली बार जब केंद्रीय मंत्री गडकरी इंदौर आए थे तो हमने इस बारे में उन्हें जानकारी दी थी।

उधर शासन की मंजूरी के बाद मप्र इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने 3200 एकड़ की प्रस्तावित इंदौर-पीथमपुर कॉरिडोर योजना का प्रारूप घोषित कर दिया है। 30 दिन में किसानों-जमीन मालिकों के दावे-आपत्ति-सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। 1400 करोड़ की राशि इस कॉरिडोर को विकसित करने में खर्च की जाएगी। 19.60 किलोमीटर लंबे इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में दोनों तरफ 300-300 मीटर की निजी जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। इस कॉरिडोर के बनने से इंदौर एयरपोर्ट से पीथमपुर मात्र 15 मिनट में पहुंचा जा सकेगा, तो आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे के साथ इंदौर-अहमदाबाद भी जुड़ जाएगा। इसमें 500 करोड़ रुपए की राशि भू-अर्जन के लिए रखी गई है। डाटा सेंटर, आईटी, होटल सहित आवासीय व अन्य गतिविधियां इस पूरे कॉरिडोर पर भविष्य में आएंगी।

पिछले दिनों शिवराज कैबिनेट ने रतलाम के साथ-साथ इंदौर-पीथमपुर इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी थी, जिसके चलते एमपीएसआईडीसी ने प्रारूप का प्रकाशन करने की सूचना जाहिर की है।

1290.74 हेक्टेयर यानी लगभग 3200 एकड़ जमीन इस 19.60 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में अधिग्रहित की जाना है, जिसमें नैनोद, कोडियार्वर्डी, नावदापंथ, सिंहासा, सिंदौड़ी, शिवखेड़ा, डेहरी, सोनवाय से लेकर दूसरी तरफ रीजलाया, बिसनावदा, श्रीराम तलावली, सिंदौड़ा, बगोदा, भैंसलाय, धन्नड़ और टीही सहित अन्य गांवों की जमीनें आ रही हैं। इंदौर के साथ-साथ महू के भी कुछ गांव इस कॉरिडोर की प्लानिंग में शामिल किए गए हैं। एमपीएसआईडीसी के एमडी रोहन सक्सेना के मुताबिक इस कॉरिडोर पर होटल, आईटी, फिन्टैक सिटी, डाटा सेंटर, लॉजिस्टिक पार्क, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ट्रेनिंग सेंटर, इंटरटेनमेंट पार्क, रेडिमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स, फिल्म इंडस्ट्रीज, मल्टीमीडिया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के साथ-साथ भविष्य में मेट्रो लाइन और अन्य टर्मिनल की भी सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसमें औद्योगिक बड़े आकार के भूखंडों के साथ-साथ 20 हजार से अधिक आवासीय भूखंड भी रहेंगे और 15 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आएगा और 25 हजार लोगों को रोजगार हासिल होगा। शासन की मंजूरी के बाद एमपीएसआईडीसी ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए योजना घोषित कर प्रारूप प्रकाशन कर दिया है, ताकि 30 दिनों में जमीन मालिकों के दावे-आपत्तियों और सुझावों को लिया जा सके। शासन ने इसके लिए जो फॉर्मूला तय किया है उसमें 20 फीसदी राशि किसानों या अन्य जमीन मालिकों को नकद दी जाएगी। वहीं शेष 80 प्रतिशत जमीन के बदले विकसित भूखंड मिलेंगे। जिस तरह प्राधिकरण ने भी अपनी योजनाओं में शामिल जमीन मालिकों को 20 से 30 फीसदी तक विकसित भूखंड दिए हैं। उसी तरह इकोनॉमिक कॉरिडोर में 20 फीसदी नकद राशि के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

● **राकेश ग्रोवर**

इंदौर-नागपुर हाईवे के आसपास की बदलेगी भौगोलिक तस्वीर

मप्र औद्योगिक विकास निगम इंदौर ने चापड़ा गांव के पास बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एक दर्जन से ज्यादा गांवों की जमीनें चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। राज्य शासन के बहुचर्चित इंटनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के चलते शहर से लगभग 46 किलोमीटर दूर इंदौर-नागपुर हाईवे के आसपास के गांवों की दशा बदलने की शुरुआत हो गई है। चापड़ा में 2100 हेक्टेयर जमीन पर बनने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जमीनें जुटाने व अधिग्रहण करने का काम मप्र औद्योगिक विकास निगम इंदौर को दिया गया है। इसके लिए चापड़ा के आसपास के 12 गांवों की जमीनें चिन्हित की जा रही हैं। ग्रामीणों की जमीनें अधिगृहित करने के लिए शासन की गाइडलाइन के हिसाब से लगभग 800 करोड़ रुपए बंटेंगे।

अब मिशन 2023 की रणनीति

विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के जो परिणाम हैं वे भाजपा और कांग्रेस के लिए रणनीति बनाने का आधार बनेंगे। इन चुनावों के नतीजे विधानसभा चुनाव का आईना हैं। अत: पार्टियां इसी के आधार पर मिशन 2023 के फतह की रणनीति बना रही हैं। दरअसल, निकाय चुनाव ने पार्टियों को यह आईना दिखा दिया है कि उनकी रणनीति में क्या-क्या खामियां हैं। उनके संगठन में कहां-कहां खामियां हैं। पार्टियां इस सब पर मंथन-चिंतन कर रणनीति बनाएंगी।

गौरतलब है कि सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों से भाजपा और कांग्रेस दोनों खुश हैं और अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बड़े शहरों में हल्का झटका खाने के बाद छोटे शहरों में अपनी सफलता पर भाजपा खुशी मना रही है तो कुछ बड़े शहरों में 23 साल बाद वापसी से कांग्रेस में जश्न है। हालांकि अंदरखाने में दोनों दल चुनाव परिणामों को सबक मान रहे हैं और इसी के आधार पर विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं। नगरीय सरकार के ये नतीजे विधानसभा चुनाव में आईने का काम करेंगे। वहीं आप की एंट्री ने भी भाजपा को नई रणनीति पर काम करने को विवश कर दिया है। विधानसभा चुनाव में अभी सवा साल का समय है। निश्चित रूप से भाजपा का संगठनात्मक नेटवर्क बेहद मजबूत है पर उसे अतिआत्मविश्वास से बाहर आकर धरातल पर रणनीति तैयार करनी होगी। इस रणनीति में आप से कैसे निपटा जाए इस पर भी विचार करना होगा। कहना न होगा कि चुनाव के समय टिकट न मिलने से नेताओं में बगावत स्वभाविक रूप से होती है, इस बगावत का फायदा इस बार की तरह विधानसभा चुनाव में भी आप ही उठाएगी।

नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम दर्शाते हैं कि बड़े शहरों में उसका जनाधार कम हुआ है। पार्टी के रणनीतिकार उसे अपने लिए अलार्मिंग मान रहे हैं। पिछली बार सभी 16 नगर निगमों में क्लीन स्वीप करने वाली भाजपा इस बार महज 9 नगर निगमों तक सिमट गई है। पार्टी नगर पालिका और नगर परिषदों में अपने ज्यादा पार्षद आने से खुश हैं और उसका दावा है कि 90 फीसदी स्थानों पर उसने सफलता के झंडे गाड़े हैं। यह दावा उसका सच भी हो सकता है पर बड़े शहर जिस तरह उसके हाथ से गए हैं, उसने उसके नेताओं की पेशानी पर बल ला दिए हैं। बुरहानपुर में उसे बेहद कम अंतर से जीत मिली है। इस जीत में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का भी हिस्सा है। अगर ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी को 10 हजार के आसपास वोट नहीं मिलते तो भाजपा को नुकसान तय था। वहीं सतना में उसे बसपा के प्रत्याशी सईद अहमद का शुक्रगुजार होना चाहिए। वे 25 हजार से अधिक वोट ले गए जिसने भाजपा की जीत आसान कर दी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक सफलता मिली है। नगर पालिका और नगर परिषद में पार्टी ने सबसे ज्यादा सफलता हासिल की है। कई जगह तो 15 में से 14 पार्षद भाजपा के जीते हैं। इन चुनावों में पार्टी चार कदम आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में हम 51 प्रतिशत वोट बैंक से आगे बढ़े हैं। नगरीय निकाय चुनाव में मिला यह जनादेश यह दर्शाता है कि जनता का अपार विश्वास भाजपा को मिला है। उन्होंने कहा कि जहां हम कमजोर रह गए हैं उस पर गंभीरता से मंथन करेंगे। पार्टी के त्रिदेव और बूथ कार्यकर्ताओं के बल पर हम 95 प्रतिशत से चुनाव जीते हैं। हम विकास के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे।

विधानसभा चुनाव के पहले आए नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे कांग्रेस को संजीवनी दे गए हैं। 5 शहरों में उसके मेयर बन गए हैं तो उज्जैन और बुरहानपुर में वह कांटे की लड़ाई में हारी है। जाहिर है विधानसभा चुनाव के समय माहौल और बदलेगा। सरकार के प्रति स्वाभाविक एंटीइनकमबेंसी का जो फायदा उसे नगरीय निकाय चुनाव में मिला है, वह विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है पर छोटे शहरों में जिस तरह उसकी पकड़ कमजोर हुई है वह उसके लिए चिंता का विषय है। उसे अपने संगठन को फिर से गढ़ना होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि पिछले चुनाव में नगर निगम में खाली हाथ रही कांग्रेस ने इस बार 5 नगर निगम जीते और दो जगह पार्टी बेहद कम अंतर से हारी। उज्जैन और बुरहानपुर में जनता ने कांग्रेस को जिता दिया था, लेकिन षड्यंत्र की राजनीति और प्रशासन के दुरूपयोग से यह सीटें कांग्रेस के खाते में नहीं आ सकीं। महाकौशल, ग्वालियर-चंबल और विंध्य में पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है।

● श्याम सिंह सिकरवार

कार्यकर्ताओं की राय को दरकिनार करना पड़ा भारी

जबलपुर, मुरैना, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, रीवा में पार्टी ने कार्यकर्ताओं की राय को दरकिनार कर ऐसे लोगों को टिकट दिया, जो कार्यकर्ताओं में सर्वस्वीकार्य नहीं थे। जबलपुर में डॉ. जितेंद्र जामदार ऐसे चेहरे थे जो भाजपा में कभी ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। वे संघ में सक्रिय थे पर कार्यकर्ताओं से उनका कभी सीधा सरोकार नहीं रहा। इसी तरह मुरैना में जिन मीना जाटव को टिकट दिया गया वे खुद कभी राजनीति में खासी सक्रिय नहीं रहीं, उनके पति जरूर राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ से जुड़े थे। इसी तरह छिंदवाड़ा में नगर निगम के जिस अधिकारी अनंत धुर्वे को टिकट दिया गया वे कभी भाजपा की सक्रिय राजनीति में नहीं थे। उन्हें सरकारी सेवा से इस्तीफा दिलवाकर चुनाव मैदान में उतारा गया। ग्वालियर में सुमन शर्मा का स्थानीय भाजपा में कोई आधार पहले से ही नहीं था। इसी तरह रीवा के प्रत्याशी प्रबोध व्यास का भी कभी जनता से सीधा वास्ता नहीं रहा। जाहिर सी बात है पार्टी कार्यकर्ताओं ने संगठन के इस निर्णय को नहीं स्वीकारा और जिस तत्परता के लिए संगठन जाना जाता है वह तत्परता कार्यकर्ताओं में नहीं दिखी। कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि वे बंधुआ नहीं हैं। प्रत्याशी थोपे जाने की इस परम्परा का खुले रूप से न सही पर भाजपा के अंदरखाने में जमकर विरोध हुआ और नतीजे में ऐसी जगहों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जहां वे दो दशक से अधिक समय से काबिज थी। ग्वालियर में तो 57 साल बाद कांग्रेस का मेयर बना है, वह भी तब जब 2 केंद्रीय मंत्री और प्रदेश सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री इस अंचल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

दिग्गजों के गढ़ में ही कांग्रेस धड़ाम

सत्ता के सेमीफाइनल यानी नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की मिशन 2023 की तैयारियों की पोल खुल गई है। पार्टी के दिग्गज नेता अपने ही क्षेत्र में पार्षदों को जिता नहीं पाए।

कांग्रेस के जो दिग्गज नेता 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का दम भर रहे हैं, उन्हीं दिग्गजों के क्षेत्र में पार्टी सत्ता के सेमीफाइनल में धड़ाम हो गई। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर किस बूते कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। यह स्थिति तब है जब दिग्गज नेताओं और जिलाध्यक्षों ने नगरीय निकाय चुनाव में अपनी पसंद का प्रत्याशी खड़ा करवाया था। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में होना है। इससे पहले हुए नगरीय निकाय चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी अपने क्षेत्र के निकाय नहीं बचा पाए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, बाला बच्चन, जीतू पटवारी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और उपाध्यक्ष हिना कांवरे के क्षेत्र में भाजपा का वर्चस्व रहा। जबलपुर में पूर्व मंत्री तरुण भनोत व लखन घनघोरिया के विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों ने जीत प्राप्त की। भोपाल, विदिशा, सागर, सिंगरौली आदि जिलों में भी कांग्रेस हार गई, यहां जिलाध्यक्षों ने अपनी पसंद से टिकट दिलाए थे। दिग्गजों के क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों की हार ने पार्टी को पसोपेश में डाल दिया है।

नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने भले ही 5 नगर निगमों में अपने महापौर जिता लिए हैं, लेकिन लगभग सारी निकायों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। दिग्गज नेता पार्षदों को जिता नहीं पाए। ऐसे में निकायों के परिणाम सामने आने के बाद अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ विधानसभावार रिपोर्ट तैयार करा रहे हैं, जिसकी समीक्षा के आधार पर कई जिलाध्यक्षों पर गाज गिरना तय है। नगरीय निकाय चुनाव के पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने विधायक दल की बैठक में साफ कर दिया था कि इन चुनावों को आगामी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाए। जो विधायक या नेता टिकट दिला रहे हैं, वे उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी भी लें। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष व संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर का कहना है कि निकाय चुनाव के परिणामों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पूर्व मंत्रियों और विधायकों के क्षेत्र में ही पार्टी को हार मिली है। कमलनाथ के कोर ग्रुप के सदस्य व पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के निर्वाचन क्षेत्र सोनकच्छ की नगर परिषद में 5 पार्षद ही कांग्रेस के जीते। यहां 6 निर्दलीय और 4 भाजपा के पार्षद चुने गए। देवास नगर निगम में पार्टी प्रत्याशी को उतने भी मत प्राप्त नहीं हुए, जितने अंतर से भाजपा ने जीत प्राप्त की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के क्षेत्र गोटेगांव में 12 पार्षद भाजपा, 2 कांग्रेस और 1 निर्दलीय चुना गया है। विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे के क्षेत्र लांजी में भाजपा के 7, कांग्रेस के 4, निर्दलीय 3 और 1 पार्षद आप पार्टी का जीता है। पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन के विधानसभा क्षेत्र राजपुर में आने वाली ठीकरी नगर परिषद में भाजपा के 8 और कांग्रेस के 5 पार्षद जीते हैं। खरगोन में विधायक और पार्टी के प्रदेश महामंत्री रवि जोशी के निर्वाचन क्षेत्र खरगोन में भाजपा के 16 पार्षद जीते हैं। यहां कांग्रेस के 4 पार्षद निर्वाचित हुए हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के निर्वाचन क्षेत्र राऊ की नगर परिषद में भाजपा के 12 और कांग्रेस के 3 पार्षद जीते हैं। पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह के चुनाव क्षेत्र खिलचीपुर में भाजपा के 8 और कांग्रेस के 6 पार्षद जीते हैं। पूर्व मंत्री हर्ष यादव के निर्वाचन क्षेत्र देवरी में 11 स्थानों पर भाजपा के पार्षद चुनाव जीते हैं। तेंदूखेड़ा विधायक संजय शर्मा, गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल, देपालपुर विधायक विशाल पटेल भी अपने क्षेत्र में कांग्रेस को बहुमत नहीं दिला सके।

● **अरविंद नारद**

जिलाध्यक्ष भी निकले कमजोर

नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों ने जीत की गारंटी के आधार पर पार्षद का टिकट दिलवाया था, लेकिन वे उन्हें जिता नहीं पाए। विदिशा के जिला कांग्रेस अध्यक्ष निशंक जैन के गृह नगर गंजबासौदा में भाजपा 16, कांग्रेस 7 वार्ड ही जीत पाई। एक निर्दलीय ने चुनाव जीता। यहां पूरे टिकट निशंक जैन की पसंद के थे। जिले की अन्य पालिकाओं व परिषदों में भी कांग्रेस बुरी तरह हार गई। भोपाल में कांग्रेस महापौर का चुनाव हारने के साथ ही वार्ड का चुनाव भी बुरी तरह से हारी है। भोपाल में भाजपा 58, कांग्रेस 22 और 5 निर्दलियों ने चुनाव जीता। शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा पर आरोप है कि वे अपनी बहू को वार्ड का चुनाव जितवाने में लगे रहे। उन्होंने टिकट वितरण के बाद अन्य वार्डों पर ध्यान नहीं दिया। सागर शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष रेखा चौधरी व ग्रामीण जिला अध्यक्ष स्वदेश जैन भी चुनाव में फ्लॉप साबित हुए। सागर में भाजपा के 40, कांग्रेस के 7 और 1 निर्दलीय ने पार्षद का चुनाव जीता। जिले की अन्य नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस के रायसेन जिलाध्यक्ष व विधायक देवेंद्र पटेल अपने विधानसभा क्षेत्र उदयपुरा नगर पालिका में ही कांग्रेस को नहीं जिता पाए। जिले की अन्य नगर पालिका व नगर परिषदों पर भी भाजपा का कब्जा हो गया। सत्ता के सेमीफाइनल में दिग्गजों के गढ़ में मिली हार ने कांग्रेस के रणनीतिकारों की चिंता बढ़ा दी है।

बुरहानपुर बना प्रेरणा

जल जीवन मिशन के तहत मप्र के बुरहानपुर ने अपना झंडा गाड़ दिया है। बुरहानपुर देश का एकमात्र जिला है, जहां 100 फीसदी घरों में नल से जल पहुंच रहा है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत देश के 110 जिलों में प्राथमिकता के तौर पर नल से जल पहुंचाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन इनमें से मात्र बुरहानपुर ने ही लक्ष्य को हासिल किया है। और आज देश के लिए प्रेरणास्रोत बना हुआ है।

बुरहानपुर जिले के लोगों ने पेयजल के लिए हैंडपंप और कुएं जैसे पारंपरिक जलस्रोतों का इस्तेमाल लगभग बंद कर इन्हें अलविदा कह दिया है। अब जिले के प्रत्येक घर में नलों के माध्यम से पेयजल की सप्लाई हो रही है। यह सब केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन से संभव हुआ है। हालांकि योजना के तहत घरों तक पेयजल पहुंचाने के लिए तय की गई मार्च 2021 की समय सीमा के अंदर न सिर्फ बुरहानपुर बल्कि मप्र पिछड़ गया है, लेकिन सबसे पहले लक्ष्य हासिल करने वाला बुरहानपुर पहला जिला बन गया है। जिले की करीब साढ़े 8 लाख की आबादी अब नलों के माध्यम से शुद्ध पानी पी रही है। योजना का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी लोक स्वास्थ्य एवं यात्रिकी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि योजना का 80 फीसदी काम पूरा कर लिया गया है। शेष बचा 20 फीसदी काम भी माह के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। जहां टंकियों का निर्माण अधूरा है उन गांवों में सीधे सप्लाई शुरू कर दी गई है।

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक जिले में 200 से ज्यादा गांव हैं। इनमें से करीब 60 फीसदी में पहले से 156 नल-जल योजनाएं संचालित थीं। इन्हें विस्तारित कर छूटे फाल्याओं तक पानी पहुंचाया गया है। शेष 40 फीसदी गांवों में 58 नई नल-जल योजनाएं स्थापित की गई हैं। इनमें 53 टंकियों का निर्माण किया जा चुका है। 20 टंकियों का निर्माण कार्य जारी है। योजना के तहत करीब 42 हजार घरों में नल कनेक्शन देकर पेयजल पहुंचाया गया है। कुछ दिन पहले ही सामने आए आंकड़ों में नल-जल योजना के तहत बुरहानपुर जिला पूरे देश में नंबर वन बना था। बुरहानपुर में 254 गांवों में नल-जल योजना के तहत पानी पहुंचाया गया है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने बुरहानपुर जिले को बधाई दी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बुरहानपुर को बधाई दी थी। नल-जल योजना के तहत बुरहानपुर में साल 2019 में काम शुरू हुआ था। उसी राह पर अब प्रदेश के कई और जिलों में काम शुरू हुआ है।

नल-जल योजनाओं का 3 माह तक ठेकेदार ट्रायल के तौर पर संचालन करेगा। इसके बाद की जिम्मेदारी हर पंचायत में बनी ग्राम जल स्वच्छता समिति को सौंप दिया जाएगा। इन समितियों द्वारा ही नागरिकों से बिल वसूली, बिजली बिल का भुगतान और मेंटेनेंस आदि किया जाएगा। शासन स्तर पर प्रत्येक नल कनेक्शन पर न्यूनतम 60 रुपए मासिक शुल्क तय किया गया है। इन समितियों के सदस्यों को एनजीओ के माध्यम से संचालन, संधारण संबंधी प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है।

नल जल योजना में बुरहानपुर पूरे देश में अव्वल आया है। इसके बाद अब कई और शहरों को भी इसी सूची में शामिल करने की कवायद की जा रही है। प्रदेश में हर घर जल योजना में तेजी के मकसद से जल जीवन मिशन के तहत 46 करोड़ 45 लाख से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है। ये राशि 6 जिलों के लिए है। इनमें धार, खरगोन, झाबुआ, बैतूल, नरसिंहपुर, कटनी जिले के ग्रामीण इलाके शामिल हैं। पीएचई विभाग की ओर से जारी की गई इस राशि से ग्रामीण परिवारों को पानी सप्लाई करने के लिए नल कनेक्शन लगाए जाएंगे। मौजूदा वक्त में मप्र के 5,400 गांव ऐसे हैं जहां शत-प्रतिशत परिवारों को नल कनेक्शन से पानी की सप्लाई की जा चुकी है। 35 हजार से अधिक गांव की जल-प्रदाय योजनाओं के काम चल रहे हैं। पूरे प्रदेश की ग्रामीण आबादी के लिए 1 करोड़ 22 लाख परिवारों को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने के लक्ष्य में से अब तक 51 लाख 28 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को हर घर जल योजना के तहत पानी की सप्लाई की जा रही है।

देश के ज्यादातर हिस्सों में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। इससे निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार हर घर जल योजना पर काम कर रही है। इसके तहत अब मप्र का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। दरअसल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि मप्र का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल (हर घर में पानी का कनेक्शन) प्रमाणित जिला बन गया है। इसे रिट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मप्र के बुरहानपुर जिले के लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और यह लोगों के बीच सामूहिक भावना को पैदा करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बुरहानपुर की मेरी बहनों और भाइयों को बधाई। यह लोगों के बीच सामूहिक भावना और जल जीवन मिशन टीम और मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मिशन मोड प्रयासों के बिना संभव नहीं हो सकता था। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर बताया कि अगस्त 2019 में सिर्फ 37 प्रतिशत घरों में पानी की सुविधा थी, हर घर जल योजना पर जल जीवन मिशन टीम के किए गए कामों के कारण तीन साल से भी कम समय में इसे 100 प्रतिशत तक पहुंचा दिया गया है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

मप्र की सिर्फ 42 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को ही पहुंच पाया लाभ

प्रदेश का बुरहानपुर जिला हर घर नल से जल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला जिला भले ही बन गया है, लेकिन प्रदेश के बाकी हिस्से में 58 फीसदी ग्रामीण आबादी अभी स्वच्छ पेयजल से महरूम हैं। वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से अब तक सिर्फ 42 फीसदी ग्रामीण आबादी को ही हर घर नल से स्वच्छ पेयजल नसीब हो सका है। सबसे बदहाल स्थिति पन्ना और सतना जिलों की है, जहां सिर्फ 16 और 19 फीसदी आबादी को ही नल से जल उपलब्ध हो पा रहा है। स्वच्छ पेयजल की सर्वाधिक कमी से जूझने वाले जिलों में छतरपुर, सिंगरौली, अलीराजपुर, भिंड और टीकमगढ़ जिले भी शामिल हैं, जहां सिर्फ 20 से 30 फीसदी आबादी ही जलजीवन मिशन में कवर हो सकी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सार्वजनिक किए गए हर घर नल से जल्द योजना के आंकड़ों के मुताबिक मप्र में कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या 1 करोड़ 22 लाख 9 हजार 394 है। जिसमें से जुलाई 2022 तक 51 लाख 13 हजार 461 परिवारों को नल जल कनेक्शन दिए गए हैं। जबकि 70 लाख 95 हजार 933 परिवारों के घर तक पानी अभी नहीं पहुंच सका है।

अब यूथ पर फोकस

प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां शुरु कर दी हैं। प्रदेश के सबसे बड़े मतदाता वर्ग यानी युवाओं को साधने के लिए भाजपा मिशन मोड में आ गई है। भाजपा की देखादेखी कांग्रेस भी युवाओं को साधने में जुट गई है। अब देखना यह है कि युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पार्टियां कौन-कौन सा प्रहसन करती हैं। प्रदेश का युवा वर्ग जिस ओर झुकेगा, अगले चुनाव में उस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा।

मिशन-2023 के लिए लगभग सभी वर्गों को साधने के बाद भाजपा का फोकस अब यूथ पर है। इसलिए प्रदेश सरकार ने युवाओं को साधने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार की नीति के अनुसार मप्र में अब युवाओं के सुझाव लेकर सरकारी योजनाओं को संचालित किया जाएगा। वहीं चंद्रशेखर आजाद की 116 वीं जन्म जयंती पर युवा महापंचायत का आयोजन कर सरकार ने संकेत दे दिया कि उसका पूरा फोकस युवाओं पर है। पंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को साधने के लिए घोषणा की कि मप्र में राज्य युवा परिषद का गठन किया जाएगा। इसमें एनएसएस, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, जन अभियान परिषद, स्काउट गाइड के युवाओं को जोड़ा जाएगा। आपके सुझाव और भागीदारी से मप्र की नई युवा नीति तैयार की जाएगी। उसकी टाइमलाइन भी मैं तय कर रहा हूं। 12 जनवरी को युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। सभी सरकारी विभागों और सरकारी कॉलेजों में हम युवा सेल का भी गठन करेंगे। जो यूथ पॉलिसी के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि आजादी में हमारे जिन वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उनके बजाय स्वतंत्रता के बाद हमें पढ़ाया गया कि आजादी केवल एक परिवार ने दिलाई। शहीद-ए-आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, भीमा नायक, टंट्या मामा जैसे वीर योद्धाओं के बारे में नहीं बताया गया। अब हमारी युवा पीढ़ी को आजादी के नायकों के जीवनगाथा से परिचित कराने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश का युवा पुरस्कार भी अलग-अलग क्षेत्रों में खेल के क्षेत्र में तो कई पुरस्कार हैं ही लेकिन विशिष्ट उपलब्धि के लिए प्रदेश में युवा पुरस्कार की स्थापना करेंगे, जो क्रिएटिव युवाओं को या संस्था को दिया जाएगा। उसका भी प्रारूप हम लोग तैयार करेंगे। यह युवा पंचायत अब हर साल में 2-3 दिन की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा- मैंने यह तय किया है कि भोपाल में एक उचित स्थान तय करके चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा लगाई जाएगी। पवित्र माटी को अभी हम शौर्य स्मारक में आजाद प्रेरणा स्थल पर स्थापित करेंगे, लेकिन जब प्रतिमा बनेगी तो उसका आधार बनाने इस माटी का उपयोग किया जाएगा। मप्र जहां था वहां से काफी आगे बढ़ा है लेकिन और आगे बढ़ना है। ये महापंचायत केवल कर्मकाण्ड नहीं है, मैं इसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं जिससे जुड़कर युवा मप्र के नवनिर्माण में सहयोग करें।

युवाओं को साधने के लिए सरकार विकास योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर भी फोकस कर रही है। मप्र में 17 साल के शासनकाल में विकास के कीर्तिमान स्थापित करने के

अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जाएंगे युवा

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने यह तय किया है जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, वो तीर्थ करने जाएं। लेकिन जो नौजवान हैं उनमें देशभक्ति की भावना का संचार करने के लिए हमने तय किया है कि वो सीमा पर जाएंगे, ताकि उन्हें पता चल सके कि किन परिस्थितियों में रहकर हमारे जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। लेह लद्दाख में -14 डिग्री तापमान में कैसे हमारे जवान खड़े रहकर भारत माता की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। इसलिए मां तुझे प्रणाम योजना को हमने शुरू किया है। यूथ पंचायत के माध्यम से जिला स्तर पर जो सभी विजेता हैं, उन विजेताओं को मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मरने की नहीं देश के लिए कुछ करने की जरूरत है और हमारे प्रदेश के युवा कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखते हैं।

बाद शिवराज सिंह चौहान की विकास की ललक कम नहीं हुई है। उनकी कोशिश है कि प्रदेश में राजधानी से लेकर दूर-दराज के गांवों तक एक समान विकास हो। इसलिए उन्होंने चौथी पारी में मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अपना सबसे अधिक फोकस विकास कार्यों पर किया। इसी का परिणाम है कि कोरोना महामारी के संकट के बाद भी प्रदेश अर्थव्यवस्था की पटरी से नीचे नहीं उतरा। अब कोरोना का संक्रमण लगभग समाप्त हो गया है। ऐसे में शासन और प्रशासन के पास विकास के लिए पर्याप्त समय है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव समाप्त होते ही पूरा फोकस विकास पर केंद्रित कर दिया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी चौथी पारी में सजग और सतर्क नजर आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने मिशन 2023 को देखते हुए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने अपने मंत्रियों को जनता की कसौटी पर कसने की तैयारी कर दी है। उन्होंने मंत्रियों से साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि अब बैठने से काम नहीं चलेगा। सरकार अब हर माह मंत्रियों के कार्यों का आंकलन करेगी। मुख्यमंत्री मप्र में सुशासन के सहारे 2023 का विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। इसके लिए प्रशासन के साथ ही शासन को भी चुस्त और दुरूस्त होना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने मंत्रियों को अधिक से अधिक समय जनता के बीच रहने और अपने विभागों के माध्यम से विकास कार्य कराने का निर्देश दिया है। मंत्री उनके निर्देश का पूरी तन्मयता से पालन करें इसके लिए उन्होंने रेटिंग प्रणाली की व्यवस्था की है।

कोरोना वायरस की महामारी के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह अडिग होकर फैसले लिए उसका असर यह हुआ है कि प्रदेश में तेजी से औद्योगिक विकास हुआ है और मप्र की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। दरअसल, महामारी के बीच भी मुख्यमंत्री ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह का वातावरण उपलब्ध कराया है उससे हमें एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में उद्योगों के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस

बढ़ रहा है। कोरोना वायरस की घातक दो लहर के बावजूद प्रदेश के उद्योग जगत ने आत्मनिर्भर मप्र अभियान को बल दिया। रॉ मटेरियल की आसमान छूती कीमतें, वर्किंग कैपिटल की कमी, स्कील्ड मैन पॉवर का अभाव और मांग की कमी ने उद्योग जगत को जरूर कुछ परेशान किया, लेकिन क्लस्टर्स के बूस्टर डोज ने 2022 के लिए आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। शासकीय के साथ निजी औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला ने भी सुनहरे भविष्य की तरफ इशारा किया है। आजादी से अब तक मप्र ने बदहाल अर्थव्यवस्था से लेकर विकास की नई ऊंचाईयां तक देखी हैं। लंबे समय से प्रदेश का औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन कोरोनाकाल के पहले झटके ने इसे हिला दिया। बावजूद इसके शुरूआती तौर पर भले ही उद्योगों को लॉकडाउन के समय तगड़ा झटका लगा हो, लेकिन मप्र का उद्योग जगत इससे हारा नहीं। न थका और न रुका, बल्कि कोरोनाकाल के बीच भी मप्र में औद्योगिक विकास ने नई राह निकाल ली। बंपर निवेश हुआ, नौकरियां गईं, लेकिन नया रोजगार भी खूब बढ़ा। केवल कोरोनाकाल में ही 15 हजार लोगों को नया रोजगार मिला। उस पर अब 3 हजार उद्योग और खोले जाना है। यह भी रोजगार की नई राह रहेगी।

प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर फोकस किया जा रहा है। सरकार नए औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीन एनर्जी, आर्गेनिक खाद से लेकर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बनाने की तैयारी कर रही है। भोपाल-राजगढ़ में 250 करोड़ से ग्रीन एनर्जी पार्क बनना है। इसमें 15 टन प्रतिदिन क्षमता का बायोगैस प्लांट, ऑर्गेनिक खाद, 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का कार्बन-डाई-ऑक्साइड कैप्चर प्लांट और 10 मेगावाट क्षमता का केप्टिव सोलर पावर प्लांट बनेंगे। हाइड्रोजन व अमोनिया गैस भी बनेगी। भोपाल-इंदौर-जबलपुर-ग्वालियर-कटनी सहित 7 प्रमुख क्षेत्रों में एयरपोर्ट व सड़क कनेक्टिविटी वाले बड़े लॉजिस्टिक पार्क लाने की तैयारी की जा रही है। भोपाल-इंदौर कॉरिडोर में आष्टा के समीप बड़े क्षेत्र पर एआइ व आईटी हब के लिए प्लान है। 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों को 714.56 करोड़ से बनना है। बैरसिया-भोपाल में 25.88 करोड़, आष्टा-सीहोर में 99.43 करोड़, धार में 79.43 करोड़, रतलाम में 462 करोड़ और नरसिंहपुर में 47.82 करोड़ की परियोजना है। इनमें 32 हजार करोड़ का निवेश संभावित है। 38 हजार रोजगार मिलेंगे। देवास में इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। यहां इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क, कमर्शियल, रेसीडेंशियल, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट की प्लानिंग है। देवास, सोनकच्छ, आष्टा व सीहोर तक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की योजना है। पुणे के पिनेकेल उद्योग समूह ने 2000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव दे रखे हैं।

● **सुनील सिंह**

रोजगार पर फोकस

मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना भी शामिल है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण कमजोर पड़ते ही मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रदेशभर में रोजगार मेलों का आयोजन शुरू करवा दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि पढ़े-लिखे युवाओं को रोजगार देने में मप्र देशभर में अव्वल है। रोजगार यानी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत युवाओं को टेक्निकल रूप से ट्रेंड किया और फिर उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिली। इसी तरह स्वरोजगार, यानी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत लोन उपलब्ध कराया। प्रदेश में मेलों का आयोजन कर युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। प्रदेश में कई छोटी कंपनियां भी निवेश करने जा रही हैं। इनसे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। इनमें रॉयल यूनिफोर्स 41 करोड़, जेके लाइफ केयर 24 करोड़, कुमार प्रिंटर्स 15 करोड़, मेकसन हेल्थ केयर 20 करोड़, राज रीसाइलिंग 18 करोड़, सिद्धायु लाइफ साइंसेस 28 करोड़, जिल ऑर्गेनिस 21 करोड़, एसटीआई फैब्रिक्राट 25 करोड़ का निवेश करने जा रही हैं। यह कंपनियां भी 12 से लेकर 200 लोगों तक को रोजगार मुहैया कराएंगी।

युवाओं की पसंद जैविक खेती

दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम के प्रदूषित हवा से तंग आकर कुछ युवाओं ने अपने गांव वापस लौटकर न केवल जैविक खेती को अपना आजीविका का साधन बनाया बल्कि गांव के किसानों को भी इसी ओर प्रेरित कर रहे हैं। इनमें भोपाल के इंजीनियर शशिभूषण, पीएचडी फार्मा अनुज, सुधांशु और सुष्मिता और आईआईटी कानपुर, आईआईएम लखनऊ तथा इंफोसिस से पढ़ाई करने के बाद विदेश में नौकरी करने वाले संदीप सक्सेना के नाम उल्लेखनीय हैं। संदीप के प्रोफाइल में कई पुरस्कारों का उल्लेख है। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई द्वारा सम्मानित होना उल्लेखनीय है। इंजीनियर शशि भूषण गुरुग्राम के अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों में बड़ी कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सजग होने के कारण वे बहुत जल्दी नौकरी छोड़कर गांव वापस आकर पुश्तैनी 25 एकड़ जमीन पर जैविक खेती करने लगे। शशि ने बहुत दिलचस्प बातें बताई कि उनकी उपज के ग्राहक उसी के आसपास के ग्रामीण हैं। उन्होंने कहा कि आसपास गांव के सभी किसान अपनी जमीन पर गेहूं बोते हैं। परंतु वे उनसे गेहूं खरीद के ले जाते हैं कारण यह है कि चूंकि वे अपने खेतों में जहर उगाते हैं, इसलिए शुद्ध खाने के लिए शशि से अनाज खरीदते हैं और अपना रसायन युक्त उपज बाजार में बेच देते हैं। सुधांशु और सुष्मिता की जोड़ी थोड़ी अलग है, वे अपने तथा अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती कर रहे हैं।

दरअसल सुधांशु और सुष्मिता उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद गुरुग्राम में करोड़ों की पैकेज पर नौकरी करने गए थे। करीब एक दशक तक नौकरी के बाद अपने गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए दोनों ने यह निर्णय लिया कि वापस अपने शहर लौटकर जैविक खेती करना इससे बेहतर है। मल्टीनेशनल की नौकरी छोड़ दोनों ने दो साल के भीतर जैविक खेती से न केवल अपने लिए शुद्ध आहार का प्रबंध किया, बल्कि गांव के अन्य छोटे किसानों को जोड़कर उन्हें भी जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया। आज सुधांशु का जैविक जीवन ब्रांड इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसके पास ग्राहकों की लंबी फेहरिस्त है, जिन्हें वह ऑर्गेनिक स्टोर, अमेजन और व्हाट्सएप के जरिए जैविक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। सुधांशु बताते हैं कि करोड़ों का पैकेज न सही, लेकिन खुद को और दूसरों को स्वस्थ रखने के लिए वे जो प्रयास कर रहे हैं, उससे उन्हें आत्मसंतोष मिल रहा है। वहीं सुष्मिता एक दशक से अधिक समय तक सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही थीं। उन्हें जमीनी स्तर से लेकर नीति निर्माण तक का व्यापक अनुभव हो गया था। स्वास्थ्य के बारे में उनकी समझ व्यापक है। वह कहती हैं कि दूषित हवा से 70 फीसदी लोग फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे हैं। वह एक प्रमाणित पोषण विशेषज्ञ, फिटनेस ट्रेनर और क्रॉसफिटर भी हैं जबकि सुधांशु ने यूके में लीड्स यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल से स्नातक किया और भारत की प्रमुख बीमा कंपनी के साथ काम किया। सुधांशु के पास स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा और चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव है, यानी सुधांशु और सुष्मिता दोनों के पास स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की जानकारी पहले से थी।

मप्र में पले-बढ़े सुधांशु और सुष्मिता को जब बड़े शहरों का जीवन उबाऊ लगने लगा, तो दोनों ने कुछ नया करने का सोचा। नए में खेती का आईडिया सबसे पहले उनके जेहन में आया। सुष्मिता कहती हैं कि बड़े शहरों में कोई भावनात्मक संबंध नहीं, कोई ठहराव नहीं, सिर्फ लोग पैसे के पीछे दिन-रात भागते हैं, इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि असल में नौकरी मिलते ही लोग पहले कर्ज लेकर गाड़ी, बंगला खरीद लेते हैं और पूरी जिंदगी ईएमआई चुकाने के लिए भागते रहते हैं। हम लोगों के साथ अच्छी बात यह थी कि हमने ऐशो-आराम के लिए बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया था। हमें लग्जरी जीवन नहीं जीना था, हमें सुकून की जिंदगी चाहिए थी। ईएमआई का कोई पंगा नहीं था, इसलिए आसानी से नौकरी छोड़ने का निर्णय ले पाए। अब दोनों ने मिलकर विदिशा मुख्यालय से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर धनौरा हवेली गांव में अपनी पुश्तैनी 14 एकड़ जमीन पर 2018 से जैविक खेती का सफर शुरू किया। शुरुआत दोनों ने जैविक औषधि से की थी। परंतु धीरे-धीरे खेत को एकीकृत जैविक खेत में बदल दिया। वर्तमान में उनके खेत में कई प्रकार की सब्जियां, हल्दी, अरहर, हरा चना, ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, काले चने, भूरे चने, प्राचीन खापली और बंसी गेहूं, जौ, सरसों, धनिया, मवेशियों के चारे के लिए बरसीम घास, कई पौधे उगाए जाते हैं। अमरूद, केला और नींबू का भी उत्पादन हो रहा है।

● **अक्स ब्यूरो**

जीरो बजट वाली खेती की सीख

सुधांशु जीरो बजट वाली खेती की सीख को सैकड़ों सीमांत किसानों तक ले जाना चाहते हैं ताकि वे भी इस अमूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनकर लाभांवित हो सकें। इससे न केवल उन्हें अपनी उपज के लिए बाजार प्राप्त करने में मदद मिलेगी बल्कि उन्हें अपने खेतों को टिकाऊ बनाने और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में भी मदद मिलेगी। वे गांव में छोटे-छोटे किसानों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा कि शुरू में किसानों के मन में यह डर था कि जैविक से उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अब यह भ्रम टूट चुका है। जैविक खाद के सिलसिले में उन्होंने कहा कि सड़कों पर बहुत सारी गाय विचरण करती रहती हैं। हम उन्हें आसरा देकर उनके गोबर और गौमूत्र को खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह जीरो बजट वाली खेती को संभव कर सकते है। सब्जियों की खेती के संबंध में उन्होंने कहा कि केवल दो से ढाई महीने में सब्जियां तैयार हो जाती हैं। किसान खेतों को टुकड़े-टुकड़े में बांटकर अलग-अलग मौसम की सब्जियां उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हम उन्हें बाजार उपलब्ध कराने में मदद कर रहे हैं ताकि वे जैविक खेती करने के लिए उत्साहित हों।

ईडी की सुप्रीम ताकत बरकरार!

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मिले गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने समेत प्रमुख अधिकारों को बरकरार रखा है। कोर्ट ने यह फैसला पीएमएलए के कई प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली 241 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए आरोपी की गिरफ्तारी, तलाशी, कुर्की, जब्ती इत्यादि अधिकार समेत कई प्रावधानों को उचित ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब ईडी नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही थी।

साथ ही ईडी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में अरेस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ताकत को बरकरार रखते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के तहत जमानत के लिए सख्त शर्तें कानूनी हैं न कि मनमानी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी अफसर पुलिस अधिकारी नहीं हैं और इसीलिए इन्फोर्समेंट केस इन्फार्मेशन रिपोर्ट यानी ईसीआईआर को एफआईआर नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ईडी के लिए ईसीआईआर यानी **अरेस्ट से जुड़े पेपर** देना जरूरी नहीं है और वह केवल गिरफ्तारी की वजह बताकर आरोपी को हिरासत में ले सकती है। गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की ताकत से लैस ईडी केंद्र सरकार की अकेली जांच एजेंसी है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। ईडी छापा भी मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। हालांकि अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है, जैसे मकान या कोई होटल, तो उसे खाली नहीं कराया जा सकता।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से छापेमारी की खबरें कुछ दिन में जरूर पढ़ने-सुनने को मिल ही जाती हैं। बीते कुछ वर्षों से अपनी कार्रवाई को लेकर यह संगठन लगातार खूब चर्चाओं में रहा है। प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है। प्रवर्तन का मतलब होता है बाध्य करना या लागू करना और निदेशालय का मतलब होता है ऐसा घर जहां से किसी कानून, विधि या उसके स्वरूप को बताया जाए। प्रवर्तन निदेशालय दो विशेष राजकोषीय कानूनों विदेशी मुद्रा अधिनियम, 1999 (फेमा) और धन की रोकधाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों को लागू करने का कार्य करता है।

प. बंगाल में बड़ा घोटाला उजागर

अभी हाल ही में ईडी ने पश्चिम बंगाल में एक बड़े घोटाले को उजागर किया है। ईडी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया तो शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में अर्पिता मुखर्जी के दो फ्लैटों पर छापेमारी के दौरान सोने, डॉलर और कुछ दस्तावेजों के अलावा 51 करोड़ रुपए की नकदी का एक बड़ा भंडार मिला है। बंगाली और उड़िया फिल्म उद्योग में काम करने वाली अभिनेत्री और मॉडल अर्पिता मुखर्जी फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। उधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए ममता बनर्जी ने पाथ को मंत्री के साथ ही पार्टी के सभी पदों से बर्खास्त कर दिया है। उधर, ईडी इस मामले में और कुछ नेताओं से पूछताछ कर सकती है।

करीब 17 साल पहले साल 2005 में प्रवर्तन निदेशालय को गंभीर वित्तीय अपराधों की जांच की शक्ति दी गई थी। तब से लेकर अब तक ईडी ने 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि देश में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सिर्फ 25 लोगों को ही अदालतों के द्वारा सजा हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत 5422 मामले या प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की है। साथ ही मार्च 2022 तक संपत्तियों को अटैच करने के 1739 आदेश जारी किए जिसके तहत 1,04,702 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई। ईडी को 2002 में अमल लाए गए पीएमएलए के सख्त प्रावधानों को लागू करने के लिए एक जुलाई 2005 से सौंपा गया था। इन शक्तियों के तहत एजेंसी जांच के स्तर पर आरोपी को समन, गिरफ्तार और उसकी संपत्ति को अटैच कर सकती है और अदालत के समक्ष अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चला सकती है।

आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी ने इस दौरान अदालतों के समक्ष 992 आरोप पत्र या अभियोजन शिकायतें दाखिल कीं। पीएमएलए के अमल में आने के 17 साल के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में 25 लोग ही अदालतों से सजा पाए हैं जबकि 400 लोग गिरफ्तार किए गए। अधिकारियों के अनुसार, जो लोग दोषी ठहराए गए उनमें ड्रग तस्करी, धोखाधड़ी से विदेश पैसा भेजने, आतंकी वित्तपोषण और सरकारी कोष में भ्रष्टाचार जैसे मामले शामिल हैं। एजेंसी ने पीएमएलए के तहत संपत्तियों को अटैच करने के लिए 1739 अस्थायी आदेश जारी किए। पीएमएलए के न्यायाधिकरण द्वारा 1369 आदेश की पुष्टि की गई। इसके तहत 58,591 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गईं जबकि अस्थायी आदेश के तहत 1,04,702 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की गई थीं।

ईडी ने शीर्ष राजनीतिज्ञों, अफसरों, कारोबारी समूहों, कारपोरेट्स, विदेशी नागरिकों और अन्य के मामलों की भी जांच की। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत 31 मार्च तक 30,716 मामलों की जांच शुरू की। यह कानून 1973 के फेरा की जगह 1999 में लागू किया गया था। आंकड़ों के अनुसार, 15,495 फेमा मामलों का निपटारा किया जबकि जांच के बाद 8109 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इनमें से 6472 कारण बताओ नोटिसों पर फैसला सुनाया गया या अंतिम रूप दिया गया। एजेंसी ने विजय माल्या और नीरव मोदी समेत 9 लोगों को 2018 के आर्थिक अपराध भगोड़ा कानून के तहत आर्थिक अपराधी भगोड़ा घोषित किया जबकि 14 लोगों के लिए उसने इसकी मांग की थी।

● **लोकेंद्र शर्मा**

अवैध खनन पर अंकुश नहीं

10 साल से नहीं थम रहे माफिया के हमले

2009 बैच के आईपीएस नरेंद्र कुमार बानमौर में बतौर एसडीओपी पदस्थ थे। होली के दिन 8 मार्च 2012 को अवैध खनन कर पत्थर लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने की कोशिश के दौरान उन पर ट्रैक्टर पलट दिया जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस आरक्षक धर्मेंद्र चौहान को माफिया ने 2015 में कुचलकर मार डाला। 6 मार्च 2016 को रेत की गाड़ी का पीछा करते हुए फॉरेस्ट गार्ड नरेंद्र शर्मा की हत्या कर दी। 7 सितंबर 2018 को मुरैना बैरियर पर डिप्टी रेंजर सूबेदार सिंह कुशवाह की हत्या कर दी गई। पुरानी छावनी थाने के तत्कालीन प्रभारी सुधीर सिंह कुशवाह 4 फरवरी 2021 को हमले में बाल-बाल बचे। इलाके के सभी 7 गांव के लोग अवैध खनन में शामिल हैं। जैसे ही यहां कोई अजनबी वाहन दिखता है, उसकी मुखबिरी शुरू हो जाती है। एक पुलिसकर्मी के अनुसार, यही वजह है कि यहां माफिया मजबूत है और कार्रवाई भी नहीं हो पाती।

आईपीएस, डिप्टी रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड, आरक्षक को कुचलकर मार देने और अनेक अधिकारियों को जान से मारने का प्रयास करने के बाद भी मप्र के ग्वालियर-मुरैना क्षेत्र में सरकार खनन माफिया के सामने नतमस्तक बनी हुई है। बात हो रही है ग्वालियर-मुरैना के बॉर्डर पर बसे रंचौली, पढ़ावली, गडाजर, मडराई, माटोली, पौर, बरईपुरा जैसे उन तमाम गांव की। इन्हें सफेद पत्थर के अवैध खनन के लिए पहचाना जाता है और कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के लिए कुख्यात माना जाता है। स्थिति ये है कि आईपीएस नरेंद्र कुमार की हत्या के 10 साल बाद भी शासन-प्रशासन इस क्षेत्र में अवैध खनन व माफिया को रोकने में नाकाम साबित हुआ है।

माफिया के हौंसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो इन क्षेत्रों से रोजाना लगभग 20 लाख रुपए तक का अवैध सफेद पत्थर खदानों से निकालकर बेच रहे हैं। बिना लीज के दबंग और लीज वाले भी खनिज नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नियमानुसार 20 फीट से अधिक गहराई में खनन करने के लिए केंद्र से अनुमति लेनी होती है। मगर, इन क्षेत्रों में किसी ने ये अनुमति नहीं ली है और खनन पहाड़ को 110 फीट की गहराई तक काट दिया गया है। वन विभाग, मुरैना में एसडीओ पद पर पहुंची श्रद्धा पंढारे ने जैसे ही रेत व **पत्थर माफिया** पर सख्ती की तो उन पर 12 बार जानलेवा हमले हुए। तेवर सख्त रहे तो माफिया ने उनका ट्रांसफर करा दिया। 45 दिन में श्रद्धा ने रेत-पत्थर माफिया की बाइक, ट्रैक्टर-ट्रॉली से लेकर ट्रक तक जब्त किए।

यह बात हैरान करने वाली है कि 15 साल से चंबल नदी से रेत निकालने पर रोक है फिर भी नदी के घाटों पर दिन-रात अवैध खनन किया जा रहा है। रेत माफिया से अधिकारी-कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण चंबल से हर माह 35 करोड़ रुपए से अधिक की रेत का अवैध कारोबार हो रहा है। मुरैना के ही करीब 14 हजार परिवार सीधे इस अवैध कारोबार से जुड़े हैं। इनके ऊपर राजनीतिक वरदहस्त है। नदी से निकली रेत पुलिस की हर जांच चौकी और बैरियर से पास होकर बाजार तक पहुंच रही है। ये रेत भानपुर, सरायछोला, देवरी चौकी के बाद आरटीओ बैरियर, सेल्स टैक्स बैरियर, कृषि उपज मंडी नाका और छौंदा टोल प्लाजा को लांघकर ग्वालियर तक आती है लेकिन कहीं भी इन वाहनों को पकड़ा नहीं जाता। जबकि बानमोर पर वन विभाग ने चौकी भी बना रखी है।

अवैध उत्खनन के लिए ग्वालियर चंबल संभाग पूरी तरह से बदनाम हो चुका है। अवैध उत्खनन करने वालों के हौंसले इतने बुलंद हैं कि वह अपने धंधे में अड़ंगा लगाने वालों को मौत के घाट तक उतार देते हैं। इतना ही नहीं सफेद पत्थर और रेत के अवैध खनन के लिए बदनाम ग्वालियर-चंबल इलाका अब मौत की खदानों के नाम पर भी बदनाम होने लगा है, क्योंकि ग्वालियर जिले की 168 पत्थर खदानों में से 50 से अधिक बंद खदानें अब मौत के गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। बारिश के दिनों के अलावा भी इन गड्ढों में पानी भर जाने के कारण यह हादसे का स्थान बन चुके हैं। शहर के आसपास इस तरह की कई खदानों के गड्ढे नजर आ रहे हैं। पानी से भरे इन गड्ढों में या तो लोग नहाने के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं या फिर लोग इन में कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। महानगर के आसपास मौजूद 200 से 250 फीट तक गहरे इन गड्ढों में हर साल आठ से दस लोग अपनी जान गंवा देते है। ग्वालियर का जिला प्रशासन ये सब जानने के बाद भी अनजान बना हुआ है। जबकि मप्र की हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का भी साफ आदेश है कि पत्थर की खदानें लोगों की जान ले रही है। इसलिए खनिज विभाग लीज की अनुमति के वक्त खनन कारोबारी से गड्ढों को भरने का बॉन्ड भरवाएं लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है।

वर्ष 2009 से अचानक बढ़ी माफिया की मनमानी को रोकने में खनिज विभाग की पॉलिसी भी अक्षम साबित हुई है। क्योंकि पॉलिसी के मुताबिक लीज के समय खनिज नियमों में साफ है कि जहां प्रशासन खदान की लीज देगा, उसके बाद, खनन कारोबारी पत्थर निकालने के बाद वहां उस लेवल तक भराव करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ग्वालियर के शताब्दीपुरम, महु जमहार के साथ-साथ जिले के बिलौआ में काली गिट्टी की खदानें संचालित की जा रही हैं। वैसे राजनीतिक संरक्षण में चल रहे वैध-अवैध उत्खनन के लिए बीते चार सालों से बिलौआ क्षेत्र चारागाह बना हुआ है। इससे पहले शहर के आवासीय क्षेत्र से लगे शताब्दीपुरम से सटी पीर बाबा की पहाड़ी काली गिट्टी के लिए मशहूर थी।

● **बृजेश साहू**

महंगाई से गांव बेहाल

राष्ट्र निर्माण के नाम पर कमरतोड़ महंगाई अनेक लोगों के लिए असहनीय होती जा रही है। वैसे तो महंगाई हर वर्ग को प्रभावित करती है, लेकिन जिनकी कमाई का बड़ा हिस्सा खाने-पीने पर खर्च हो जाता है उन पर इसकी मार सबसे अधिक है। कारण यह है कि ईंधन के बाद खाने-पीने की चीजों के दाम ही सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। सरकार का रवैया रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से पता चलता है। पुणे में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अमेरिका जो सबसे धनी देश है, वहां मुद्रास्फीति पिछले 40 वर्षों में अपने चरम पर है। इसलिए हमें अपराधबोध नहीं महसूस करना चाहिए। हालांकि जिस दिन उन्होंने यह कहा, उसी शाम वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती की घोषणा कर दी। पेट्रोल पर ड्यूटी 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए घटाई गई है। हालांकि इससे पहले दोनों के दाम दो महीने में 10-10 रुपए बढ़े भी थे। इससे पहले रिजर्व बैंक ने भी अचानक कर्ज 0.40 फीसदी महंगा कर दिया था ताकि महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके। हालांकि अभी यह कहना मुश्किल है कि इन कदमों से महंगाई कितनी काबू में आएगी।

सरकारी आंकड़ों पर ही गौर कीजिए। अप्रैल में खुदरा महंगाई 8 साल में सबसे ज्यादा 7.79 फीसदी पर पहुंच गई। खाद्य महंगाई 8.38 फीसदी हो गई। यह मार्च में 7.68 फीसदी थी और एक साल पहले यह सिर्फ 1.96 फीसदी थी। फूड बास्केट में शामिल लगभग सभी चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ है। पिछले महीने थोक महंगाई तो 15.08 फीसदी पर पहुंच गई और यह लगातार 13 महीने से 10 फीसदी से ज्यादा है। इस महंगाई की खास बात है कि यह शहरियों की तुलना में ग्रामीणों को अधिक परेशान कर रही है। शहरों में खुदरा महंगाई दर 7.09 फीसदी तो ग्रामीण इलाकों में यह 8.38 फीसदी हो गई। किसान भले ही खाने की चीजें उपजाते हों, लेकिन उन्हें खाद्य सामग्री अधिक दाम पर खरीदनी पड़ रही है। गांवों में खाद्य मुद्रास्फीति दर 8.50 फीसदी और शहरों में 8.09 फीसदी है। अप्रैल 2021 में गांवों में खाद्य महंगाई 1.31 फीसदी और शहरों में 3.15 फीसदी थी।

किसानों पर महंगाई की मार दोतरफा है, क्योंकि उनके लिए खेती की लागत तो बढ़ गई लेकिन उपज के दाम उस अनुपात में नहीं बढ़े। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट बताती है, भारत में खेती की लागत वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में 20 फीसदी तक बढ़ गई। पिछले 5 सालों में कृषि लागत में काफी अंतर आया है। ट्रैक्टर की कीमत 5 साल में 50 फीसदी से अधिक बढ़ गई है। डीजल, खाद और बीज के दाम तथा मजदूरी भी काफी बढ़ी है, लेकिन बढ़ी लागत के अनुपात में फसलों के मूल्य नहीं बढ़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सामान्य मानसून की उम्मीद और खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी के कारण 2022-23 में ग्रामीणों की आय बढ़ेगी, लेकिन कृषि लागत अधिक बढ़ने के कारण यहां की आबादी पर संकट और गहरा सकता है।

रूस-यूक्रेन जंग से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम बढ़े तो किसानों की आमदनी बढ़ने की भी उम्मीद जगी। लेकिन यह उम्मीद तब काफूर हो गई जब सरकार ने देश में गेहूं की उपलब्धता के संकट का हवाला देते हुए निर्यात पर पाबंदी लगी दी। हरियाणा प्रोग्रेसिव किसान संगठन के अध्यक्ष साहब सिंह कहते हैं कि निर्यात के कारण किसानों को पहली बार गेहूं के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (2015 रुपए प्रति क्विंटल) से 300 रुपए तक अधिक मिल रहे थे। लेकिन निर्यात पर प्रतिबंध के बाद दाम एमएसपी से नीचे आ गए हैं। इस तरह मौसम की तपिश के कारण उत्पादन का नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए राहत का रास्ता सरकार ने बंद कर दिया है।

महंगाई से पूरा विश्व परेशान है। अमेरिका और यूरोप चार दशकों की रिकॉर्ड महंगाई का सामना कर रहे हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते खाद्यान्न, खाद्य तेल और ईंधन की महंगाई से फिलहाल राहत की संभावना नहीं है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने सुरक्षा परिषद में कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया के 60 फीसदी अल्पपोषित लोग प्रभावित हुए हैं। अनेक देशों में बड़ी संख्या में लोग अकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित इंटरगवर्मेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) ने भविष्यवाणी की है कि भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्यान्न उत्पादन घटने से महंगाई और बढ़ेगी। मार्च और अप्रैल में भीषण गर्मी से गेहूं और अन्य रबी फसलों की उपज 25 प्रतिशत तक कम हुई है। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए संकट बढ़ गया है।

● **जितेंद्र तिवारी**

महंगाई से निपटने गंभीरता जरूरी

महंगाई से निपटने के प्रयासों में गंभीरता लाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ एवं पंजाब योजना बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अमृत सागर मित्तल कहते हैं, गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने जैसे फैसले से महंगाई कम करने में खास मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर खाद्य पदार्थों के दाम 25 फीसदी तक बढ़ चुके हैं। पीडीएस के दायरे में आने वाली 80 करोड़ आबादी को महंगाई से राहत देने के लिए राशन व्यवस्था का मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। केरोसिन मुक्त अभियान के तहत चंडीगढ़ समेत देश के कई इलाकों की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी सस्ते ईंधन से वंचित कर दी गई, लेकिन इसकी जगह पीडीएस में रियायती रसोई गैस सिलेंडर को शामिल नहीं किया गया। कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर महंगाई का दबाव कम करने लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य तेल, दालें और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों को शामिल करने की दलील दी जा रही है। कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर शोध कर रहे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के छात्र निर्मल सिंह का कहना है कि मांग और आपूर्ति के बीच अंतर पाटने और खाद्य पदार्थों के सतत विकास को बनाए रखने के लिए 'क्लाइमेट स्मार्ट' फसलों को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। महंगाई पर काबू पाने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों की सप्लाई चेन मजबूत बनाने और उनके अति भंडारण तथा मूल्य निर्धारण की निगरानी के लिए एक पारदर्शी तंत्र बनाने की जरूरत है।

घुसपैठ बढ़ाने के लिए नियमों का सहारा

प्रदेश में एक तरफ बाघ सहित अन्य वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ने के कारण जंगल छोटे पड़ने लगे हैं, वहीं वन क्षेत्र में मानवीय घुसपैठ बढ़ाने के लिए नियमों को सहारा लिया जा रहा है। राजधानी भोपाल में बाघभ्रमण क्षेत्र में रसूखदारों के निर्माणों को वैध करने और मनमाना निर्माण करने के लिए शहर विकास योजना 2031 में इसके लिए प्रावधान किए गए। प्रावधान के अनुसार जिस व्यक्ति की वन क्षेत्र में जितना बड़ा भू-खंड है उसके डेढ़ गुना तक वह निर्माण कर सकता है। इस प्रावधान से वन्य प्राणी विशेषज्ञ आश्चर्यचकित हैं। गौरतलब है कि कलियासोत से केरवा, कोलार तक वन क्षेत्र में 10 बड़े कॉलेज, 40 से अधिक बड़े फार्म हाउस, 70 के करीब बड़े बंगले, 90 से अधिक व्यवसायिक गतिविधियां शुरू हो गईं। इतना ही नहीं, जंगल के अंदर अपनी जमीन की दावेदारी करने वालों की संख्या भी बढ़ गई।

गौरतलब है कि कलियासोत से केरवा, कोलार तक वन क्षेत्र में साल दर साल अतिक्रमण बढ़ा है और वहां निर्माण कार्य हुए हैं उससे वन्यप्राणी अब वनों से निकलकर कांक्रीट के जंगल यानी गांव और शहरों की ओर आ रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि निरंतर वन्यप्राणियों और मनुष्यों में लगातार संघर्ष बढ़ रहा है। इसे रोकने की बजाय शहर किनारे बाघ के घर में मानवीय घुसपैठ बढ़ाने के लिए अब नियमों का सहारा भी लिया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार यहां वन की जगह पीएसपी लैडयूज तय कर एक एफएआर तय किया गया है। शहर विकास योजना 2031 में इसके लिए प्रावधान किए गए। एफएआर यानि जमीन के क्षेत्रफल की तुलना में निर्माण का नियम। एक एफएआर का मतलब है एक हजार वर्गफीट जमीन पर एक हजार वर्गफीट निर्माण की अनुमति मिलना। इसके अलावा नए नियमों में एफएआर खरीदने का प्रावधान भी है। चंदनपुरा व इससे लगे वनक्षेत्र में आधा एफएआर खरीदा भी जा सकता है। जाहिर है, यहां किसी के पास 10 हजार वर्गफीट जमीन है तो वह 15 हजार वर्गफीट तक निर्माण करने की अनुमति के लिए कोशिश कर सकता है। इस पूरे क्षेत्र में शहर के कई नामी व प्रमुख लोगों की जमीनें हैं। यहां इस एफएआर का लाभ उठाकर बड़े निर्माण किए जा सकते हैं। इससे बाघ की आवाजाही और रहवास में खलल पड़ेगा। यदि इन्हीं नियम व श्रेणी के साथ योजना लागू हुई तो फिर बाघ व मानव के बीच टकराव की स्थिति और बढ़ेगी। गौरतलब है कि चंदनपुरा बाघ रहवास व भ्रमण क्षेत्र में पीएसपी लैडयूज तय कर यहां पहले स्कूल, अस्पताल, कॉलेज जैसे बड़े संस्थान खुल गए। पीएसपी लैडयूज के तहत वनक्षेत्र कम कर बड़े निर्माण किए गए। समय के साथ इन्हें सभी तरह की अनुमतियां भी मिल गई। अब नई योजना में शहर की पॉश कॉलोनी की तरह निर्माण शर्त तय कर तेजी से यहां निर्माण की राह खोलने की स्थिति बना दी गई।

बाघभ्रमण क्षेत्र में नियमों की अनदेखी करते हुए स्कूल-कॉलेज और अस्पताल के लिए जमीन आवंटन हुआ है। चंदनपुरा में शैक्षणिक संस्थान समेत अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के निर्माण हो रहे हैं। कलियासोत जलभराव वाले ग्राम खुदागंज, बरखेड़ी खुर्द, बरखेड़ी कला क्षेत्र में भी पीएसएपी दर्शाकर स्कूल-कॉलेजों के लिए निर्माण की तैयारी है। जबकि, ग्राम चंदनपुरा, चीचली, मेंडोरा, मेंडोरी, छावनी क्षेत्र उच्चतम न्यायालय के 12-12-96 के आदेश में गोधावर्मन में परिभाषित वन की श्रेणी में है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय की रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने 6 फरवरी 2020 को आदेश दिया था कि क्षेत्र को 3 माह के अंदर जंगल मेपिंग कर नोटिफाई कर वन विभाग को जंगल की भूमि हस्तांतरित करें। यह क्षेत्र रातापानी अभ्यारण्य से जुड़ा है। वन विभाग यहां 40 बाघों का भ्रमण क्षेत्र मानता है। यह बाघों का प्रजनन क्षेत्र भी है। इसीलिए भोपाल मास्टर प्लान 2031 में यूआरडीपीएफआई गाइडलाइन और फारेस्ट एक्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को लागू करने की मांग की जा रही है। ग्राम चंदनपुरा, चीचली, मेंडोरा, मेंडोरी, छावनी क्षेत्र उच्चतम न्यायालय के केस नंबर 2/202/1995 के आदेश 12-12-96 गोधावर्मन में परिभाषित वन की श्रेणी में आता है। वन विभाग ने कोर्ट के आदेश के बाद 350 हेक्टेयर क्षेत्रफल को जंगल घोषित किया है। यह रातापानी अभयारण्य से जुड़ा है। इसलिए यह बाघ भ्रमण क्षेत्रों में आता है।

● **विकास दुबे**

बाघभ्रमण क्षेत्र खत्म करने की साजिश

कलियासोत डैम के नजदीक बाघभ्रमण क्षेत्र को संरक्षित करना था, लेकिन यहां के ग्राम खुदागंज, बरखेड़ी खुर्द, बरखेड़ी कला क्षेत्र के कुछ क्षेत्र डैम के जलभराव क्षेत्र में आते हैं। प्रस्तावित मास्टर प्लान 2031 में इन गांवों के जलभराव क्षेत्रों को पीएसएपी दर्शाया गया है। यानी यहां स्कूल, कॉलेज खोले जा सकते हैं। इसी तरह केरवा कोठी से केरवा डैम ग्राम मेंडोरा में वनस्पति उद्यान जो वर्तमान मास्टर प्लान में है, इसकी जगह आवासीय सामान्य 5 में दिखाया गया है। जो कि वाटर बॉडी के लिए नुकसानदेह है। कलियासोत डैम से ऊपर ग्राम सिंगपुर के वनस्पति उद्यान क्षेत्र को पीएसपी कर यहां भी निर्माण की राह खोलने के प्रावधान हैं। शहर किनारे बाघभ्रमण व रहवास क्षेत्र चंदनपुरा, मेंडोरा, मेंडोरी और संबंधित क्षेत्रों में 6 बाघ मौजूद है। नगर वन में काफी दिनों तक रहे बाघों में से दूसरा बाघ भी यहां से निकल गया है। बताया जा रहा है कि ये बाघ अब सीपीए प्लांटेशन से लेकर एक निजी यूनिवर्सिटी के पीछे की ओर ही है। यहां भ्रमण करने वाले रूपेश मालवीय का कहना है कि उन्होंने बाघों की आवाज सुनी है। यहां कॉर्नर पर दुकान लगाने वाले का कहना है कि बाघ की दहाड़ उसे भी सुनने को मिली है। गौरतलब है कि शहर किनारे इस क्षेत्र में 18 से 20 बाघ है, इनमें अभी कुछ शावक भी हैं। इनमें से करीब 6 बाघ फिलहाल भोपाल किनारे जंगल में ही हैं। रेंजर शिवपाल पिपरदे का कहना है कि बाघ नगर वन से निकल चुके हैं। हालांकि वे अब भी लगातार मॉनीटरिंग की बात कह रहे हैं, ताकि बाघों के मूवमेंट पर नजर रखी जा सके।

सरकारी जेबकटी से आहत!

आम आदमी पर महंगाई की मार बढ़ गई है। 18 जुलाई से जरूरत की कई चीजें महंगी हो गईं, जिसकी वजह से आपकी जेब पर और बोझ बढ़ेगा। दही-लस्सी से लेकर अस्पतालों में इलाज के लिए अब लोगों को अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। जरूरत की तमाम वस्तुओं पर सरकार ने जीएसटी की दरें बढ़ा दी हैं। कई वस्तुओं को पहली बार जीएसटी के दायरे में लाया गया है। जीएसटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक गत दिनों इस सिफारिश को लागू किया गया, जिसके कारण कई चीजें महंगी हो जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार जीएसटी के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया था। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया।

ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स आदि पर सरकार ने जीएसटी को बढ़ा दिया है। अब इस पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी वसूली जाएगी। अब 5,000 रुपए से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा 1,000 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल के कमरों पर 12 फीसदी के हिसाब से टैक्स लगाने का प्रावधान है। अभी तक इस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता था। बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब इकनॉमी क्लास तक सीमित होगी। आरबीआई, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जैसे नियामकों की सेवाओं के साथ रिहायशी मकान कारोबारी यूनिट को किराए पर देने पर टैक्स लगेगा।

बैटरी या उसके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायती 5 फीसदी जीएसटी बना रहेगा। पैक्ड मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन और मटर पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। जो पहले नहीं लगता था। चेक जारी करने के एवज में बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। सौर वॉटर हीटर पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा, पहले ये 5 प्रतिशत था। सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और शवदाहगृह के लिए जारी होने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। ये अब तक 12 फीसदी था। वहीं रोपवे से वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन, सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी हुआ। ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में यूज होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है पर अब 18 की बजाय 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या महंगा हो रहा है और क्या सस्ता... हम आपको जीएसटी के इतिहास बारे में बताएं और इससे पहले भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर क्या टैक्स प्रणाली थी उसके बारे में बताएं, उसके पहले सोचा आपको एक सरकारी आंकड़ा बता दें।

दरअसल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जून महीने में जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 56 फीसदी बढ़कर 1.44 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ये लगातार पांचवां ऐसा महीना रहा, जब सरकार को जीएसटी से एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ है। मई में सरकार को जीएसटी से 1.40 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। प्री-पैक फूड आइटम जैसे दूध के पैक्ड प्रोडक्ट- दही, लस्सी, पनीर और छाछ पर सरकार ऐसे वक्त में 5 फीसदी जीएसटी वसूल रही है जब देश में महंगाई अभी भी कई सालों के उच्च स्तर पर बनी हुई है और दूसरी ओर जीएसटी कलेक्शन भी लगातार बढ़ रहा है। अच्छा! कई लोगों को ये भी लगता है कि सरकार क्या करे, ये फैसला तो जीएसटी कांउसिल ने लिया है। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? चलिए ये भी क्लियर हो जाएगा जीएसटी कांउसिल को जानने से पहले आइए जीएसटी को जान लें जिसकी दरें बढ़ने से लोगों के लिए मक्खन लगाना भी मुश्किल हो गया है। मतलब ब्रेड टोस्ट-रोटी-पराठे पर मक्खन लगाकर खाना भी मुश्किल हो गया है।

साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता की अध्यक्षता में जीएसटी के ऊपर रिव्यू के लिए एक कमेटी का गठन किया था जिसमें उन्हें जीएसटी का पूरा मॉडल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। केलकर टास्क फोर्स ने जीएसटी के रूप में अप्रत्यक्ष करों का एकीकरण करने की सलाह दी। 2006 में अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने जीएसटी का जिक्र किया था। 2010 में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपने भाषण में घोषणा की थी कि जीएसटी अप्रैल, 2011 से लागू कर दिया जाएगा। 2011 में लोकसभा में सभी वस्तु और सेवाओं पर जीएसटी के लिए 115वां संविधान संशोधन बिल लाया गया। 2013 में स्थाई समिति ने जीएसटी पर अपनी रिपोर्ट पेश की और नवंबर 2009 में सरकार के पेट्रोलियम पदार्थों के जीएसटी में शामिल करने के प्रस्ताव को एंपावर्ड कमेटी ने खारिज कर दिया।

● **जय सिंह**

अब तक का सबसे बड़ा टैक्स सुधार

भारत में अब तक का सबसे बड़ा टैक्स सुधार, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। एक देश-एक कर कहे जाने वाली इस सेवा को मोदी सरकार ने स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार कहा था। कहते हैं इस कर सुधार का ढांचा आज से 22 साल पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। वस्तु एवं सेवा कर को संक्षिप्त रूप में जीएसटी कहते हैं। गुड्स यानी जिन सामानों का इस्तेमाल हम करते हैं, उसमें कोई भी पैकेज्ड खाद्य सामग्री, सिगरेट पैकेट, मोबाइल हैंडसेट, ट्रक से लेकर कार तक शामिल सेवाओं में हम दूरसंचार सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं या होटल में रहना-खाना और वहां की सर्विस। जीएसटी लागू करने का मकसद सीधा और साफ है- एक देश-एक मार्केट-एक टैक्स। जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्स, वैट, क्रय कर, एक्साइज ड्यूटी और अन्य कई टैक्स समाप्त हो गए। इनकी जगह जीएसटी ने ले ली। हालांकि, अभी भी शराब, पेट्रोलियम पदार्थ और स्टाम्प ड्यूटी को जीएसटी से मुक्त रखा गया है। इन पर आज भी पुरानी टैक्स व्यवस्था लागू है।

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का सिलसिला अब विकराल रूप ले चुका है। इससे लोकतंत्र की गरिमा को आघात पहुंच रहा है। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुफ्त की बंदरबाट पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन भारत में ऐसी कोई प्रमुख पार्टी नहीं है, जिसने चुनावों के दौरान मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की सियासत न की हो। इसी प्रचार पर फोकस रखा जाता है-'मुफ्त ले लो, पर वोट हमें दे दो।'

● राजेंद्र आगाल

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां लोकतंत्र की जड़ें काफी मजबूत हैं। तभी तो यहां जब भी लोकतंत्र का महापर्व यानी चुनाव आता है तो देश की पूरी आबादी उसके रंग में रंग जाती है। लेकिन पिछले एक-डेढ़ दशक से देश में लोगों को लुभाने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का सिलसिला इस तेजी से बढ़ा है कि लोकतंत्र का महापर्व मुफ्त की घोषणाओं का बाजार बनकर रह जाता है। हर राजनीतिक पार्टी इस दौरान लोगों को आकर्षित करने के लिए तरह-तरह की घोषणाएं करती हैं। दक्षिण भारत से शुरू हुआ मुफ्त की रेवड़ी बांटने का सिलसिला आज पूरे देश में पसर चुका है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटने पर आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का सिलसिला बंद होगा और कब?

अभी हाल ही में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्त रेवड़ियां बांटने की राजनीति का मुद्दा उठाया था। मुफ्तखोरी के जरिए वोट बटोरने की संस्कृति पर सख्त टिप्पणी की थी और ऐसी रेवड़ियों को देश के विकास के लिए घातक भी करार दिया था। प्रधानमंत्री ने खासकर युवाओं को सावधान करते हुए आव्हान किया था कि हमें इस सोच को हराना और राजनीति से हटाना है। प्रधानमंत्री के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक धन से तर्कहीन मुफ्त उपहार देने का वादा करने वाले राजनीतिक दलों के मुद्दे को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर एक स्टैंड लेने के लिए कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र से इस बात पर विचार करने को कहा कि क्या समाधान के लिए वित्त आयोग के सुझाव मांगे जा सकते हैं। इससे देश में सवाल उठने लगे हैं कि क्या मुफ्त की रेवड़ियां बांटने पर अंकुश लगेगा?

सभी रेवड़ी की श्रेणी में नहीं

बहरहाल भारत में ऐसी कोई प्रमुख पार्टी नहीं है, जिसने चुनावों के दौरान मुफ्त रेवड़ियां बांटने की सियासत न की हो। इसी प्रचार पर फोकस रखा जाता है-'मुफ्त ले लो, पर वोट हमें दे दो।' दरअसल रेवड़ियां, जन कल्याणकारी योजनाओं और लोक लुभावन नीतियों के बीच एक पतली-सी लकीर है। यदि आम नागरिक की जिंदगी, आजीविका, अस्तित्व से जुड़ी कोई परियोजना है और उसे सरकार नि:शुल्क ही मुहैया करा रही है, तो उसे रेवड़ी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। भारत एक सामाजिक कल्याण की सोच वाला देश है, लोकतंत्र है, जनता के प्रति सरकार के दायित्व हैं। अर्थव्यवस्था, राजकोषीय घाटा, राष्ट्रीय कर्ज, जीडीपी और कर-संग्रह बेहद महत्वपूर्ण कारक हैं, लेकिन उनके मद्देनजर सरकार जनता को गरीबी और भुखमरी की तरफ नहीं धकेल सकती। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज लगातार बांट रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सस्ता अनाज अलग से उपलब्ध कराया जाता रहा है। देश में खाद्य सुरक्षा का कानून है। इसके अलावा, कोरोना-रोधी टीकों की 200 करोड़ से अधिक खुराकें भी नि:शुल्क दी गई हैं और यह सिलसिला अब भी जारी है। आयुष्मान भारत, उज्ज्वला गैस योजना, पक्के घर, नल में जल, शौचालय, किसान सम्मान राशि आदि योजनाएं लगभग नि:शुल्क हैं। उन्हें रेवड़ियां नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे राष्ट्रीय स्तर पर, हर राज्य और हर पात्र नागरिक को मुहैया कराई जा रही हैं। देश में 6-14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा भी

बिजली लिस्ट में सबसे पहले

मुफ्त सामान की लिस्ट में बिजली पहले नंबर पर आती है। हाल फिलहाल में कई राज्यों में बिजली कटौती बढ़ गई थी। इसके पीछे एक बड़ा कारण था राज्यों पर बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों का बकाया पैसा। जब राजनीतिक पार्टियां मुफ्त बिजली का वादा करती हैं तो उसका सीधा मतलब है मुफ्त में कुछ यूनिट बिजली मिलना। ज्यादातर लोग ऐसे वादों से खुश हो जाते हैं और उस नेता के फैन हो जाते हैं जो मुफ्त में बिजली देने की घोषणा करता है। हालांकि जमीनी हकीकत ये है कि राज्य सरकारों पर इस तरह की घोषणा का उल्टा असर पड़ता है। मुफ्त बिजली का मतलब है राज्य सरकारों को बिजली वितरण कंपनियों को ज्यादा पैसा चुकाना होगा। ये वो पैसा होता है, जिसे सरकार को अपने खजाने से देना होता है। राज्य इस बढ़े खर्च को चुका पाने में नाकाम हो जाते हैं, जिससे बिजली वितरण कंपनियों का राज्यों पर बकाया बढ़ जाता है। इस पैसे को चुकाने के लिए राज्य सरकारें, केंद्र से और ज्यादा कर्ज लेती हैं। ये खतरनाक साइकिल लगातार चलती रहती है, और बिजली संकट बढ़ता रहता है। मुफ्त बिजली का वादा किसी राज्य पर कितना भारी पड़ रहा है, ये भी आपको जानना चाहिए। राज्यों पर बिजली वितरण कंपनियों का बकाया 1 लाख 39 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये एक बड़ी रकम है और ये बताती है मुफ्त बिजली का वादा कितना खोखला है। अब आप सोचिए कि अगर किसी राज्य के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां फ्री बिजली की घोषणा कर देती हैं, जबकि उस राज्य का बिजली वितरण कंपनियों का करोड़ों रुपए का बकाया है तो इसका नतीजा क्या होगा। कोरोनाकाल में सभी राज्यों पर आर्थिक बोझ पड़ा, सबका बजट बिगड़ा, अब रिकवरी भी हो रही है। जरा सोचिए कि ऐसे हालात में अगर मुफ्त सामान देने के वादे किए जाएंगे तो उसका राज्यों की आर्थिक सेहत पर कितना बुरा असर होगा।

मुफ्त है। हालांकि शीर्ष अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को सचेत सलाह दी थी कि सितंबर, 2022 तक मुफ्त अनाज वाली योजना जारी न रखी जाए, क्योंकि उससे हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था असंतुलित भी हो सकती है, लेकिन कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने योजना को जारी रखने का फैसला किया। मकसद था कि इस दौर में देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोना चाहिए।

ये हैं मुफ्त रेवड़ियां

दरअसल 'मुफ्त रेवड़ियों' में नि:शुल्क बिजली-पानी, इलाज, टीवी, साइकिल, लैपटॉप, स्मार्टफोन, बाइक, साड़ी, मंगलसूत्र, वाशिंग मशीन, प्रेशर कुकर, मुफ्त परिवहन आदि को गिना जा सकता है, जो विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव के मौके पर परोसते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को निशाना बनाते हुए रेवड़ियों की बात नहीं की थी, लेकिन त्वरित प्रतिक्रिया केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी (आप) की तरफ से ही आई है। राजधानी दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 4.01 लाख रुपए है। यह खुद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में कहा है। दिल्ली अर्द्धराज्य है। उसके तमाम मोटे खर्च केंद्र सरकार करती है। दिल्ली सरकार एक बड़ी नगरपालिका है। उसे करीब 70,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, लेकिन उसके अलावा 9500 करोड़ रुपए अनुदान के तौर पर केंद्र सरकार से लिए जाते हैं। ऐसे कथित राज्य को मुफ्त रेवड़ियां बांटने की जरूरत क्या है? शिक्षा, इलाज आदि केंद्र सरकार मुहैया करवा रही है। दरअसल आने वाले वक़्त में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केजरीवाल सरकार की अनियमितताओं के खुलासे करेगा। आप की

पंजाब में सरकार बने चार महीने हुए हैं। पंजाब पर करीब 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, फिर भी राज्य सरकार मुफ्त बिजली, राशन, महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह आदि की रेवड़ियों में जुटी है। पैसा मांगने मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रधानमंत्री के पास चले आते हैं। ऐसी मुफ्तखोरी से जनकल्याण कैसे होगा? राज्य ही दिवालिया हो जाएंगे। सर्वोच्च अदालत ने भी 'रेवड़ियों' की सियासत पर अपनी चिंता और सरोकार जताए हैं, लेकिन फिलहाल दखल देने से इंकार कर दिया है। रेवड़ियों की संस्कृति ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्यों में दिखी है। तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश में मुफ्तखोरी के कई चुनावी वायदे किए गए हैं। उनकी बजटीय स्थितियां हमें ज्यादा नहीं पता हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था तो देशभर की प्रभावित होती है।

कंगाली के कगार पर आधे राज्य

देश में कोरोना महामारी के बाद कई राज्यों ने जनता को सब्सिडी और मुफ्त योजनाओं की रेवड़ियां बांटकर खुद को कंगाली के कगार पर खड़ा कर दिया है। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के बीच अब इन वोट बटोरने वाली योजनाओं पर नई बहस छिड़ गई है। पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, उप्र जैसे कई राज्य कर्ज के मकड़ जाल में फंसे हैं। अगर इन राज्यों को केंद्र मदद न करे तो हालात श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हो सकते हैं। आर्थिक विशेषज्ञ लगातार केंद्र को कृषि और स्वास्थ्य योजनाओं में सब्सिडी धीरे-धीरे कम करने और मुफ्त की योजनाओं पर प्रतिबंध की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि कंठ तक कर्ज में डूबे ये राज्य आय का आधे से ज्यादा हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च कर रहे हैं।

रिजर्व बैंक के मुताबिक पंजाब ने पिछले कुछ साल में केवल 5 फीसदी रकम आर्थिक संसाधन बनाने में खर्च की जबकि 45 फीसदी से अधिक रकम कर्ज की किस्तों में जमा की। आंध्र प्रदेश ने 10 फीसदी रकम आर्थिक संसाधनों पर जबकि 25 फीसदी कर्ज अदायगी में खर्च की। बाकी राज्यों का भी यही हाल है। राज्यों पर औसतन राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 31.3 फीसदी कर्ज है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर उसकी जीएसडीपी का 56.6 फीसदी तो पंजाब पर रिकॉर्ड 53.3 फीसदी कर्ज है। इसके बाद राजस्थान 39.8 फीसदी, पश्चिम बंगाल 38.8 फीसदी, केरल 38.3 फीसदी, आंध्रप्रदेश 37.6 फीसदी कर्ज है। बड़े राज्यों में सिर्फ गुजरात 23 फीसदी और महाराष्ट्र 20 फीसदी कर्ज के साथ

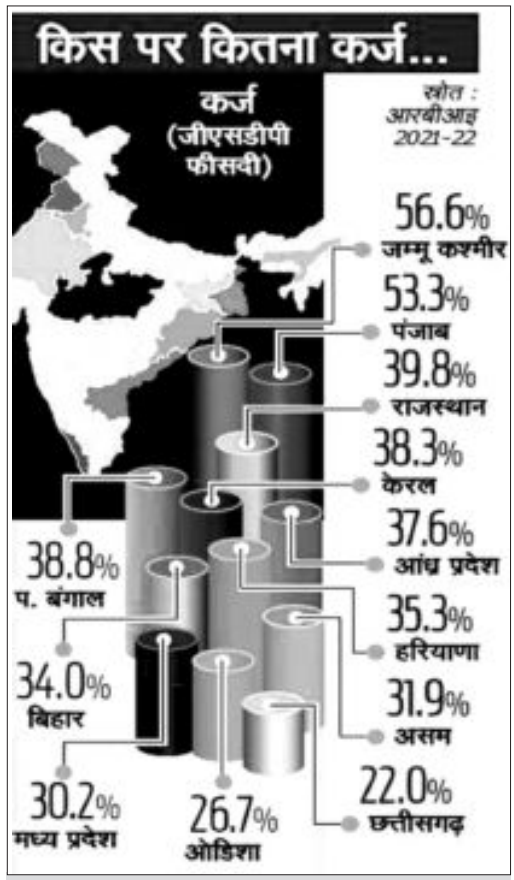

दक्षिण भारत से शुरू होकर पूरे देश में फैला रेवड़ी कल्चर

देश के दक्षिण राज्यों खासकर तमिलनाडु में सबसे पहले मुफ्त बांटने की सियासत शुरू हुई। यहां चुनाव जीतने के लिए मंगलसूत्र, टीवी, प्रेशर कुकर और साड़ी फ्री में बांटी जाने लगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के कार्यकाल में अम्मा कैंटीन खूब फली-फूली। दक्षिण भारत के बाद अब यह उत्तर भारत के साथ-साथ पूरे देश में वोट पाने का एक शॉर्टकट जरिया बन चुका है। वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों ने मुफ्त बिजली-पानी, अनाज, लैपटॉप, मोबाइल, स्कूटी और बेरोजगारी भत्ता को हथियार बनाया। इसका नतीजा ये हुआ कि आज कई राज्यों की अर्थव्यवस्था कर्ज के बोझ तले दबने लगी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी रेवड़ी कल्चर से देश को होने वाले नुकसान को लेकर आगाह कर चुका है। उधर कैग के डेटा के हवाले से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्सिडी पर राज्य सरकारों के खर्च में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिससे कर्ज बढ़ता जा रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 में सब्सिडी पर राज्यों ने कुल खर्च का 11.2 प्रतिशत खर्च किया था। जो 2021-22 में बढ़कर 12.9 प्रतिशत हो गया। सब्सिडी पर सबसे ज्यादा खर्च उप्र, ओडिशा, झारखंड, केरल और तेलंगाना ने किया। वहीं पंजाब, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकार ने सब्सिडी पर अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 10 प्रतिशत से ज्यादा खर्च किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारें सब्सिडी की बजाय मुफ्त दे रहीं हैं। जिससे फ्री पानी, फ्री बिजली, बिल माफी और कर्जमाफी से सरकारों को कोई कमाई नहीं हो रही है। उल्टे सरकार को इस पर खर्च करना पड़ रहा है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) लक्ष्य 20 फीसदी के करीब हैं।

वोटरों को लुभाने से बढ़ा कर्ज

पंजाब में आप ने चुनावी वायदे में हर महिला को 1,000 रुपए महीने और हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने को कहा था। इससे भगवंत मान सरकार पर 17500 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार पड़ेगा। बिजली पर हर साल 5,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसी तरह उप्र में भी मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना पर हजारों करोड़ खर्च होंगे। बिहार, राजस्थान, मप्र और आंध्र प्रदेश का भी यही हाल है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बेहतर टैक्स व्यवस्था ही खुशहाली ला सकती है। जरूरतमंदों तक योजनाएं पहुंचे मगर दुरुपयोग न हो। अमेरिका और यूरोप समेत तमाम देशों में सामाजिक सुरक्षा टैक्स लिया जाता है। चीन में यह 10 तो रूस में 11 फीसदी है। इस रकम से गरीबों की मदद होती है। भारत में भी इससे गरीबों को मदद मिल सकती है। राजस्थान में अब तक की सरकारों ने जितना कर्ज लिया उसका 25 फीसदी गहलोत ने तीन साल में लिया। राज्य पर कुल कर्ज 4 लाख 34 हजार करोड़ से ज्यादा हो चुका है। सरकार सालाना 25 हजार करोड़ रुपए का ब्याज अदा कर रही है। पुरानी पेंशन योजना और मुफ्त बिजली राज्य को और भी भयंकर कर्ज में फंसा सकती है।

उप्र सहित हालिया विधानसभा चुनावों में भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों ने अपना चुनावी अभियान मुख्य रूप से इन्हीं मुफ्त की रेवड़ियों के इर्दगिर्द तक सीमित रखा था। सभी हालिया चुनावी अभियानों में मोदी सरकार ने अपना पूरा ध्यान गरीब कल्याण पर केंद्रित रखा था। गरीब कल्याण के लिए हर उपाय को इस प्रकार बेचा गया कि वह या तो ऐतिहासिक बन गया या दुनिया में सबसे बड़ा। मई में जब सरकार के 8 साल पूरे हो गए, तब मोदी ने एक गरीब कल्याण सम्मेलन में इस पर बात की और एक के बाद एक कल्याणकारी योजनाएं गिनाईं, जो निश्चित रूप से मुफ्त की रेवड़ी की श्रेणी में आती हैं। उनकी सरकार पहले इस शब्दावली का न के बराबर इस्तेमाल करती थी। अपने पहले कार्यकाल (2014-19) के दौरान मोदी ने बदलाव की राजनीति की बात की थी। उन्होंने महत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) की जमकर आलोचना की थी। इसकी आलोचना में उन्होंने कहा था कि भारत के नागरिक गड्ढ़ा खोदने में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उनके लंबे चौड़े भाषणों में गरीब और गरीबी

अमीरों को सबसे अधिक मिलती हैं मुफ्त की रेवड़ियां

देश में इन दिनों आम जनता को दी जाने वाली मुफ्त की रेवडियां चर्चा में हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमीरों यानी औद्योगिक घरानों को मिलने वाली रेवड़ियों की किसी को चिंता नहीं है। भारत की 20 बड़ी कंपनियों के पास भारत की अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल मुनाफे का 70 फीसदी हिस्सा है। साल 1990 में मुनाफे में हिस्सेदारी का यह आंकड़ा महज 14 फीसदी हुआ करता था। यानी 1990 के बाद बड़ी कंपनियों ने संसाधन के हिसाब से उनका हक खूब मारा है, जिनकी संसाधनों तक पहुंच हमेशा से कम ही रही है। इन सबका मतलब यही है कि देश में बड़ी परेशानी मुफ्त में रेवड़ियां बांटना नहीं है, बल्कि बड़ी परेशानी यह है कि आर्थिक नीतियां ऐसी हैं कि संसाधनों का बंटवारा समतामूलक नहीं है। साल 2019 में सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की। कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दी गई थी। जबकि यहां पर भयंकर कमाई होती है। यहां से सरकार को ज्यादा टैक्स वसूलना चाहिए। क्या इस छूट को सरकार द्वारा कॉर्पोरेट को दी जाने वाली रेवड़ी कही जाएगी या नहीं? 2014-15 और 2020-21 के बीच मोदी सरकार ने कॉरपोरेट करदाताओं को 6.15 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न छूट, रियायतें और छूट दी। इसे कर प्रोत्साहन कहा जाता है। इसी तरह बैंकों द्वारा कॉर्पोरेट सेक्टर को दिए गए 10.72 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को बट्टे खाते में डाल दिया गया है। एक मिसाल और लीजिए, बुजुर्गों के रेल टिकट पर उन्हें छूट मिलती थी। सरकार को इस छूट की वजह से 1500 करोड़ के आसपास नहीं मिलता था। सरकार ने इस छूट को बंद कर दिया है। जबकि कोविड महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया का कामकाज बंद था तब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक बीएसई (जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है) में सूचीबद्ध कंपनियों ने 2021-22 में 9.3 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 70 प्रतिशत ज्यादा था। महामारी से पहले यानी 2010-11 और 2019-20 के बीच हर साल के औसत मुनाफे से तकरीबन तीन गुना ज्यादा था। सोचिये इतना मुनाफा इन्होंने कैसे कमाया? क्या सरकारी नीतियों के जरिये रेवड़ियां बांटे बिना यह संभव है? अगर सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर पर ढंग से नियंत्रित करती तो उसे 1500 करोड़ रुपए से कई गुना राजस्व इकट्ठा होता।

शब्द मुश्किल से जगह बना पाते थे। लेकिन बाद में हर राज्य में विधानसभा चुनावों और 2019 में आम चुनावों से पहले उन्होंने एलपीजी में सब्सिडी और किसानों के लिए नगद भुगतान के लिए योजना की घोषणा कर दी। महामारी के दौरान उन्होंने मुफ्त राशन की योजना लागू की और कोविड-19 के टीकाकरण को मुख्य कल्याणकारी कदम बताया और इसे विश्व के सबसे बड़े मुफ्त टीकाकरण अभियान की संज्ञा दी। मोदी को कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए धन्यवाद देने के लिए केंद्र सरकार ने कई कार्यक्रम भी चलाए।

पहले तमिलनाडु तक सीमित

एक समय ऐसा था जब लोक लुभावन घोषणाएं कर मुफ्त चीजें देने के वादे तमिलनाडु तक ही सीमित थे, लेकिन अब यही काम देशभर में राजनीतिक दल करने में लग गए हैं। जब एक दल मुफ्त चीजें देने की घोषणा करता है तो दूसरे दल भी ऐसा करने से नहीं चूकते और वे भी ऐसी घोषणाएं करने के लिए विवश हो जाते हैं। चुनावों की तारीख आते ही राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं। इन दलों की ओर से जनता के सामने लोक लुभावन वादे किए जाते हैं। ऐसे वादों पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ताकि मुफ्तखोरी पर अंकुश लगे। ऐसा करने की अनुमति राजनीतिक दलों को नहीं दी जानी चाहिए। एक समय वो था जब लोक लुभावन घोषणाओं के तहत मुफ्त चीजें देने के वादे तमिलनाडु तक सीमित थे। देश में इन दिनों ऐसा ही हो रहा है। हाल ही में गोवा, पंजाब, मणिपुर से लेकर उप्र और उत्तराखंड में कोई दल मुफ्त बिजली देने का वादा कर रहा था तो कोई मोबाइल-लैपटाप बांटने की बातें कर रहा था। किसानों का मामला इन दिनों काफी चर्चा में है। इसलिए राजनीतिक दलों की ओर से उनके कर्ज माफ करने की भी घोषणाएं की जाती हैं। ऐसे में लोक लुभावन वादे करने की राजनीति बेलगाम होती जा रही है। हालात तो यहां तक आ गए हैं कि अब नकद राशि देने के भी वादे किए जा रहे हैं। यह एक तरह से मतदाताओं के वोट खरीदने की कोशिश है। चुनावों के दौरान पैसे और शराब बांटने का सिलसिला पहले से ही कायम है। यह तथ्य है कि चुनावों के दौरान उस पैसे की बड़े पैमाने पर बरामदगी होने लगी है, जो मतदाताओं के बीच चोरी-छिपे बांटने के लिए एकत्र किया जाता है। चुनावों में राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली घोषणाओं का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो उसने यह पाया था कि साड़ी, मिक्सी, मोबाइल, टीवी आदि मुफ्त देने की घोषणाओं से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की बुनियाद ही ध्वस्त हो जाती है। सच तो यह है कि ऐसी घोषणाएं अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने का काम करती हैं। जब कोविड महामारी के चलते राज्यों की आर्थिक स्थिति पहले से ही खस्ताहाल है तब फिर राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना आवश्यक हो जाता है। बेहतर होगा कि निर्वाचन आयोग ऐसे कोई दिशा-निर्देश जारी करे, जिससे राजनीतिक दलों की मनमानी घोषणाओं पर लगाम लगे। क्योंकि इससे मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। यह समझा जाना चाहिए कि इस संस्कृति को बढ़ावा देकर कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता।

न टिकाऊ न जिताऊ

यदि मतदाता बुद्धिमान और शिक्षित हैं, तो वे इस तरह की चालों के झांसे में नहीं आएंगे। मुफ्त उपहार स्वीकार करने के बाद भी, वे सरकार के प्रदर्शन या उसकी कमी के अनुसार मतदान करना चुन सकते हैं। यदि वे मुफ्त उपहारों और वादों को अस्वीकार करते हैं, तो राजनीतिक दल अधिक रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए आगे बढ़ेंगे। अस्वीकृति की शुरुआत पंचायत राज और राज्य विधानसभा चुनावों से होनी चाहिए।

मतदाताओं के केवल एक निश्चित वर्ग के लिए किसी विशेष क्षेत्र में सब्सिडी चुनाव में जीत का आश्वासन नहीं दे सकती है। श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था के पतन की हालिया खबरों ने राज्य की भूमिका पर एक नई बहस को जन्म दिया है। श्रीलंका की सरकार ने बोर्ड भर में करों में कटौती की और कई मुफ्त सामान और सेवाएं प्रदान कीं। नतीजतन, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई और सरकार गिर गई। संभावित मतदाताओं को मुफ्त उपहार देने या देने का वादा करने वाली राजनीतिक पार्टियां न तो बहुत पुरानी हैं और न ही बहुत नई घटना हैं। लेकिन, पिछले 10 वर्षों में इस प्रथा का विस्तार होता दिख रहा है। आमतौर पर वितरित किए जाने वाले मुफ्त में साइकिल, स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप और बिलों पर छूट (पानी, बिजली, आदि) जैसे सामान शामिल हैं। सत्ता में पार्टियों द्वारा मुफ्त में बांटे जाते हैं और विपक्षी दलों द्वारा वादा किया जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी के मुफ्त की रेवड़ी भाषण के बाद ये गंभीर विषय जोर-शोर से चर्चा में है, आजकल हमारे देश में हर पार्टी के द्वारा मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खासकर युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों से मुफ्त उपहार भारत में राजनीति का एक अभिन्न अंग बन गए हैं, चाहे चुनावी लड़ाई में वादे करने के लिए हो या सत्ता में बने रहने के लिए मुफ्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए।

रेवड़ी की राजनीति कैसे खत्म होगी?

भारतीय राजनीति की कुछ बीमारियां लाइलाज हैं। रेवड़ी बांटने की राजनीति उन्हीं में से एक है। यह बीमारी तभी से है, जब से चुनाव होते हैं और सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि किसी न किसी रूप में दुनिया के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में है। भारत में जब इस पर बहस शुरू हुई है तो कुछ विद्वान लोग बताने लगे हैं कि विचारधारात्मक राजनीति के कमजोर होने के बाद रेवड़ी बांटने की राजनीति बढ़ी है। असल में ऐसा नहीं है। जब कथित तौर पर विचाराधारात्मक राजनीति बहुत मजबूत थी और पार्टियां सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करती व चुनाव लड़ती थीं तब भी रेवड़ी बांटने की राजनीति होती थी। फर्क यह है कि तब रेवड़ी बांटने की राजनीति को एक मजबूत सैद्धांतिक आधार दिया जाता था और आज सीधे मतदाता को रिश्वत देने के अंदाज में रेवड़ी बांटी जा रही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सैद्धांतिक आधार के साथ रेवड़ी बांटना ठीक हो और रिश्वत देने के अंदाज में रेवड़ी बांटना गलत हो?

सवाल है कि रेवड़ी बांटने की राजनीति क्यों शुरू हुई और क्यों अभी तक जारी है? इस सवाल के जवाब में ही यह निष्कर्ष छिपा है कि भारत में रेवड़ी की राजनीति कभी खत्म नहीं होगी। आजादी के बाद रेवड़ी बांटने की शुरुआत देश के सामाजिक और ऐतिहासिक हालातों की वजह से हुई। सदियों तक गुलाम रहे देश में बड़ी आबादी बुनियादी सुविधाओं से वंचित थी। इसलिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था करने से लेकर मुफ्त राशन बांटने तक की शुरुआत हुई। तब भारत में अन्न का अकाल था। भारत 'शिप टू माउथ' वाला देश था। दुनिया के दूसरे देशों से जहाज पर लद कर अनाज आता था तब लोगों का पेट भरता था। ऐसे देश में अगर सरकार कमजोर व वंचित वर्गों के लिए एफरमेटिव एक्शन नहीं लेती तो अराजकता के हालात बन सकते थे। अफसोस की बात है कि समय के साथ खत्म होने की बजाय एफरमेटिव एक्शन वाली राजनीति मजबूत होती चली गई। भारत अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया और दुनिया की पांचवीं-छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया फिर भी एफरमेटिव एक्शन की जरूरत बनी रही या बनाए रखी गई।

आजादी के बाद जितने भी समय आधारित कानून बनाए गए या एफरमेटिव एक्शन लिए गए वे सब आज भी जस के तस चल रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद भी आरक्षण की व्यवस्था न सिर्फ कायम है, बल्कि इसकी मांग और बढ़ गई है। अनाज के मामले में देश के आत्मनिर्भर हो जाने के पांच दशक बाद भी देश की 70 फीसदी के करीब आबादी सरकार की ओर से दिए जा रहे मुफ्त अनाज पर निर्भर है।

इसलिए देश में ऐसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए जिससे जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले। अगर सरकार यह सुनिश्चित कर दे कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिल जाएगा, तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वालों पर भी लगाम लग जाएगी। दरअसल, देश की बड़ी आबादी अभी भी सुविधाविहीन है। बेरोजगारी और गरीबी के कारण लोग मुफ्त की चीजों की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा उठाती हैं और अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटती हैं। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और सरकार को इस दिशा में एकीकृत होकर काम करने की जरूरत है। तभी मुफ्त की रेवड़ियों पर अंकुश लग पाएगा। वरना सरकारें वोट के लिए इसी तरह खजाना उड़ाती रहेंगी और उसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

रेवड़ी कल्चर के साइड इफेक्ट

रेवड़ी कल्चर से जहां राज्यों की आर्थिक सेहत पर बुरा असर हो रहा है। तो वहीं दूसरे स्तर पर भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। पंजाब में साल 1971 में सिर्फ 1,92,000 ट्यूबवेल थे। लेकिन बिजली बिल में माफी और सब्सिडी मिलने से इसकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। आज यहां ट्यूबवेल की संख्या 14.1 लाख तक पहुंच गई है। इससे भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। आलम यह है कि अधिक दोहन के चलते भूजल 20 से 30 मीटर नीचे चला गया है। जिससे पंजाब बहुत बड़े जलसंकट की ओर बढ़ रहा है। आरबीआई के मुताबिक सभी राज्य सरकारों पर मार्च 2021 तक करीब 69.47 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। फिलहाल तमिलनाडु पर 6.59 लाख करोड़, उप्र पर 6.53 लाख करोड़, महाराष्ट्र पर 6.08 लाख करोड़, पश्चिम बंगाल पर 5.62 लाख करोड़, राजस्थान पर 4.77 लाख करोड़, गुजरात पर 4.02 लाख करोड़ और आंध्र प्रदेश पर 3.98 लाख करोड़ का कर्ज है। पंजाब और राजस्थान में चुनावी साल में सियासी दलों की ओर से जमकर रेवड़ियां बांटी गईं। जिससे दोनों ही राज्य आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़े हो गए हैं।

द्रौपदी मुर्मू का नाम भले ही बहुत लोगों को नया लगे किंतु शासन और प्रशासन से भली-भांति परिचित है मुर्मू और जमीनी भारत की समस्यायों को इन्होंने खुद देखा है, झेला है और कुछ हद तक सुलझाया भी होगा। हालांकि राष्ट्रपति के अधिकार भारतीय राजनीति के परिपेक्ष्य में सीमित हैं। किंतु फिर भी एक उम्मीद जगती है कि इतने लंबे राजनितिक सफर में तय किए हुए तमाम मील के पत्थर द्रौपदी मुर्मू के जीवन का हासिल है। जिसे वो यकीनन स्त्री और शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग में ला सकती हैं। फिलहाल ये एक बड़ा कदम है जो भारत के इतिहास की तारीख में दर्ज हो गया है।

जुझारू व्यक्तित्व की द्रौपदी मुर्मू

द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के लिए जिस दिन से ये नाम आया लोगों ने ढूंढकर उनके बारे में पढ़ा, प्रेरित हुए और खुशी हुई की एक बार फिर महिला राष्ट्रपति भारत की राजनीति का हिस्सा बनेगी। हालांकि आज के भारत की राजनीति पूरी तरह से शतरंज की बिसात है। अब आप उसमें चलने वाले प्यादे हैं या बाहर से देखकर समझने वाले दर्शक ये आप पर निर्भर हैं। सभी नामों को ठोंक बजाकर देखने के बाद द्रौपदी मुर्मू का नाम उनके व्यक्तित्व की तरह ही मजबूत निकला। जीतना पहले दिन से तय था। स्त्री, आदिवासी और सेल्फ मेड यानि कि अपने दम पर अपनी जीवन में मुकाम हासिल करने वाला जुझारू व्यक्तित्व। यकीनन द्रौपदी मुर्मू का चुनाव शत-प्रतिशत सही और गरिमा के अनुरूप है। एक शिक्षिका जो अपने इलाके की पहली ग्रेजुएट थी और जिन्होंने अपनी जीवन की तमाम दुश्वारियों के बाद भी शिक्षा के प्रति अपने समर्पण को कम नहीं होने दिया।

उनके निजी जीवन के दुखों को रेखांकित न करते हुए मात्र उनकी हिम्मत और जिजीविषा की बात करें तो हम पाएंगे कि जिस स्त्री शक्ति की हम बात करते हैं मुर्मू उसका जीता जगता उदाहरण है। हालांकि एक स्त्री के उच्च पद पर पहुंचने पर मनाई जाने वाली कुछ अधिक खुशी इस बात का द्योतक है कि अभी स्त्रियां बराबरी से कहीं दूर हैं इसलिए ऐसी कोई भी उपलब्धि, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग वाला एहसास देता है।

हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के गांव तक सड़क बन गई है और यकीनन रंगरोगन भी नया हुआ होगा। मयूरभंज के जिस इलाके को हम राष्ट्रपति के घर के रूप में देखकर गौरवान्वित होने की प्रक्रिया में हैं, उस प्रक्रिया में इस इलाके के हालिया सालों के हालात टाट में पैबंद लगते हैं। ये इलाका भारत के सबसे पिछड़े प्रदेशों में से एक है और आज भी कुछ बरसाती नदियों-नालों को पार करने को बांस के पुल बने हैं और नन्हें बच्चे और बुजुर्ग उसी पर जाने-आने को मजबूर हैं। अपनी निजी जीवन की त्रासदियों को दरकिनार कर अपने घर को ही पाठशाला में बदलने वाली मुर्मू शिक्षा के प्रति यकीनन बहुत सजग और समर्पित हैं। किंतु इनका कर्मक्षेत्र अपने ही देश के इलाकों के प्रति पिछली सरकारों की उदासीनता को दर्शाता है। आखिर क्या वजह रही कि खनिज संपदा से भरपूर राज्य में सबसे गरीब इलाके हैं।

द्रौपदी मुर्मू का नाम भले ही बहुत लोगों को नया लगे किंतु द्रौपदी मुर्मू 1997 में ओडिशा के रायरंगपुर जिले से पहली बार जिला पार्षद चुनी गई थीं। साथ ही यह रायरंगपुर की उपाध्यक्ष भी बनीं। इसके अलावा साल 2002 से लेकर के साल 2009 तक मयूरभंज जिला भाजपा का अध्यक्ष बनने का मौका भी मिला। साल 2004 में यह रायरंगपुर विधानसभा से विधायक बनने में भी कामयाब हुईं और आगे बढ़ते-बढ़ते साल 2015 में इन्हें झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य के राज्यपाल के पद को संभालने का भी मौका मिला। शासन और प्रशासन से भली भांति परिचित हैं मुर्मू और जमीनी भारत की समस्यायों को इन्होंने खुद देखा है, झेला है और कुछ हद तक सुलझाया भी होगा।

द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आना इसलिए भी खास था क्योंकि कहीं न कहीं एक तीर से दो निशाने लगे हैं। आदिवासी इलाकों से उच्च पद पर आसीन होने वाली पहली महिला बनी हैं और इससे महिलाओं को सक्रिय राजनीति में लाने का भाजपा का संकल्प भी दिखाई देता है। हालांकि राष्ट्रपति के अधिकार भारतीय राजनीति के परिपेक्ष्य में सीमित हैं। किंतु फिर भी एक उम्मीद जगती है कि इतने लंबे राजनीतिक सफर में तय किए हुए तमाम मील के पत्थर द्रौपदी मुर्मू के जीवन का हासिल है। जिसे वो यकीनन स्त्री और शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग में ला सकती हैं।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

स्त्री सशक्तिकरण का परचम

द्रौपदी मुर्मू का नाम जब भारत के किसी गांव में बैठी कोई बच्ची राष्ट्रपति के रूप में पढ़ेगी तो उसकी आंखों में भी मेहनत और सफलता के सपने जागेंगे। अब इस सफलता से जमीनी तौर पर भी कोई बदलाव आएगा या नहीं ये देखना होगा। आने वाला वक्त बताएगा ही कि क्या द्रौपदी मुर्मू नाममात्र को स्त्री सशक्तिकरण का नाम बनेंगी या इस पद पर भी अपने व्यक्तित्व की अलग छाप छोड़ जाएंगी। फिलहाल ये एक बड़ा कदम है जो भारत के इतिहास की तारीख में दर्ज हो गया है। देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिल चुकी है। आजादी के 75वें साल के अमृत महोत्सव पर यह उपलब्धि गांधी को उनकी विचारधारा के विपरीत खड़ी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि स्वरूप है। ऐसा इसलिए क्योंकि गांधी को राष्ट्रपति जैसे पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को देखने की इच्छा थी। भारतीय राष्ट्रपति के इतिहास में द्रौपदी मुर्मू आजाद भारत (1958) में उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव के संथाल परिवार में बिरंची नारायण टुडू (पिता) के यहां जन्मी पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी शायद ही किसी ने सोचा होगा।

कांग्रेस की राह आसान नहीं

2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अभी से तैयारी शुरु कर दी है। कांग्रेस की कोशिश है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वह भाजपा के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरे, लेकिन पार्टी के हालात देखकर साफ लग रहा है कि कांग्रेस के लिए आगे की राह आसान नहीं है।

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के हाथों से लगातार सत्ता खिसकती जा रही है। पंजाब की हार के साथ कांग्रेस के पास सिर्फ 2 राज्य बचे हैं। इसके अलावा 2 राज्यों में सहयोगी के रूप में सरकार है। लगातार 2 आम चुनावों में अपमानजनक पराजय और साल 2022 की शुरुआत में देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद आपसी झगड़ा और असंतोष लगभग सभी राज्य इकाइयों में पनप रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र, गोवा के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस में आपसी गुटबाजी के कारण 3 वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। यही नहीं आने वाले राज्यों में जहां-जहां चुनाव हैं, वहां कांग्रेस आपसी गुटबाजी से जूझ रही है।

हिमाचल विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत में होने हैं। हिमाचल में बीते 2 दशक से भाजपा और कांग्रेस ने बारी-बारी से सरकार चलाई है। लेकिन, इस बार भाजपा, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी पूरे जोर-शोर से चुनाव तैयारियों में जुट गई हैं। कायदे से तो इस बार हिमाचल में कांग्रेस की बारी है लेकिन मौजूदा हालात को देखकर यही लगता है कि इस बार भाजपा को सत्ता से हटा पाना आसान नहीं है। इसका मुख्य कारण प्रदेश कांग्रेस के भीतर आपसी गुटबाजी का माहौल चरम पर होना है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई। जिससे उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गईं। लेकिन, आनंद शर्मा ने इस बात का खंडन किया। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी गुटबाजी से बाहर निकलती नजर नहीं आ रही है। इससे चुनावी तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। अब तो पार्टी में फूट का खतरा भी लग रहा है।

इस साल गुजरात में भी चुनाव होना है। यहां कांग्रेस पिछले 27 साल से भाजपा को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन, यहां भी कांग्रेस आपसी कलह से लड़ रही है। जिस कारण कई नेता पार्टी छोड़ अन्य दलों का दामन थाम रहे हैं। इसका हालिया उदाहरण पटेल समुदाय के बड़े नेता हार्दिक पटेल का भाजपा में शामिल होना है। ऐसे में यहां पार्टी को एकजुट रखना भी एक चुनौती है।

भाजपा के खिलाफ कांग्रेस की मुहिम

कांग्रेस भी भाजपा के खिलाफ ताबड़तोड़ आक्रामक मुहिम चला रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को लेकर भी कांग्रेस हमलावर है और उदयपुर में हुई हत्या के आरोपियों के भाजपा नेताओं के साथ हाथ लगी तस्वीरों के जरिए भी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना काम तो कर ही दिया था, उदयपुर में कन्हैयालाल साहू के हत्यारों को फौरन गिरफ्तार करके। लिहाजा अब वे भाजपा के खिलाफ खुलकर खेलने लगे हैं। अशोक गहलोत कहते हैं कि उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के आरोपियों की भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आई हैं और पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। ये एनआईए के लिए भी जांच का विषय है कि किस हद तक उनका कनेक्शन था, कितना कर्मठ कार्यकर्ता था? एक पुराने मामले का जिक्र कर अशोक गहलोत किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं जब थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो रहा था तभी किसी भाजपा नेता का फोन आ गया। कोई भाजपा नेता थे। पुलिस से कहने लगे- ये हमारे कार्यकर्ता हैं, तंग मत करो। फिर सवाल उठाते हुए अशोक गहलोत कहते हैं, मतलब, वो उनके संपर्क में रहा... कितना संपर्क में रहा है? किस हद तक उनकी दोस्ती थी? सदस्यता थी? कितना कर्मठ उनका कार्यकर्ता था? किस रूप में था? ये तो एनआईए ही पता लगा सकती है।

कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन, पार्टी सिद्धारमैया बनाम डीके शिवकुमार खेमे में बंटी है। पार्टी के दो बड़े नेता एक-दूसरे के आमना-सामने आ चुके हैं। साथ ही पार्टी के भीतर गुटबाजी भी बढ़ती जा रही है। इस स्थिति में आगामी चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को हराना और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। 15 साल से जमी भाजपा की सरकार को हटाकर कांग्रेस पूरे बहुमत से सत्ता में आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव गुट के बीच आपसी विवाद की खबरें सामने आती रहती हैं। ये आपसी विवाद दिल्ली दरबार तक भी पहुंचा था। हालांकि, कांग्रेस आलाकमान दोनों नेताओं में सुलह कराने में कामयाब दिख रहा है। फिर भी जब-तब दोनों के बीच अनबन की खबरें आती ही रहती हैं।

राजस्थान में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव के लिहाज से राजस्थान कांग्रेस के लिए बेहद अहम राज्य है। राजस्थान में तो कांग्रेस लंबे वक्त से जबरदस्त गुटबाजी का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री पद की चाहत रखने वाले सचिन पायलट तो एक बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर निकल भी चुके थे। लेकिन, कांग्रेस आलाकमान ने किसी तरह इसे रोका और राजस्थान में मप्र की कहानी दोहराए जाने से बचा लिया। लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तंज भरे बयानों से ऐसा नहीं लगता है और दोनों के बीच सत्ता को लेकर वर्चस्व का जिन्न रह-रहकर बाहर निकल ही आता है।

चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की लगातार हार से पार्टी में शीर्ष नेतृत्व के प्रति असंतोष भी बढ़ रहा है। पार्टी के कई बड़े नेता कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लेकर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठा चुके हैं। जिन्हे जी-23 का नाम मिला है। इनमें गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा जैसे बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। जो अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को खत लिखकर शीर्ष नेतृत्व की कार्यशैली और संगठन चुनाव में देरी की आलोचना भी कर चुके हैं। आने वाला समय चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि, इस दौरान कई राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मप्र

तीस्ता पर निगाहें, सोनिया पर निशाना

भाजपा की तरफ से सोनिया गांधी पर हमले के लिए तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर आई एसआईटी की रिपोर्ट को उछाला जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता लगे हाथ यूपीए सरकार के दौरान तीस्ता सीतलवाड़ को मिले पद्मश्री पुरस्कार की भी बार-बार याद दिला रहे हैं। गुजरात सरकार की एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि तीस्ता सीतलवाड़ असल में राजनीति में आना चाहती थीं। एसआईटी ने ये दावा एक गवाह के हवाले से किया है। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक, तीस्ता सीतलवाड़ ने एक नेता से कहा था कि अगर शबाना आजमी और जावेद अख्तर को राज्यसभा सांसद बनाया जा सकता है तो मुझे क्यों नहीं? रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि तीस्ता सीतलवाड़ तब कांग्रेस नेता रहे अहमद पटेल के साथ मिलकर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने के लिए साजिश रच रही थीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बाकायदा बयान जारी कर ऐसे आरोपों का पूरी तरह खंडन किया है। साथ ही 2002 के गुजरात दंगों की याद दिलाते हुए, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से मोदी को राजधर्म की याद दिलाए जाने का भी खासतौर पर जिक्र किया है। जयराम रमेश का कहना है, हम जानते हैं कि कैसे एक पूर्व एसआईटी प्रमुख को मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देने के बाद पुरस्कृत किया गया था।

और कर्नाटक जैसे कई अहम राज्य हैं। इसके अलावा 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। कांग्रेस आपसी अंतर्कलह और गुटबाजी के कारण ही हर राज्य में अपना वजूद खोती जा रही है। अगर समय रहते कठोर कदम नहीं उठाया तो कांग्रेस का भगवान ही मालिक है।

देश की राजनीति में हाल फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है, बेशक नजर 2024 के आम चुनाव पर होगी, लेकिन अभी सभी का सारा फोकस मानसून सेशन पर ही लगता है। आने वाले विधानसभा चुनाव भी रणनीति का निश्चित तौर पर हिस्सा होंगे, लेकिन कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि कैसे केंद्र में सत्ताधारी भाजपा को संसद के मानसून सेशन में कठघरे में खड़ा किया जाए? और भाजपा कांग्रेस की ऐसी हर कोशिश को पहले ही खत्म कर देना चाहती है। वैसे तो ये लड़ाई सीधे-सीधे सत्तापक्ष और विपक्ष की है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लेकिन चीजें उतनी सीधी और सरल भी तो नहीं हैं। सत्तापक्ष में भाजपा के साथ एनडीए के साथी भी हैं। कुछ घोषित तौर पर साथ न रहते हुए भी साथ खड़े रहते हैं और द्रौपदी मुर्मू के मैदान में आ जाने के बाद तो ये घालमेल और भी ज्यादा बढ़ गया है। विपक्षी खेमे में सूत्रधार तो कांग्रेस ही रहती है, या बने रहने की कोशिश रहती है। कभी ममता बनर्जी तो कभी शरद पवार और अभी केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव भी वैसी ही भूमिका में खुद को पेश करने की कोशिश करते आ रहे हैं।

अब तक तो यही देखने को मिला है कि विपक्ष के लिए एकजुट होना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव प्रत्यक्ष उदाहरण है। विपक्ष ने उम्मीदवार तो एक ही खड़ा किया, लेकिन धीरे-धीरे ज्यादातर भाजपा की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सपोर्ट में जा खड़े हुए। और आखिरकार मुर्मू ही राष्ट्रपति बन गईं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने संसद के मानसून सत्र में सभी विपक्षी दलों को एकमंच पर आकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने की अपील की है। केसीआर ने इसके लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, एनसीपी नेता शरद पवार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव सहित विपक्षी दलों के और भी नेताओं से बात की है। लेकिन मोटे तौर पर देखें तो आखिरकार ये लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा ही समझ में आती है। मतलब, सोनिया गांधी बनाम नरेंद्र मोदी कांग्रेस की तरफ से भाजपा को घेरने की तरह-तरह से कोशिशें हो रही हैं और भाजपा की तरफ से उसका काउंटर या एहतियाती अटैक किए जा रहे हैं। लड़ाई में जिसे जो मुद्दा तगड़ा समझ में आ रहा है, खुलकर उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस डॉलर के मुकाबले रुपए की ताजा स्थिति पर सोशल मीडिया कैंपेन चला रही है, तो भाजपा के लिए थर्ड पार्टियां ऐसे हमलों को न्यूट्रलाइज करने में मददगार बन रही हैं। हामिद अंसारी से लेकर तीस्ता सीतलवाड़ के मामले मिसाल ही तो हैं।

थर्ड पार्टी कोई एक नहीं है। ये एक समूह बन गया है। जैसे पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के केस में वो पाकिस्तानी पत्रकार और तीस्ता सीतलवाड़ या गांधी परिवार से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के मामले में अदालतों के आदेश। सोनिया गांधी भाजपा के निशाने पर हैं ताकि मानसून सेशन में कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने से परहेज करे! भाजपा इन थर्ड पार्टी राजनीतिक कवच के तौर पर इस्तेमाल करने लगी है। सबकी अपनी-अपनी और महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ भाजपा ऐसा कर रही है, कांग्रेस की तरफ से भी वैसा ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये तो राजनीतिक कौशल की बात है कि कौन किस चीज का कितने असरदार तरीके से इस्तेमाल कर सकता है?

एक पाकिस्तानी कॉलमनिस्ट के दावे के चलते पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। हालांकि, पाकिस्तानी पत्रकार खुद भी सवालों के घेरे में रहा है, लेकिन राजनीति में तो ये सब करने के लिए बस छौंका लगाने की जरूरत होती है। पाकिस्तानी पत्रकार की भूमिका का राजनीतिक इस्तेमाल हो जाता है। बाकी बहस अलग से होती रहेगी। देखा जाए तो भाजपा के निशाने पर हामिद अंसारी लगते जरूर हैं, लेकिन असली टारगेट तो सोनिया गांधी हैं। तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में भी बिलकुल ऐसा ही है। और एसआईटी के हलफनामे से आरोपों को मजबूत करने के लिए अहमद पटेल का नाम भी मिल गया है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन टूल्स के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस, भाजपा पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम भी नहीं लगा सकती। तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ एसआईटी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय भी अदालत के आदेश पर ही जांच कर रहा है। राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है। सोनिया गांधी से अभी पूछताछ चल रही है। जाहिर है जांच पड़ताल के बाद ईडी की तरफ से रिपोर्ट कोर्ट में दिए ही जाएंगे और उससे निकलकर जो आएगा उस पर भी राजनीति वैसे ही होगी जैसे तीस्ता के मामले में गुजरात एसआईटी की रिपोर्ट पर हो रहा है।

● **विपिन कंधारी**

दक्षिण फतह का नया प्लान!

पूरब, पश्चिम और उत्तर में भगवा लहराने के बाद अब भाजपा का पूरा फोकस दक्षिण की ओर है। पार्टी ने आगामी लोकसभा के साथ ही दक्षिण भारत के राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपना पूरा फोकस दक्षिण की ओर कर दिया है। इसके लिए पार्टी के रणनीतिकार दक्षिणी राज्यों में सक्रिय हो गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दक्षिण फतह के अभियान में जुटे हुए हैं।

2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले विधानसभा के चुनावों में भाजपा ने दक्षिण भारत फतह करने के लिए एक नया प्लान बनाया है। कहने को तो इस प्लान में भाजपा के कई कद्दावर नेता शामिल हैं। लेकिन दक्षिण जीतने की पूरी जिम्मेदारी गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फिलहाल शुरुआती चरण में कुछ बड़े नेताओं को सौंपी है। योजना के मुताबिक संसद के मानसून सत्र के खत्म होने के बाद शाह और नड्डा की जोड़ी दक्षिण भारत के कुछ बड़े राज्यों की राजधानी को अपना ठिकाना बनाने वाली है। बकायदा इसके लिए भाजपा ने अपने कुछ शुरुआती चुनिंदा नेताओं की सूची तैयार कर उन्हें दक्षिण फतह करने के काम पर लगा दिया है।

हैदराबाद में ही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद दक्षिण भारत को जीतने के लिए जो प्लान तैयार किया गया था, उसे अब अमल में लाया जाना शुरू कर दिया गया है। भाजपा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पार्टी के नेताओं का एक बड़ा तबका दक्षिण में जाकर अपनी पैठ बनाना शुरू भी कर चुका है। लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके दूसरे संगठन दक्षिण भारत में मजबूती से आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु में भगवा फहराने के लिए ग्राउंड लेवल पर लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए बकायदा संघ के प्रचारक रहे और बाद में संगठन में अहम पद पर आकर न सिर्फ उप्र बल्कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में भाजपा को मजबूत करने वाले शिवप्रकाश पर पार्टी ने बड़ा दांव लगाया है।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि भाजपा के पास ऐसे कई कद्दावर नाम हैं जो चर्चा में तो नहीं रहते हैं, लेकिन उनका जमीनी काम और लोगों से नेटवर्क इतना मजबूत रहता है कि जब तक कोई बड़े चुनाव आते हैं तब तक ये बगैर चर्चा में रहने वाले नाम चुनाव की जीत की आधारशिला तैयार कर चुके होते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक दक्षिण भारत में भी भाजपा ने ऐसे ही अपने कई मजबूत नेटवर्क वाले जमीनी नेताओं को दक्षिण भारत की ओर रवाना कर दिया है। पार्टी से जुड़े एक कद्दावर नेता कहते हैं कि संगठन के मजबूत स्तंभ में से एक शिवप्रकाश को दक्षिण भारत में भगवा लहराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल शिवप्रकाश ने आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में अपना राजनीतिक ठिकाना बना लिया है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में उन्हें दक्षिण भारत में मजबूती से किला फतह कर दिल्ली वापस आना है और यही वजह है कि पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक सभी वरिष्ठ पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता तक अपना पूरा फोकस दक्षिण भारत पर केंद्रित कर चुके हैं। भाजपा ने तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और आंध्रप्रदेश के पार्टी प्रदेश अध्यक्षों को मजबूती के साथ संगठन को आगे बढ़ाने का पूरा रोडमैप तैयार करके दे दिया है। तमिलनाडु भाजपा के 38 वर्षीय प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी के. अन्नामलाई कहते हैं कि

बस मानसून सत्र के खत्म होने का इंतजार

भाजपा के रणनीतिकारों की टीम में शामिल एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि दक्षिण भारत में उठाए जाने वाले हर भाजपा के राजनीतिक कदम को लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा से चर्चा होती है। उसके बाद में ही सभी फैसले लिए जाते हैं और टीम को काम पर लगाया जाता है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा आलाकमान ने तय किया है कि संसद के मानसून सत्र के बाद भाजपा का एक बड़ा दल दक्षिण भारत में डेरा जमा देगा। नेताओं का यह पूरा दल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के बाद तक केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में डेरा जमाए रहेगा।

मोदी-शाह और नड्डा के नेतृत्व में भाजपा दक्षिण भारत के राज्यों में न सिर्फ लोकसभा के चुनावों में विजयी पताका फहराएगी, बल्कि दक्षिण के राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनावों में भी आने वाले परिणाम आपको बता देंगे कि 2024 का चुनाव कैसा रहने वाला है।

अन्नामलाई दावा करते हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में 25 लोकसभा सीटें उनकी पार्टी यहां से जीतेगी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में शामिल एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि उनकी पार्टी ने के अन्नामलाई जैसे युवा और प्रतिभाशाली पूर्व आईपीएस अधिकारी को अगर राज्य इकाई की कमान सौंपी है तो कुछ सोच समझकर ही ऐसा फैसला लिया गया होगा। सूत्रों का कहना है कि भाजपा दक्षिण भारत में युवाओं के बड़े चेहरों के साथ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में विजय पताका फहराने की तैयारी में लगी हुई है।

भाजपा से जुड़े नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी शुरुआती दौर से जिन राज्यों में अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाती रही है, वहीं से 2024 के लोकसभा चुनावों में वह अपना गैप पूरा करने वाले हैं। पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता बताते हैं कि 2019 में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें हासिल की, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा और विधानसभा के चुनावों में आए परिणाम इस बात की तस्दीक करते हैं कि उनकी पार्टी कितनी मजबूती से पश्चिम बंगाल में उभरी है। वह कहते हैं इसी तरीके से उड़ीसा में भी 21 में से 8 सीटें भाजपा ने जीतीं। जबकि तेलंगाना में 4 सीटें जीतकर भाजपा ने दक्षिण में मजबूती से कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए।

बीते दिनों हैदराबाद में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस आयोजन के लिए हैदराबाद के चयन का निर्णय सुविचारित एवं रणनीतिक कदम था। बैठक से पहले प्रमुख भाजपा नेताओं ने तेलंगाना में डेरा डालकर संपर्क अभियान भी चलाया। फिर कार्यकारिणी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को 'भाग्यनगर' के रूप में संबोधित करने के साथ ही मुस्लिमों के पसमांदा समूह के बीच पैठ बनाने का संदेश भी दिया। इस सबके अलावा हाल में केंद्र सरकार ने उड़नपरी पीटी उषा, सुर सम्राट इलैयाराजा, बाहुबली जैसी फिल्म के लेखक के. विजयेंद्र प्रसाद और समाजसेवी वीरेंद्र हेगड़े को मनोनयन के माध्यम से राज्यसभा भेजने का फैसला किया। इनकी जड़ों की पड़ताल करें तो उषा केरल से, इलैयाराजा तमिलनाडु, विजयेंद्र प्रसाद आंध्र और हेगड़े कर्नाटक से आते हैं। ये दोनों घटनाक्रम अनायास नहीं हैं। ये यही संकेत करते हैं कि भाजपा अब दक्षिण में कर्नाटक से आगे बढ़कर अपने किले मजबूत करना चाहती है। यह दांव उसकी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है।

भाजपा उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुकी है कि उसमें एक स्तर के बाद विस्तार की गुंजाइश सीमित हो जाएगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी वह पकड़ बनाने में सफल हुई है। बंगाल में तो वह चौथे पायदान से सीधे दूसरे स्थान पर आकर तृणमूल कांग्रेस को टक्कर देने की स्थिति में आ गई है। उड़ीसा में भी वह आक्रामक रणनीति और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाने के दांव से मुकाबले में आने की उम्मीद कर रही है। ऐसे में बचता है दक्षिण, क्योंकि वहां कर्नाटक के अलावा उसका कोई खास आधार नहीं। इसीलिए वह दक्षिण को साधने में जुटी है। इसके पीछे यही उद्देश्य लगता है कि आगामी आम चुनाव में उसे यदि अपने स्थापित गढ़ों में कुछ नुकसान उठाना पड़े तो नए क्षेत्रों से उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए।

दक्षिण के 5 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में लोकसभा की 130 और विधानसभा की 912 सीटें हैं। भाजपा के पास इनमें लोकसभा की 30 सीटें ही हैं और उसमें भी 25 अकेले कर्नाटक से। यानी दक्षिण में कर्नाटक के आगे उसे बहुत काम करना है। इन राज्यों में भाजपा की सफलता कई पहलुओं पर निर्भर करेगी। कर्नाटक में वह मजबूत है, फिर भी 2023 में लगातार दूसरा विधानसभा चुनाव जीतना कुछ मुश्किल जरूर, मगर नामुमकिन नहीं होगा। केरल और पुडुचेरी में उसने जड़ें जमाई हैं, लेकिन तमिलनाडु और आंध्र में वह बहुत कमजोर है। इन राज्यों में भाजपा गठबंधन के लिए किन दलों के साथ आती है और उसका प्रदर्शन कैसा रहेगा, यह बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि वह कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव अगले साल जीत पाती है या नहीं।

तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेताओं की भाजपा से बढ़ती रार-तकरार तो यही संकेत करती है कि यहां भाजपा की ताकत बढ़ी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को यहां मात्र 7 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे, लेकिन अगले साल हुए लोकसभा चुनाव में उसे 20 प्रतिशत मत मिले और मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी भी भाजपा प्रत्याशी से चुनाव हार गईं। इसके बाद डुबक्का और हुजूराबाद उपचुनावों में भाजपा को भारी जीत मिली। हैदराबाद निकाय चुनाव में भी उसे अप्रत्याशित सफलता मिली। स्थिति यह हो गई कि हैदराबाद में अपना मेयर बनाने के लिए केसीआर को ओवैसी की पार्टी का समर्थन लेना पड़ा। ये रुझान तेलंगाना में भाजपा की मजबूती का संकेत करते हैं और यही कारण है कि पार्टी यहां पूरे दमखम से अपनी बिसात बिछाने में जुटी है।

● इन्द्र कुमार

भाजपा कार्यकारिणी के संकल्प

पार्टी ने बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए। वरिष्ठ नेता अमित शाह ने राजनीतिक संकल्प के प्रस्ताव पर कहा कि अगले 30 से 40 साल में भाजपा का युग होगा और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादास्पद टिप्पणियों और उदयपुर और अमरावती में हत्याओं पर शाह ने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति खत्म होने के बाद साम्प्रदायिकता भी खत्म हो जाएगी। हाल की चुनावी जीत पर अमित शाह ने कहा कि पिछले चुनावों और उपचुनावों में भाजपा की जीत ने पार्टी के विकास और प्रदर्शन की राजनीति के लिए लोगों की स्वीकृति को रेखांकित किया है। उनके मुताबिक, यह नतीजे परिवार का शासन, जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति को खत्म करने के लिए हैं। अमित शाह ने कहा कि भाजपा तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पारिवारिक शासन समाप्त करेगी और आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा सहित अन्य राज्यों में सत्ता में आएगी। बैठक में शाह ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताया, जिसमें जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी गई थी। शाह ने कहा- 'दंगों में अपनी कथित भूमिका को लेकर जांच का सामना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी साध ली और भगवान शिव की तरह जहर पीकर संविधान में अपना विश्वास बनाए रखा।'

कलह की नहीं हो पाई सुलह

छत्तीसगढ़ में राजनीतिक कलह की सुलह दिल्ली में भी नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव गत दिनों दिल्ली तो पहुंचे, लेकिन केंद्रीय नेताओं से मुलाकात नहीं हुई। मुख्यमंत्री बघेल हिमाचल प्रदेश के नेताओं के साथ मुलाकात करके रायपुर वापस लौट आए। वहीं, भोपाल से दिल्ली पहुंचे सिंहदेव भी भोपाल वापस लौट जाएंगे। कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो सिंहदेव की विधानसभा सत्र तक प्रदेश में वापसी संभव नहीं है। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद थी कि सिंहदेव के पंचायत विभाग छोड़ने और रविंद्र चौबे को पंचायत विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद दिल्ली दरबार में कुछ हल निकल सकता है।

कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव बाबा के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस्तीफा देने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थक खुलकर आमने-सामने आ गए हैं। विधायकों ने सिंहदेव पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हाईकमान को पत्र भेजा है। विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने प्रदेश में संवैधानिक संकट की बात कहते हुए जमकर हंगामा किया। भूपेश सरकार से जवाब मांगा, जिसके बाद सदन की कार्रवाई एक दिन लिए स्थगित करनी पड़ी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 16 जुलाई को पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा देने के साथ यह कहते हुए खलबली मचा दी है कि उनके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। सिंहदेव के इस्तीफे के बाद मचा घमासान लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के इस सियासी हालात की गूंज दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है। सिंहदेव खुद दिल्ली में हैं। पार्टी पदाधिकारी हाईकमान की तरफ से इस पर निर्णय होने की बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हैं, उसे देखते हुए यही लगता है कि आने वाले समय में दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन से इनकार नहीं किया जा सकता।

टीएस सिंहदेव के इस्तीफे का मामला कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच गया है। ऐसे में इसका निर्णय कांग्रेस हाईकमान को ही करना है। इस्तीफा मंजूर होगा कि नहीं होगा? इन सब मामले पर राजनीति दिल्ली में केंद्रित हो गई है। हालांकि इस्तीफा मंजूर करना या न करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, फिर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामला हाईकमान पर छोड़ दिया है। इधर भाजपा, सरकार में सब कुछ सही नहीं होने का दावा कर रही है। यह दबाव बनाने दिया गया इस्तीफा है या फिर सरकार के अंदर सही में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे तमाम सवाल अभी छत्तीसगढ़ की राजनीति में उठ रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में ढाई-ढाई साल का विवाद, मंत्री का इस्तीफा और सत्ता में टकराव का असर कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा। कांग्रेस के भीतर मचा घमासान सार्वजनिक हो गया है। इस तरह की परिस्थितियां किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छी नहीं होती। सिंहदेव के पास अभी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, बीस सूत्रीय, वाणिज्यिक कर (जीएसटी) का प्रभार है। सिंहदेव अपने प्रभार वाले बाकी विभागों में कैबिनेट मंत्री बने रहेंगे या उसे भी छोड़ देंगे यह बड़ा सवाल है। एक साल बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में घटनाक्रम से कांग्रेस की सेहत पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ढाई साल पूरा होने के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री बदलने की आंधी चली टीएस सिंहदेव खेमे को कमजोर करने की कोशिश शुरू हो गई। सिंहदेव समर्थन विधायक भी पाला बदलने लगे। टीएस सिंहदेव की **अनुशंसाओं** की फाइलें डंप की जाती रहीं। मंत्री के विभाग में दखल और सचिवों की कमेटियों का निर्णय जाहिर सी बात है किसी मंत्री के लिए यह सहज स्थिति नहीं है। इसे लेकर टीएस सिंहदेव लंबे समय से सरकार से खफा हैं। सरगुजा संभाग में टीएस समर्थकों पर पुलिस व प्रशासन द्वारा टार्गेटेड कार्रवाई के साथ उनके लिए प्रशासनिक प्रोटोकॉल तक का पालन नहीं करने से उनकी नाराजगी और बढ़ी। टीएस सिंहदेव की इससे बेहतर स्थिति भाजपा के डॉ. रमन सिंह सरकार में थी, जब वे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे।

राजनीति के जानकारों की मानें तो कैबिनेट मंत्री सिंहदेव ने अपनी ही सरकार पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उससे तो यही प्रतीत होता है कि अब सिंहदेव ज्यादा समय कांग्रेस की राजनीति में रहने वाले तो नहीं हैं। जाहिर है राजनीति करने के लिए जिस भी पार्टी को वे चयन करें उसमें वे अपने आपको क्लीन चिट देने के लिए इन आरोपों को ही जनता के बीच लेकर जाएंगे। जाहिर है ऐसी स्थिति में जनता की सहानुभति टीएस सिंहदेव के साथ होगी जिसका सीधा खमियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। राजनीतिज्ञों की मानें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व टीएस सिंहदेव के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर एक प्रकार की अंदरूनी खींचातानी लंबे समय से चली आ रही थी जिसकी जानकारी दिल्ली में बैठे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को भी भलीभांति है लेकिन इसके बावजूद उनके द्वारा मामला शांत कराने के बजाय चुप रहना कई सवाल खड़े करता है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

अपनी ही सरकार पर लगाए लिखित आरोप

कारण चाहे जो भी हो लेकिन 15 वर्षों के बाद भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने में सड़क से लेकर सिंहासन तक के सफर में इन दोनों नेताओं ने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। युवाओं में नया जोश भरने व सत्ता में बैठे भाजपा से सीधी टक्कर लेने में वर्तमान मुख्यमंत्री को सीबीआई से पूछताछ से लेकर जेल जाना पड़ा था। वहीं लंबे समय से कांग्रेस में रहकर कांग्रेस में भितरघात करने वाले कांग्रेस के नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने में भी पीछे नहीं रहे जिससे कांग्रेस को लंबे समय के बाद सत्ता का सुख नसीब हुआ। चुनाव में बेहतर रणनीति बनाने व किसी ना किसी बात से कांग्रेस से नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने व चुनाव में किसी भी संसाधन की कमी ना हो इसके लिए एक बेहतर कार्ययोजना बनाने में या फिर जनघोषणा पत्र तैयार करने में जो काबिलियत टीएस सिंहदेव ने दिखाई उससे आज भी कांग्रेस के शीर्ष नेता प्रभावित हैं। यही कारण है कि समय-समय पर सिंहदेव को दूसरे राज्यों का भी घोषणा-पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई।

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी के बाद अब पार्टी (शिवसेना) पर घमासान तेज हो गया है। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी की पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर दी गई। शिंदे गुट ने इसके साथ ही नई कार्यकारिणी का ऐलान भी कर दिया। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नया नेता चुन लिया गया है। खास बात यह है कि शिवसेना ने पार्टी प्रमुख के पद को नहीं हटाया है। यानी उद्धव ठाकरे का पद जस का तस रखा गया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम ने एक बार फिर बेमानी होते जनादेश को उजागर कर दिया है। जनमत जो हो, दलबदल करवाकर दूसरी पार्टी की सरकार को अल्पमत में लाना सत्ता हथियाने का नया तरीका बन गया है। 56 साल पुरानी शिवसेना में अब तक की सबसे बड़ी बगावत के बाद बना एकनाथ शिंदे गुट भले इसे सिद्धांत और विचारधारा की लड़ाई बता रहा हो, लेकिन आज के दौर में ऐसा दावा हास्यास्पद ही लगता है।

ढाई साल पहले 2019 में जब महाराष्ट्र में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी सरकार बनी, तब भाजपा ने कहा था कि तीन पहिए वाली सरकार अपने ही विरोधाभासों के चलते गिर जाएगी। तीसरे पहिए के नट-बोल्ट निकालने वाला कौन है, यह खुद शिंदे ने जाहिर कर दिया जब उन्होंने कहा कि इससे पहले वे पांच बार भाजपा के साथ सरकार बनाने का प्रयास कर चुके थे। मिशन महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका भी बताने की जरूरत नहीं। शपथ ग्रहण के पांच दिन बाद शिंदे 4 जुलाई को विश्वास मत जीत गए। 288 (अभी 287) सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 144 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। विश्वास मत के पक्ष में 164 और विरोध में 99 ने वोट डाले। खास बात यह रही कि कांग्रेस के 11 और राकांपा के कई विधायक अनुपस्थित रहे। भाजपा विधायक राहुल नरवेकर विधानसभा अध्यक्ष और राकांपा नेता अजित पवार विपक्ष के नेता चुने गए हैं।

इस प्रकरण ने राज्यपाल और स्पीकर की भूमिका को भी फिर विवादों में ला दिया है। बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, फिर भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फ्लोर टेस्ट की भाजपा की मांग स्वीकार करने में जरा भी देरी नहीं की। कोश्यारी 2019 में एक सुबह अचानक देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाकर विवादों में आए थे। 1994 में कर्नाटक के एसआर बोम्मई से लेकर 2016 में अरुणाचल प्रदेश के नबम रेबिया मामले तक, सुप्रीम कोर्ट कई बार राज्यपाल और स्पीकर की भूमिका की आलोचना कर चुका है। हालांकि इस बार सवाल सुप्रीम कोर्ट पर भी उठ रहे हैं क्योंकि पहले तो उसने डिप्टी स्पीकर के आदेश पर दो हफ्ते के लिए रोक लगा दी, उसके बाद फ्लोर टेस्ट की भी अनुमति दे दी।

इस राजनीतिक संकट में सबसे बड़ा उलटफेर आखिरी क्षणों में दिखा जब भाजपा ने शिंदे को मुख्यमंत्री और फडणवीस को उपमुख्यमंत्री बनाया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक तीर से भाजपा ने कई निशाने साधने की कोशिश की है। एक तो यह शिंदे गुट को असली शिवसेना बताने की कोशिश है ताकि शिवसेना का बड़ा धड़ा शिंदे के साथ आए। शिंदे मूल रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र से आते हैं जो राकांपा प्रमुख शरद पवार का गढ़ है। मराठा नेता शिंदे को सामने रखकर भाजपा पवार को चुनौती दे सकेगी। प्रदेश में 30 से 32 फीसदी मराठा मतदाता हैं। फडणवीस ब्राह्मण हैं जिनकी संख्या सिर्फ तीन फीसदी है। एक संदेश यह भी है कि दूसरे प्रदेशों में भी अगर अन्य दलों में बागी हुए तो भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है। कहा जाता है कि हालिया प्रकरण की पटकथा फडणवीस ही लिख रहे थे। लेकिन आखिरी पंक्तियां कोई और लिखेगा, यह शायद उन्हें भी नहीं मालूम था। पहले उन्होंने कहा कि वे सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उन पर उपमुख्यमंत्री बनने के लिए दबाव डाला। विश्लेषक यह भी मानते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने फडणवीस के पर कतरे हैं।

महाराष्ट्र की सत्ता दो मायने में महत्वपूर्ण है। एक तो उप्र के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें (48) यहीं हैं। दूसरा, इकोनॉमी के लिहाज से महाराष्ट्र (30 लाख करोड़ रुपए जीएसडीपी) देश का सबसे बड़ा राज्य है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के नगर निगम (बीएमसी) का बजट (45 हजार करोड़ रुपए) ही कई राज्यों के बजट से अधिक है। इसलिए अगली लड़ाई बीएमसी की होगी जिस पर करीब तीन दशक से शिवसेना का कब्जा है। यहां 2017 में सेना को 84 और भाजपा को 82 सीटें मिली थीं। सितंबर-अक्टूबर में करीब डेढ़ दर्जन निगमों/निकायों के चुनाव होने हैं। कभी शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे 'हिंदुत्व' का चेहरा माने जाते थे। उन्होंने दावा भी किया था कि 1992 में बाबरी मस्जिद शिव सैनिकों ने गिराई थी। लेकिन आज की भाजपा हिंदुत्व के दायरे में किसी और को नहीं देखना चाहती। विश्लेषक दोनों दलों के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह इसी को मानते हैं। 2019 में जब भाजपा बहुमत से दूर रह गई तो उद्धव ने मुख्यमंत्री पद का दावा किया। उनका कहना था कि अमित शाह ने इसका वादा किया था। भाजपा नहीं मानी तो उद्धव ने राकांपा और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। सूत्रों के अनुसार, भाजपा तब से ठाकरे को सबक सिखाने का इंतजार कर रही थी।

● **बिन्दु माथुर**

शिवसेना में असंतोष के कई कारण

भाजपा भले महाविकास अघाड़ी सरकार हटाने के प्रयास में थी, लेकिन शिवसेना के भीतर असंतोष के बिना यह टूट संभव नहीं थी। अतीत में छगन भुजबल, नारायण राणे और यहां तक कि राज ठाकरे के जाने को भी शिवसेना झेल चुकी है। लेकिन इस बार 55 में से 40 विधायक टूट गए। फिलहाल उद्धव गुट में 15 विधायक रह गए हैं। माना जा रहा है कि शिंदे गुट अब शायद उद्धव गुट के विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि इससे शिव सैनिकों में उनके खिलाफ संदेश जा सकता है। शिवसेना में असंतोष के कई कारण हैं। उद्धव बेटे आदित्य ठाकरे को उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ा रहे थे। कहा जाता है कि वे शिवसेना नेता अनिल परब और अनिल देसाई जैसे चुनिंदा लोगों से ही घिरे रहते थे। इससे शिंदे जैसे गद्दी के दावेदारों का नाराज होना लाजिमी था। शिंदे ने कहा भी, आज जो हुआ वह एक दिन का नतीजा नहीं है। मुझे लंबे समय तक दबाकर रखा गया। सुनील प्रभु (उद्धव गुट के विधायक) भी इसके गवाह हैं। बकौल शिंदे, अजित पवार ने उनसे कहा था कि अघाड़ी सरकार में उनके साथ 'दुर्घटना' हो गई।

जल परियोजना पर राजनीति

ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को लेकर इन दिनों सियासत में गहमा-गहमी मची हुई हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है 'हम प्रधानमंत्री मोदी को उनका वादा याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने को कहा था, लेकिन अब वह अपने वादे से मुकर रहे हैं। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। यह हमारा अधिकार है।' गहलोत ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि इस परियोजना से राजस्थान के 13 जिलों में सिंचाई हो सकती है। उन्होंने इस मामले में केंद्र के इस तर्क को गलत बताया कि जल प्रदेश का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से इनकार करता है, तो हम इसे अपने बूते पूरा करेंगे। सूत्रों की मानें, तो राजनीतिक रस्साकसी में इस परियोजना का काफी मीठा पानी व्यर्थ बह रहा है।

उल्लेखनीय है कि चंबल नदी पर धौलपुर में केंद्रीय जल आयोग का रिवर गेज स्टेशन है। जहां नदी में बहकर जाने वाले पानी की मात्रा मापी जाती है। केंद्रीय जल आयोग के इस स्टेशन से प्राप्त 36 साल के आंकड़ों के अनुसार, रिवर गेज स्टेशन से हर साल औसतन 1,900 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी व्यर्थ बह जाता है। राज्य के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल का कहना है कि योजना से मात्र 3,500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी ही उपयोग में लिया जाएगा। ईआरसीपी की डीपीआर मप्र-राजस्थान अंतरराज्यीय स्टेट कंट्रोल बोर्ड की सन् 2005 में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार तैयार की गई है। इस निर्णय के अनुसार, राज्य किसी परियोजना के लिए अपने राज्य के कैचमेंट से प्राप्त 90 फीसदी पानी एवं दूसरे राज्य के कैचमेंट से प्राप्त 10 फीसदी पानी का उपयोग इस शर्त के साथ कर सकते हैं कि यदि परियोजना में आने वाले बांध और बैराजों का डूब (तराई) क्षेत्र दूसरे राज्य सीमा में नहीं आता हो, तो ऐसे मामलों में राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से इस परियोजना पर कार्य करेगी, तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि जब केंद्र सरकार परियोजना को 90 अनुपात 10 के आधार पर राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा देगी, तब भी यह 10 साल में पूरी होगी। लंबे समय से इस परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने की मांग केंद्र सरकार से कर रहा है, लेकिन इस पर अभी तक कोई फैसला केंद्र ने नहीं लिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने जयपुर एवं अजमेर से 7 जुलाई, 2018 एवं 6 अक्टूबर, 2018 को आयोजित रैलियों से ईआरसीपी को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक निभाया नहीं गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री धारीवाल ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में अभी तक राज्य का पैसा लग रहा है। पानी राजस्थान के हिस्से का है, तो केंद्र सरकार परियोजना का कार्य रोकने के लिए कैसे कह सकती है? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने इस रवैये से प्रदेश की जनता को पेयजल से और किसानों को सिंचाई के पानी से वंचित करने का प्रयास क्यों कर रही है? इस तरह के रोड़े अटकाने की वजह से 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई का काम प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा सतही जल की उपलब्धता पर आश्रित जल जीवन मिशन की कई जिलों में सफलता दर भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। ऐसे में केंद्र के इस कदम से तो किसानों की आय भी खत्म हो जाएगी।

बता दें कि इस योजना से हाड़ोती के चारों जिले जुड़े हुए हैं। यहां दीगोद तहसील में योजना के तहत नवनेरा बांध का निर्माण हो रहा है। इस योजना को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता खुलकर बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मुद्दे को लेकर 13 जिलों के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी कर चुके हैं। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि ईआरसीपी राज्य की महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें केंद्रीय जल आयोग की वर्ष 2010 की गाइडलाइन की पालना करते हुए केंद्र सरकार के उपक्रम वेप्कॉस ने 37,200 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की थी। इसके बाद भी केंद्र सरकार ने इसमें रोड़े अटकाए। धारीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार योजना में सिंचाई का प्रावधान हटाने पर अड़ी है। हम किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। इस परियोजना से सिंचाई सुविधा के प्रावधान को नहीं हटाया जा सकता। केंद्र जब तक राष्ट्रीय महत्व का दर्जा नहीं दे देती, राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से इसका कार्य जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना 13 जिलों की जीवन-रेखा साबित होगी। इसके पूरा होने से पेयजल उपलब्धता के साथ 2,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा। इस परियोजना से बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़ सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक के निवासियों की पेयजल आवश्यकता पूरी होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवनेरा-गलवा, बिशनपुर-ईसरदा, तिक, महलपुर बैराज, रामगढ़ बैराज के 9,600 करोड़ रुपए के काम हाथ में लेने की बजट में घोषणा की थी। इसका कार्य वर्ष 2022-23 में शुरू कर 2027 तक पूरा किया जाएगा।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

परियोजना में निकाली जा रही खामियां

दिलचस्प बात है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत इस योजना में खामियां निकाल रहे हैं। शेखावत इसकी डीपीआर को ही गलत बताते हैं। उन्होंने कोटा प्रवास के दौरान कहा था कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की डीपीआर दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं बनी। इस पर मप्र की भी आपत्ति है। इसलिए इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व की योजना का दर्जा नहीं मिला। यदि दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव केंद्र को मिलता तो कोई दिक्कत नहीं आती। केंद्र सरकार चाहती है कि यह योजना समय पर पूरी हो, लेकिन राज्य के निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव नहीं मिला। उधर भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार हर घर तक जल पहुंचाने की योजना पर कार्य कर रही है। राजस्थान सरकार ने इस योजना में सहयोग नहीं किया, इस कारण प्रगति प्रभावित हुई। ईआरसीपी की कार्य योजना केंद्रीय जल आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार बनाने में राज्य सरकार को क्या दिक्कत है। राज्य सरकार को इस मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय हल निकालने में केंद्र सरकार का सहयोग करना चाहिए। इस मुद्दे के बहाने राज्य सरकार अपनी विफलताएं छिपा रही है। 13 जिले के लोग राज्य सरकार के बहकावे में नहीं आएंगे।

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

उम्मीदों भरी दूसरी पारी

किसी राज्य में निवेश करने से पहले कंपनियां वहां मैनपावर की उपलब्धता के साथ-साथ सरकार और उसकी नीतियों में स्थिरता का आंकलन करती हैं। इसके साथ-साथ कंपनियां यह भी देखती हैं कि उस राज्य का 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी)' के पैमाने पर प्रदर्शन कैसा रहा है। कुछ साल पहले तक ईओडीबी की रैंकिंग में एक दर्जन से ज्यादा राज्य उप्र से आगे रहते थे। 2017 में ईओडीबी रैंकिंग में उप्र 12वें स्थान पर था। लेकिन, उप्र अभूतपूर्व उछाल हासिल करके अब दूसरे स्थान पर काबिज हो गया है। इसके कारणों का विश्लेषण करते हुए उप्र सरकार में चीफ एडिशनल सेक्रेटरी (एमएसएमई) नवनीत सहगल बताते हैं कि उप्र ने राज्य में 500 से अधिक सुधारों को बीआरएपी एक्सरसाइज के तहत लागू किया है। इसमें कई सुधार हुए हैं जिसका हमें साफ फायदा दिख रहा है। जैसे, सिंगल विंडो सिस्टम, निवेश समर्थक, भूमि प्रशासन और भूमि और संपत्ति का हस्तांतरण, पर्यावरण पंजीकरण, श्रम विनियमन प्रवर्तक, उपयोगिता परमिट प्राप्त करना, निर्माण परमिट सक्षमकर्ता आदि। इसके अलावा, प्रदेश सरकार ने अनावश्यक कानूनों को सरल, गैर-आपराधिक बनाने के उद्देश्य से बोझिल अनुपालन को कम करने का भी काम किया है।

उप्र सरकार के उठाए कदमों की सराहना करते हुए जून 2022 में हुई सरकार की तीसरे इन्वेस्टर समिट में उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि निवेश मित्र के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम लागू होने से राज्य में निवेश के लिए बहुत सहायता मिली। नवनीत सहगल मानते हैं कि उप्र में निवेश मित्र का सफल क्रियान्वयन व्यवसाय करने की सुगमता की गति बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। वे कहते हैं, सिर्फ चार साल की अवधि में ही, निवेश मित्र ने 85 प्रतिशत उपयोगकर्ताओं की संतुष्टि के साथ 7.3 लाख से अधिक एनओसी लाइसेंस का निपटान किया है। गौरतलब है कि उप्र की रैंकिंग सुधरने के कारण राज्य में ताबड़तोड़ निवेश होने की शुरुआत होने लगी है। ब्रिटानिया, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ब्रह्मोस, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस और अडाणी जैसी कंपनियां राज्य में करोड़ों की निवेश का वादा कर चुकी हैं। यही नहीं, भारत की पहली डिस्प्ले यूनिट चीन से स्थानांतरित होकर उप्र के नोएडा में आ चुकी हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी नोएडा में स्थापित किया जा रहा है।

योगी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि सरकार ने उप्र को लेकर निवेशकों की धारणाओं को बदला है। 1990 के दशक में देश का बाजार दुनिया के लिए खुला था। भारत के अधिकतर राज्यों में विदेशी निवेश की बारिश होने लगी लेकिन उप्र पीछे रहा, जिसका प्रमुख कारण इसकी छवि थी। उस दौर में उप्र गुंडाराज, हत्याएं, अपहरण-फिरौती का प्रयाय-सा बन गया था। लेकिन, उप्र की छवि में अब बड़ा बदलाव आया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की मानें तो उप्र में अपराध पिछले सात साल के न्यूनतम स्तर पर है। हालांकि विपक्षी दल इससे इत्तेफाक नहीं रखते। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय का कहना है कि एनसीआरबी का आंकड़ा भ्रमित करने वाला है। वे कहते हैं, थाने में प्राथमिकी दर्ज कराना आज के समय में सबसे कठिन काम है। जब थाने में केस दर्ज नहीं होगा तो एनसीआरबी के आंकड़ों में दिखेगा कैसे? हालांकि सरकारी आंकड़ों में फर्क साफ दिखता है। प्रदेश में साल 2013 में बलात्कार के 3,050 मामले सामने आए थे जो 2020 में घटकर 2,769 हो गए। इसी तरह, हत्याओं की संख्या साल 2013 में 5,047 थी, जो अब 25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,779 हो गई है।

जाहिर है, अपराध की घटती दर की वजह से उप्र में एक निवेश का माहौल बना है जो धरातल पर मूर्त रूप से दिखाई पड़ रहा है। महामारी के दौरान भी उप्र में विदेशी निवेश न सिर्फ अप्रभावित रहा बल्कि इसमें बढ़ोतरी देखी गई। वित्त वर्ष 2017-20 के बीच उप्र ने एफडीआई प्रवाह में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी कंपनियों ने जून 2021 में निवेश 5,211.98 करोड़ रुपए से बढ़ाकर दिसंबर 2021 में 5,758.17 करोड़ रुपए कर दिया। हालांकि विपक्ष इसे भी मानने को तैयार नहीं है। राजीव राय कहते हैं कि यहां इन्वेस्टमेंट के नाम पर यह झूठा प्रचार हो रहा है। वे कहते हैं, सरकार आंकड़े दे कि जितने इन्वेस्टमेंट हुए हैं, उसमें से कितने प्रोजेक्ट पूरे हुए और कितनों पर काम चल रहा है? भाजपा को सपना दिखाने की आदत है। जिस तरह से बुलेट ट्रेन परियोजना फ्लॉप हुई है, यह भी फ्लॉप साबित होगा।

सत्तापक्ष ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज करता है। उसका कहना है कि उप्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार प्रत्येक दो साल पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करा रही है और अब तक प्रदेश में ऐसे तीन सम्मेलन हो चुके हैं। वर्ष 2018 में लखनऊ में हुई पहली 'उप्र इन्वेस्टर्स समिट' में 4.68 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले। वहीं, दूसरे सम्मेलन में 67,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली 290 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। यही नहीं, हाल ही में 2022 में हुए तीसरी इन्वेस्टर समिट में सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए की कीमत की करीब 1400 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी ने घोषणा की कि वे उप्र में आने वाले समय में 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे 35,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष कुमारमंगलम बिड़ला ने प्रदेश में 40 हजार करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया, जिससे 40 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का अवसर उत्पन्न होगा।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार

किसी भी राज्य को सशक्त होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर से रोड कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण स्थान है। उप्र में एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के नोडल अधिकारी, प्लानिंग सेक्रेटरी आलोक कुमार कहते हैं कि सामान के आयात और निर्यात में कोई रुकावट न आए इसके लिए कनेक्टिविटी सुधारना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे कहते हैं, उप्र के पास सबसे बड़ा रनिंग यमुना एक्सप्रेस-वे है। इसके अलावा हमारे पास बुंदेलखंड, आगरा और गंगा एक्सप्रेस-वे भी है। हमारा सिविल एविएशन सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारे पास 5 एयरपोर्ट और कई लोकल एयरपोर्टस भी हैं। बिजली की आपूर्ति बाधारहित हो, इस पर भी हमारा खासा जोर है। आने वाले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर में तेजी से बदलाव दिखेगा। अगर उप्र में सभी निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे बन जाएं तो उप्र में कुल 1,788 किलोमीटर एक्सप्रेस-वे का नेटवर्क होगा, जो देश में सबसे ज्यादा है।

8वीं अनुसूची में शामिल होगी भोजपुरी?

पिछले पांच दशक से भोजपुरिया समाज भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग कर रहा है। लेकिन आज तक इस मांग पर कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई है। हर बार नियमों का हवाला देकर इस मांग को खारिज कर दिया जाता है। इसकी वजह से निराश हो चुके भोजपुरिया समाज को एक बार फिर आस जगी है। वजह ये है कि इस बार संसद में एक साथ तीन ऐसे सांसद मौजूद हैं, जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं। भोजपुरी की वजह से पहले सिनेमा और अब सियासत में नाम कमाने वाले इन सितारों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर कोई चाहता है कि तीनों सांसद एक साथ मिलकर संसद के अंदर भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल करें।

भोजपुरी फिल्म अभिनेता और गायक मनोज तिवारी और रवि किशन पहले से ही संसद में मौजूद हैं। हाल ही में हुए उपचुनाव में आजमगढ़ से चुनकर दिनेश लाल यादव निरहुआ संसद पहुंचे हैं। मानसून सत्र के पहले दिन उन्होंने संसद में शपथ ली। इस दौरान उन्होंने जय भारत, जय भोजपुरी बोलकर उन तमाम लोगों के दिल में आस जगा दी है, जो लंबे समय से भोजपुरी को भाषा के रूप में सरकारी मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, इससे पहले कई बार प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली है। सबसे पहले 60 के दशक में गाजीपुर से सांसद विश्वनाथ गहमरी ने संसद में अपना पूरा भाषण भोजपुरी में दिया था, ताकि लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सके। उनकी पुस्तक की प्रस्तावना को प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुर ने भोजपुरी में लिखा था। सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ भी भोजपुरी को भाषा का दर्जा दिलाने की मांग संसद में कर चुके हैं।

भोजपुरी दुनिया की सबसे बड़ी बोली है, इसके बावजूद इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? इस सवाल के जवाब में भोजपुरी कवि और फिल्म समीक्षक मनोज भावुक कहते हैं, देखिए हर बार सरकार में बैठे लोग समस्या दिखाने के लिए भोजपुरी के समानांतर कई अन्य भाषाओं को खड़ा कर देते हैं। इसके बाद उनका कहना होता है कि यदि हमने भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया तो हमें कई अन्य भाषाओं को भी मजबूरन शामिल करना पड़ जाएगा। वरना विरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरे विचार से ये गलत बात है। क्योंकि भोजपुरी से किसी बोली या भाषा की कोई तुलना नहीं है। देश में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा भोजपुरी बोली जाती है। इतना ही नहीं देश से बाहर यदि कोई बोली सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो वो भोजपुरी ही है। एक नहीं कई देशों में इसे बोला जाता है।

मनोज भावुक आगे कहते हैं, ज्मॉरीशस, फिजी, गयाना, सूरीनाम, नेपाल यहां तक कि सिंगापुर, उत्तर अमेरिका और लैटिन अमेरिका में भी भोजपुरी बोली जाती है। मॉरीशस में तो इसे सरकारी मान्यता भी मिल चुकी है। वहां पहले से ही पांच से अधिक भाषाएं मौजूद हैं। भोजपुरी तो वहां की भाषा भी नहीं है। भारत से गए हुए लोगों की भाषा हैं। इसके बावजूद इसे सरकारी भाषा मान लिया गया है। भोजपुरी का इतिहास एक हजार साल से भी अधिक पुराना है। यहां तक कि शेरशाह सूरी के राज्य में सरकारी कामगाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। इतना सबकुछ होने के बाद भी सरकारी और सियासी इच्छाशक्ति की कमी की वजह से इसे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा रहा है।

इस वक्त देश की संसद में तीन सांसद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, इस मुद्दे को लेकर उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? इस पर मनोज भावुक कहते हैं, देखिए मैं भोजपुरी सिनेमा से बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा हूं। इस मुद्दे को बहुत करीब से देखता आया हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इन लोगों के संसद में होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। रवि किशन जब सांसद बने तो उन्होंने भी पहला काम यही किया कि संसद में भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की और गाना भी गाया था, लेकिन आज ये मुद्दा कहां है? कोई नहीं जानता। ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि देश में भोजपुरी भाषी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर से लेकर मुख्यमंत्री तक हुए हैं, लेकिन भोजपुरी का कुछ नहीं हो सका है। एक समय में 40 से ज्यादा सांसद भोजपुरी बोलने वाले रहे हैं, अभी भी लोकसभा से राज्यसभा तक तीन दर्जन से ज्यादा ऐसे सांसद हैं, जो भोजपुरी बोलते हैं। लेकिन क्या हुआ? इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक इच्छाशक्ति का हमेशा से अभाव रहा है। जब तक इसे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर लिया जाता, तब तक कुछ नहीं कहा सकता है। साल 2003 में हुए संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, बोडा और डोगरी को शामिल किया गया, लेकिन भोजपुरी को नहीं, इसके पीछे क्या वजह है?

● **विनोद बक्सरी**

कोशिशें बराबर होती रही हैं

भोजपुरी को भाषा का दर्जा दिलाने के लिए गाजीपुर से सांसद रहे विश्वनाथ गहमरी ने संसद में पूरा भाषण भोजपुरी में दिया था। सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत कोशिश की है, आखिर कहां कमी रह गई है? इस पर चंदन तिवारी कहती हैं, विश्वनाथ गहमरी जी का भाषण तो कालजयी माना जाता है। योगी जी ने भी बहुत प्रयास किया है। रघुवंश प्रसाद सिंह, प्रभुनाथ सिंह जी ने भी संसद में प्रयास किया है। इसके लिए मजबूती से मांग उठाई है। भोजपुरी की पहली फिल्म डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी की प्रेरणा से बनी थी। इस फिल्म को दिल्ली से लेकर देश के राजनीतिक गलियारे तक में बाबू जगजीवन राम ने गर्व के साथ प्रचारित किया कि ये हमारी मातृभाषा में बनी फिल्म है। हमारी कमी यह रह गई कि हम अपनी भाषा और संस्कृति को एक अलग कर्म मानते हैं। यह हमारी अस्मिता और पहचान से नहीं जुड़ रहा है। यहां सिर्फ राजनीतिक कमी नहीं मान सकती। समाज भी जब अपनी भाषा को अपनी अस्मिता से जोड़ेगा और यह संदेश देगा कि उसके लिए सभी चीजों के साथ अपनी भाषा का मान-सम्मान और पहचान जरूरी है, तो राजनीतिक संदेश भी जाएगा कि भोजपुरी भाषियों को तमाम भौतिक विकास के साथ उनका सांस्कृतिक विकास भी चाहिए। हमारे समाज की असली कमी यही है कि वो अपनी भाषा को अपनी अस्मिताई पहचान से नहीं जोड़ पा रहा।

ANU SALES
CORPORATION
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
Dispensation
Aspiration
We Deal in Pathology
& Medical Equipment
BA200
BioSystems
The Highest Flexibility
Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530
Email : ascbhopal@gmail.com

नहिं कलि करम न भगति बिबेकू

कलियुग में श्रीराम नाम की महिमा अपार है। इसके जाप मात्र से ही मनुष्य अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जो मनुष्य भौतिक सुख-सुविधाओं में लीन होकर ईश्वर को भूल जाता है उसे अंत में पछताना पड़ता है। श्रीराम प्रातः उठकर अपने माता-पिता व गुरुओं के चरण स्पर्श करते थे। पिता के कहने पर राजपाट त्याग कर वन में ऋषि-मुनियों के सानिध्य में चले गए। उन्होंने अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन किया। इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहाए।

नहिं कलि करम न भगति बिबेकू।
राम नाम अवलंबन एकू॥
कालनेमि कलि कपट निधानू।
नाम सुमति समरथ हनुमानू॥

कलियुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलियुग रूपी कालनेमि के (मारने के) लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमानजी हैं॥

कहते हैं कि कलियुग ने आने के लिए राजा परीक्षित से बहुत अनुनय-विनय की। कहा कि घबराइए नहीं महाराज, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, बस 'स्वर्ण' में घर बसाएंगे। हमारे साथ दो-चार संगी, साथी होंगे- राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम-वासना आदि। अपने गुण बताते हुए कलियुग ने कहा- सुनो हमारी महिमा! हमारे राज में जो प्रभु का 'केवल' नाम ले लेगा, उसकी मुक्ति निश्चित है।

और तो और, मन से सोचे गए पाप की हम सजा नहीं देंगे, पर मन से सोचे गए पुण्य का फल जरूर देंगे। राजा परीक्षित ने कलियुग को आने दिया तो सबसे पहले वह राजा के सोने के मुकुट में ही विराजमान हुआ और सबसे पहले उन्हें ही मृत्यु की ओर धकेल दिया।

कलियुग को सभी कोसते हैं, सभी क्रोध, राग, द्वेष और वासना से ग्रस्त हैं। कोई कहता है काश, हम सतयुग में पैदा हुए होते। कोई त्रेता और द्वापर युग के गुण गाता है। तुलसीदास ने जन-मानस की हालत देखकर समझाया कि कलियुग में बेशक बहुत सी गड़बड़ियां हैं, मगर उन सबसे बचने का उपाय जितनी सरलता से कलियुग में मिल सकता है, उतनी सरलता से किसी और काल में नहीं मिला। पहले प्रभु को पाने के लिए ध्यान करना पड़ता था।

त्रेता में योग से प्रभु मिलते थे, द्वापर में कर्मकांड का मार्ग था। ये सभी मार्ग नितांत कठिन और घोर तपस्या के बाद ही फलीभूत होते हैं, पर कलियुग में ईश्वर को प्राप्त करना पहले के मुकाबले बड़ा ही सरल हो गया है। कैसे भाई? हर मत और संप्रदाय ने गुण गाया है 'नाम' का। यह वह मार्ग है जहां विविध संप्रदाय एकमत हो जाते हैं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा...

कलियुग केवल नाम अधारा।
सुमिरि सुमिरि नर उतरहिं पारा।।

नाम जप में किसी विधिविधान, देश, काल, अवस्था की कोई बाधा नहीं है। किसी प्रकार से, कैसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कैसे भी नाम जप किया जा सकता है। इस नाम जप से हर युग में भक्तों का भला हुआ। श्रीमद्भागवत में कथा आती है अजामिल ब्राह्मण की, जिसने सतयुग में घोर पाप किया। पत्नी के होते हुए वैश्या के पास रहा। वैश्या के पुत्र का नाम नारायण रख दिया। मरते समय पुत्र को पुकारा, 'नारायण!' तो स्वयं नारायण आ गए।

ऐसी ही एक और कथा है गज ग्राह युद्ध की। गज ने अपनी सूंड तक अपने को डूबते पाया तो पुकारा 'रा!' इतनी भी शक्ति नहीं थी कि पूरा 'राम' कह दे। पर प्रभु ने भाव समझ लिया और गज के प्राण बचा लिए। त्रेता में वाल्मीकि ने नाम जप किया तो उल्टा। 'राम' कह न सके, डाकू थे, मांसाहारी थे, सो 'मरा' कहना सरल लगा, तोते की तरह रटते रहे तो स्वयं श्री राम पधारे कुटिया में।

'उलटा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भए ब्रह्म समाना।' द्वापर युग में दौपदी ने भरी सभा में रोते हुए हाथ खड़े कर दिए। सभी का सहारा छोड़ दिया तो कृष्ण की याद आई। श्रीकृष्ण चीर रूप में प्रकट हुए।

कलियुग में तो नाम जप के भक्तों की भरमार है। कबीर, मीरा, रैदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान, नानक, रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि आदि। राजा परीक्षित के वैद्य धन्वन्तरि तो कहते थे कि 'नाम जप' औषधि है, जिससे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। इस औषधि का लाभ गांधीजी ने भी तो उठाया। हर अवस्था में, चिंता में, रोग में उन्होंने 'राम नाम' का आश्रय लिया।

लेकिन नाम जप का यह अर्थ नहीं कि पाप करने की छूट मिल गई। नाम से पापों का विनाश होता तो है, पर तभी जब व्यक्ति के हृदय में पिछले पापों के प्रति प्रायश्चित और उन्हें दोबारा न करने का संकल्प हो। नाम जप की औषधि के साथ परहेज भी आवश्यक है। नाम जपते रहो, क्रोध स्वतः दूर हो जाएगा। जप में बुरी प्रवृत्तियां पीछे हटती जाती हैं। उन्हें जबरन हटाने का प्रयास न करो, बस नाम जपो, प्रेम से।

रामचरितमानस में भी बाबा तुलसी ने लिखा है... सत्ययुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं॥ द्वापर में श्री रघुनाथजी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है और कलियुग में तो केवल श्री हरि की गुणगाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं॥

कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना।
एक अधार राम गुन गाना॥
सब भरोस तजि जो भज रामहि।
प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि॥

कलियुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री रामजी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्यागकर जो श्री रामजी को भजता है और प्रेमसहित उनके गुणसमूहों को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलियुग में प्रत्यक्ष है।

● **ओम**

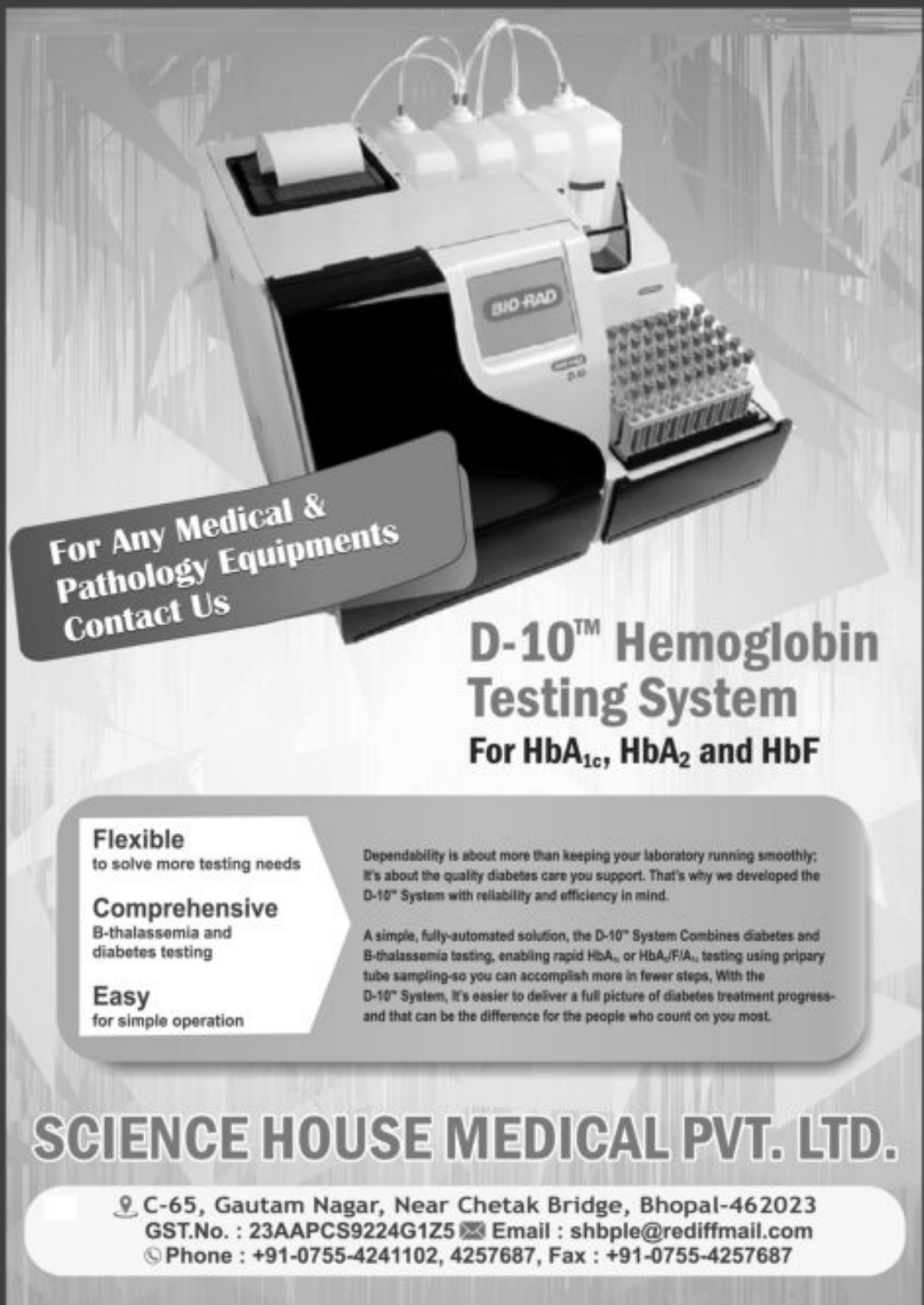
For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us
BIO-RAD
D-10™ Hemoglobin
Testing System
For HbA1c, HbA2 and HbF
Flexible
to solve more testing needs
Comprehensive
B-thalassemia and
diabetes testing
Easy
for simple operation
Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly;
It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the
D-10™ System with reliability and efficiency in mind.
A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and
B-thalassemia testing, enabling rapid HbA2 or HbA2/F/A2 testing using pripary
tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the
D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-
and that can be the difference for the people who count on you most.
SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.
C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

दर्द

मम्मी... गोलू जोर से चीखा।

क्या हुआ बेटा? उसकी चीख सुनकर नैना तड़प कर उसके कमरे में भागी आई।

मम्मी... ये देखो न, मेरी उंगली कट गई। बड़े जोरों का दर्द हो रहा है।

कैसे कट गई तुम्हारी उंगली? अरे, ये तो बहुत खून बह रहा है। उसकी मां अधीरता से प्रथमोपचार की पेटी लेने दूसरे कमरे की ओर दौड़ पड़ी।

इस बीच गोलू सुबकता रहा। नैना ने उसकी उंगली में दवाई लगाकर पट्टी बांध दी। दस वर्षीय गोलू ने अपनी उंगली की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी, एक बात पूछूं?

हां, बेटा! बोलो, क्या पूछना चाहते हो?

मम्मी.. मेरी उंगली से थोड़ा सा खून बह गया तो तुम तड़प उठीं और मुझे भी बड़े जोरों का दर्द हो रहा था। कल हम जिस बकरे का गोश्त इतने चाव से खा रहे थे उसे कितना दर्द हुआ होगा?..और फिर उसकी मम्मी कितना रोई होगी?

– राजकुमार कांदु

आजादी

रामू-अरे आजाद हो गए तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम तमाम बंदिशों को भूल जाओ। जिनका होना भी बहुत जरूरी है। आजादी अपनी जगह ठीक है लेकिन कुछ बंदिशें भी जरूरी है। श्याम को समझाते हुए कहा।

श्याम-मगर आजादी का मतलब तो होता है सभी तरह से आजाद। फिर बंदिशों का क्या मतलब। ये तो वही बात हो गई कि हाथ-पैर को बांध करके कह दिया गया कि अब तुम्हें दूसरे शहर जाने की पूरी आजादी है।

रामू-तुम समझें नहीं आजादी का मतलब ये थोड़ी है कि तुम सभी बंदिशों से आजाद हो गए। तुम्हारी कुछ सीमा भी हैं, जिसका उल्लंघन करने पर कानून को दंडित करने का अधिकार है। अगर कानून लोगों को अपना डर न दिखाएं तो अराजकता फैलने का खतरा है।

– अभिषेक जैन

संघर्ष

समय नहीं है अब सोने का,
उठकर आगे आना है।
संघर्षों से लड़ कर हमको,
जीवन सफल बनाना है।।

राह हजारों होते हैं जी,
जो हमको भटकाते हैं।
पांव पकड़कर पीछे खींचे,
समझ नहीं हम पाते हैं।।
बहरे मेंढक बनकर हमको,
चोटी में चढ़ जाना है।
संघर्षों से लड़ कर हमको,
जीवन सफल बनाना है।।

दुनिया वाले कहते सारे,
तुम से ना हो पाएगा।
राह कठिन है देखो आगे,
दलदल में फंस जाएगा।।
कहते हैं तो कहने देना,
कर के हमें दिखाना है।
संघर्षों से लड़ कर हमको,
जीवन सफल बनाना है।।

लक्ष्य साध कर चलते हैं जो,
वही सफल हो पाते हैं।
चुभे पांव में कांटे फिर भी,
दर्द सहन कर जाते हैं।।
दृढ़ निश्चय कर आगे बढ़ना,
करना नहीं बहाना है।
संघर्षों से लड़ कर हमको,
जीवन सफल बनाना है।।

मंजिल अपनी मिल जाती है,
मात पिता खुश होते हैं।
देख सफल अपने बच्चों को,
नींद चैन की सोते हैं।।
यही रीत है दुनिया की तो,
हंसना और हंसाना है।
संघर्षों से लड़ कर हमको,
जीवन सफल बनाना है।।

– प्रिया देवांगन 'प्रियू'

> *विश्व के महानतम बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली इन दिनों खराब फार्म के दौर से गुजर रहे हैं। आलम यह है कि टेस्ट, वनडे और टी-20 यानी सभी फॉर्मेट में उनका फ्लॉप शो चल रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि विराट कोहली टीम से बाहर न हो जाएं।*

विराट संकट में कोहली!

टी20 वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली लगातार आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि, इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टी20 मैचों में कोहली ने दूसरे मैच में 1 रन और तीसरे में 11 रन ही बनाए थे। और, उनकी खराब फार्म के बावजूद रोहित शर्मा की ओर से उनका समर्थन करने के बाद तय माना जा रहा है कि टी20 वर्ल्डकप में विराट कोहली टीम इंडिया के स्क्वॉड में शामिल रहेंगे। जबकि, टीम इंडिया के कई वेटरन खिलाड़ियों और क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने विराट कोहली के खराब फार्म को लेकर उनकी जबरदस्त आलोचना की है। ढाई साल से जारी विराट कोहली के खराब प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर पर भी भरपूर माहौल बना हुआ है। इसके बावजूद टी20 मैचों में अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए मिलने वाले मौके की जगह विराट कोहली ने वेस्टइंडीज दौरे से खुद को आराम दिया है। कोहली के इस फैसले के बाद कहना गलत नहीं होगा कि अब विराट को आराम से ज्यादा संन्यास के बारे में सोचना चाहिए।

विराट कोहली टीम इंडिया के स्टार प्लेयर्स में से एक हैं। जिसकी वजह से टीम इंडिया के तकरीबन हर विदेशी दौरे या घरेलू सीरीज में विराट कोहली स्क्वॉड का हिस्सा होते हैं। लिखी सी बात है कि टीम इंडिया का ये बिजी शेड्यूल कोहली के लिए थकाने वाला है। लेकिन, ऐसा भी नहीं है कि बीसीसीआई की ओर से विराट कोहली समेत अन्य स्टार खिलाड़ियों को आराम नहीं दिया जाता है। कई कमजोर टीमों के खिलाफ मैचों में इन खिलाड़ियों को स्क्वॉड से बाहर रखा जाता है। लेकिन, टी20 वर्ल्डकप से पहले तैयारी के आखिरी मौके के तौर पर वेस्टइंडीज के दौरे से अलग होकर विराट कोहली ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि, इस फैसले से क्रिकेट फैन्स के बीच यही मैसेज गया है कि विराट कोहली के लिए टीम इंडिया के लिए खेलने से ज्यादा आईपीएल जरूरी है। क्योंकि, अगर आराम से फार्म वापस आती, तो विराट कोहली को थकाऊ आईपीएल से आराम लेना चाहिए था।

इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विराट कोहली टीम इंडिया के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं। लेकिन, सूर्यकुमार यादव, दीपक हूडा जैसे खिलाड़ियों की एक बड़ी फौज आईपीएल के जरिए टीम इंडिया में अपनी दावेदारी ठोक रही है। इतना ही नहीं, इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन घरेलू टूर्नामेंट में भी बेहतर ही रहा है। वहीं, टीम इंडिया के पास दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ी भी हैं। जो अनुभव के साथ ही हालिया प्रदर्शन के लिहाज से विराट कोहली से हर मामले में इक्कीस ही साबित होते हैं। अगर टीम इंडिया प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों को ही टी20 वर्ल्डकप के स्क्वॉड में शामिल करने का मन बनाती है, तो विराट कोहली के लिए टीम इंडिया में अपनी जगह बचाना मुश्किल हो जाएगा। टीम इंडिया को 1983 में पहला वर्ल्डकप जिताने वाले कप्तान कपिल देव ने कहा है कि अगर वर्ल्ड के नंबर 2 गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को टेस्ट मैच में बाहर बिठाया जा सकता है। तो, वर्ल्ड के नंबर 1 को भी बाहर बिठाया जा सकता है। जब आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं, तब इन फार्म प्लेयर्स को खिलाना चाहिए।

ये पहला मौका नहीं है, जब टीम इंडिया से किसी बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप करने की मांग की जा रही हो। इससे पहले कई बड़े खिलाड़ियों को उनके खराब प्रदर्शन की वजह से टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने कोहली के खराब फार्म को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक ऐसा भी समय था, जब आउट ऑफ फार्म होने पर आपकी प्रतिष्ठा को नजरअंदाज कर आपको टीम से ड्रॉप कर दिया जाता था। सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, हरभजन सिंह सभी को उनकी खराब फार्म की वजह से ड्रॉप किया गया। ये सभी घरेलू क्रिकेट में खेले, रन बनाए और वापसी की। लगता है कि अब मानदंड काफी बदल गए हैं, जहां आउट ऑफ फार्म होने के लिए आराम है। देश में इतनी प्रतिभा है कि प्रतिष्ठा से नहीं खेला जा सकता। भारत के महानतम मैच-विजेताओं में से एक अनिल कुंबले कई मौकों पर बाहर बैठे। बड़ी जीत के लिए एक्शन की जरूरत है।

● आशीष नेमा

तो संन्यास ही रास्ता

विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दो टी20 मैचों में कुल 12 रन ही बना सके हैं। और, अब अपनी खराब फॉर्म की वजह से आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। हालांकि, ये विराट कोहली के लिए राहत की ही बात है कि उनके हाथ में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले तीन वनडे मैचों की सीरीज में अपनी खराब फॉर्म से निपटने का मौका है। लेकिन, अगर विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी फेल हो जाते हैं। तो, इस बात में शायद ही कोई दो राय होगी कि जिस तरह से बीसीसीआई ने विराट कोहली से कप्तानी ली थी। उसी तरह उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के टी20 स्क्वॉड से हमेशा के लिए संन्यास दिला दिया जाए।

...जब लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर मनोज कुमार ने बनाई फिल्म 'उपकार'

पद्मश्री, नेशनल अवॉर्ड और सात फिल्मफेयर अवॉर्ड से सम्मानित, एक ऐसा एक्टर जिसने देशभक्ति की ऐसी एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई कि उनका नाम ही मनोज कुमार से भारत कुमार पड़ गया। मनोज कुमार ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं।

1965 को दौर था जब भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। युद्ध जैसे ही खत्म हुआ तब लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार से मुलाकात की और इस युद्ध के दौरान हुई परेशानियों पर एक फिल्म बनाने की बात कही। ये बात मनोज के मन में घर कर गई। फिर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के नारा जय जवान, जय किसान से प्रेरित होकर फिल्म उपकार लिखी। इस फिल्म को निर्देशन और डायरेक्शन भी मनोज ने ही किया साथ ही फिल्म में लीड एक्टर भी मनोज ही थे। फिर जब 1967 में फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म को लोगों का खूब प्यार मिला और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म के लिए मनोज कुमार को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड तो मिला ही साथ ही इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित भी किया गया।

इमरजेंसी में मनोज कुमार पर हुए जुल्म

1972 में रिलीज हुई शोर हिंदी सिनेमा की सुपरहिट फिल्म है। इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मनोज कुमार ही थे। फिल्म के गाने काफी पॉपुलर हुए थे। इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मनोज कुमार ने इस फिल्म को दोबारा रिलीज करने की योजना बनाई और इसे रिलीज करने की तारीख की भी घोषणा कर दी थी, लेकिन इससे पहले मनोज कुमार ने इमरजेंसी का विरोध कर संजय गांधी और तत्कालीन प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल को नाराज कर दिया था। हालांकि, मनोज कुमार की विद्याचरण शुक्ल से काफी अच्छी पहचान थी। फिर भी संजय और शुक्ल की जोड़ी ने मनोज कुमार को सबक सिखाने से पहले फिल्म शोर को दोबारा थिएटर्स में रिलीज होने से पहले ही दूरदर्शन पर रिलीज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जब फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो इसे देखने कोई नहीं आया। इसी तरह उनकी दस नंबरी भी इमरजेंसी के दौरान 1976 में रिलीज हुई, लेकिन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया।

बॉलीवुड में स्ट्रगल के दौरान सुसाइड के बारे में सोचते थे मिथुन चक्रवर्ती

बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि उन दिनों सुसाइड करने का ख्याल मन में आता था। उन्होंने कहा ऐसा लगता था कि मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अपने बर्थप्लेस यानी कोलकाता जाने का भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वहां कोई ऑप्शन ही नहीं था।

मिथुन ने एक इंटरव्यू में कहा, आमतौर पर मैं इस बारे में बात नहीं करता। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम फेस भी नहीं है, जिसके बारे में बताना चाहूं। मैं स्ट्रग्लिंग पीरियड के बारे में बात नहीं करता क्योंकि इससे नए आर्टिस्ट डीमोटिवेट हो सकते हैं। हर कोई स्ट्रगल से गुजरता है, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा था।

मिथुन ने आगे कहा, कई दफा मुझे लगता था कि मैं अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाऊंगा। सुसाइड करने के बारे में भी सोचता था। कुछ कारणों के चलते मैं कोलकाता भी नहीं लौट सकता था। लेकिन मेरी सलाह है कि बिना लड़े कभी भी जिंदगी को खत्म न करें। मैं पैदाइशी योद्धा हूं। ये नहीं जानता कि हारते कैसे हैं और अब देखिए मैं कहां हूं।

गोविंदा ने करण जौहर को बताया था डेविड धवन से भी ज्यादा खतरनाक

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा का एक पुराना इंटरव्यू काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने करण जौहर को जेलेस और खतरनाक कहा था। दरअसल फिल्ममेकर डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी एक समय पर बहुत फेमस थी। लेकिन कुछ समय बाद उनके रिश्ते में मनमुटाव आ गए। अब पुराने इंटरव्यू में गोविंदा ने फिल्ममेकर करण जौहर पर भी निशाना साधा था। बातचीत के दौरान उन्होंने करण की तुलना डेविड धवन से की थी।

गोविंदा से जब पूछा गया कि क्या वो कॉफी विद करण में जाएंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, अगर वो मुझे अपने शो में बोलते हैं, तो ये सम्मान की बात होगी। वो दिखाते हैं कि वो बहुत विनम्र और मासूम हैं, लेकिन वो डेविड से ज्यादा जेलेस और खतरनाक हैं। गोविंदा ने आगे कहा, उन्होंने मुझे पिछले 30 सालों में कभी कॉल नहीं किया। वो कभी भी ऐसे लोगों से बातचीत नहीं करते, जो उनके ग्रुप का नहीं है। मुझे डाउट है कि वो लोगों को हैलो तक नहीं बोलते होंगे। वो जितना दिखाते हैं, उतने दयालु नहीं हैं। मुझे वो कभी सीधे नहीं लगते।

देश के नए संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित किए जाने वाले शेरों की मुख मुद्रा कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है। उनका मानना है कि ये शेर आक्रामक हैं जबकि मूल कृति सारनाथ वाले शेर सौम्य हैं।

जब सिट्टी-पिट्टी गुम करने वाले शेर से हुई मुलाकात...

हमारे देश में मुख्य रूप दो तरह के शेर पाए जाते हैं। एक सिट्टी-पिट्टी गुम करने वाले और दूसरे शायरी में अर्ज किए जाने वाले। पहले को देखकर मुंह से आह निकल जाती है और दूसरे को सुनकर वाह। दूसरे वाले सिर्फ मुशायरों-महफिलों या शायरों के दीवान में मिलते हैं, लेकिन पहले वाले नोट-सिक्के, किताबों, सरकारी इमारतों-दस्तावेजों से लेकर जंगलों तक में उपलब्ध होते हैं। इन्हें जंगल का राजा भी कहा जाता है, लेकिन जबसे जंगल कट गए हैं, राजा साहब के रुतबे में कमी आ गई है।

शेर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। पहले ये सर्कस में भी पाए जाते थे, किंतु पशुओं के मानवाधिकार का मुद्दा उठने के बाद से सर्कस का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। बच्चों को शेर का डर दिखाकर सुलाने का काम भी होता आया है। इस प्रकार देखें तो शेर के कई उपयोग हैं। अच्छा है कि ये बातें शेर को नहीं पता, वरना कब का रायल्टी की मांग कर चुका होता। आजकल इसे मुद्दा बनाकर भी उपयोग किया जा रहा है।

मजे की बात तो यह है कि शेर को मुद्दा बनाने वालों में कुछ रंगे सियार, गिरगिट और आंसू बहाने वाले घड़ियाल भी शामिल हैं। देश के नए संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित किए जाने वाले शेरों की मुख मुद्रा कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है। उनका मानना है कि ये शेर आक्रामक हैं, जबकि मूल कृति सारनाथ वाले शेर सौम्य हैं। अजीब तर्क है। शेर मूलत: एक हिंसक जानवर है। नव रस की दृष्टि से, उस पर स्वाभाविक रूप से रौद्र, वीर, भयानक और वीभत्स रस शोभा देते हैं। यदि कोई उसमें श्रृंगार, हास्य, करुणा और शांत रस देखना चाहे तो उसकी बुद्धि पर तरस खाने का दिल करता है।

मामले को तूल पकड़ता देखकर आखिर हमारे भीतर का भी शेर...मतलब पत्रकार जाग गया और हम अपना बीमा कराने के उपरांत जा पहुंचे शेर की मांद में। पहुंच तो गए, किंतु उसे देखते ही तोते उड़ गए...सारी हिम्मत काफूर हो गई। हमें घबराया देखकर राष्ट्रीय पशु, राष्ट्र भाषा में बोला, तुम्हारा परिचय? हम आपके साढू भाई। क्या मतलब? वह बोला। मतलब शादी से पहले हम भी शेर थे।, हमने जवाब दिया।

यह सुनकर वह इतनी विकराल हंसी हंसा कि हम सहम गए। आगे बोला, डरो मत! चले आओ...सावन शुरू हो चुका है इसलिए एक महीने के लिए मैंने नान वेज छोड़ दिया है।

नान वेज छोड़ दिया या माहौल देखकर डर गए? डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं। शेर दहाड़ा फिर अचानक धीमे स्वर में बोला, पत्नी को छोड़कर...मुद्दे पर आओ। मुद्दे की ही बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को आपकी भाव-भंगिमा पर आपत्ति है। उनका कहना है कि पहले आप सौम्य और शांत थे...अब दहाड़ रहे हैं?

नासमझ हैं वे, जो ऐसा कहते हैं। तुमने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि शेर जब दो कदम पीछे लेता है तो लंबी छलांग लगाने के लिए...न कि भागने के लिए। उस सारनाथ वाली सौम्यता को तुम पीछे वाले दो कदम समझो। अब दहाड़ने का दौर है।... अब वे दिन लद गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। यह नए जमाने का भारत है... मैं आनलाइन और आफलाइन, दोनों तरह से दहाड़ सकता हूं...।

शेर अपनी रौ में बोले जा रहा था। ऐसा लगता था उसे काफी दिन बाद बोलने का मौका मिला है या शायद भाभी जी...मतलब शेरनी उस वक्त मांद में नहीं थी। शेर जी वाकई शेर बन गए थे। बोले, मेरी जिस पुरानी सौम्य फोटो की चर्चा हो रही है, वह उस जमाने की है, जब न टेलीफोन होता था...न कैमरा। इंसान ही नहीं, जानवर भी सीधे-सादे होते थे। जिस मुद्रा में माडल को बैठा देते, बैठे रहते थे। अब मोबाइल का दौर है। सेल्फी का जमाना है और तुम जानते हो कि उल्टा-सीधा मुंह बनाए बिना सेल्फी अच्छी नहीं आती। मैंने भी ऐसा किया और लोगों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया।

हमने विषय बदलने की गरज से पूछा, श्रीलंका में रहने वाला आपका कजन आजकल बड़ी मुसीबत में है...आप उसकी कुछ मदद क्यों नहीं करते? भारत सरकार कर तो रही है मदद। वैसे भी ड्रैगन से दोस्ती का यह नतीजा तो होना ही था। यह कहकर शेर ने चुप्पी साध ली, किंतु गुफा के भीतर से जोरदार दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। सामने लाल-लाल आंखें लिए हमारी अपनी शेरनी... अर्थात् पत्नी खड़ी थीं और हम औकात में आ चुके थे।

● **कमल किशोर सक्सेना**

सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के

अनवरत 8 वर्ष

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)** में 5 लाख 5 हजार से अधिक पात्र हितग्राहियों को मिला घर। मध्यप्रदेश, देश में दूसरे स्थान पर।
- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि** में 83 लाख 78 हजार किसानों के खातों में 13 हजार 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित।
- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना** अंतर्गत अब तक 79 लाख 84 हजार महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** में 28 लाख 99 हजार गर्भवती माताओं को 1261 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मजदूरी क्षतिपूर्ति के रूप में। योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर।
- **स्वच्छ भारत मिशन 2021** में प्रदेश के इन्दौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, नर्मदापुरम, बड़वाह और पचमढ़ी कैन्ट उत्कृष्ट शहर। 27 शहरों को स्टार रेटिंग।
- **अमृत मिशन** के अंतर्गत अब तक 6 हजार 894 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 162 परियोजनाएँ स्वीकृत।
- **जल जीवन मिशन** के अंतर्गत 50 लाख से अधिक परिवारों को घर-घर नल से जल उपलब्ध।
- **प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना** के अंतर्गत 5 लाख 18 हजार से अधिक हितग्राहियों को 563 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण वितरित। योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देशभर में प्रथम।
- **आयुष्मान भारत पीएम जनआरोग्य मिशन** के अंतर्गत अब तक 7 लाख 72 हजार पात्र हितग्राहियों का निःशुल्क उपचार। 2 करोड़ 70 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जनरेट कर मध्यप्रदेश, देश में प्रथम।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना** के अंतर्गत प्रदेश के 1 करोड़ 89 लाख से अधिक हितग्राहियों को 96 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण राशि स्वीकृत।
- **आयुष्मान भारत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर** प्रदेश में 9 हजार 100 से अधिक हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के माध्यम से गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, जाँचें एवं दवा वितरण।
- **वन नेशन, वन राशन कार्ड** कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य एवं राज्य से बाहर 87.69 लाख परिवारों ने पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन प्राप्त करने का लाभ उठाया।
- **पोषण अभियान** के प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रदेश के 6 लाख 47 हजार बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराया गया।
- **आंगनवाड़ियों में जन-सहभागिता** से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए "एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी" अभियान। जनता के सहयोग से करोड़ों रुपये की सामग्री प्राप्त।
- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना** के अंतर्गत 5 करोड़ 44 लाख लोगों को निःशुल्क राशन।

मोदी जी के कुशल नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ता मध्यप्रदेश

धन्यवाद मोदी जी

D-19283/22

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

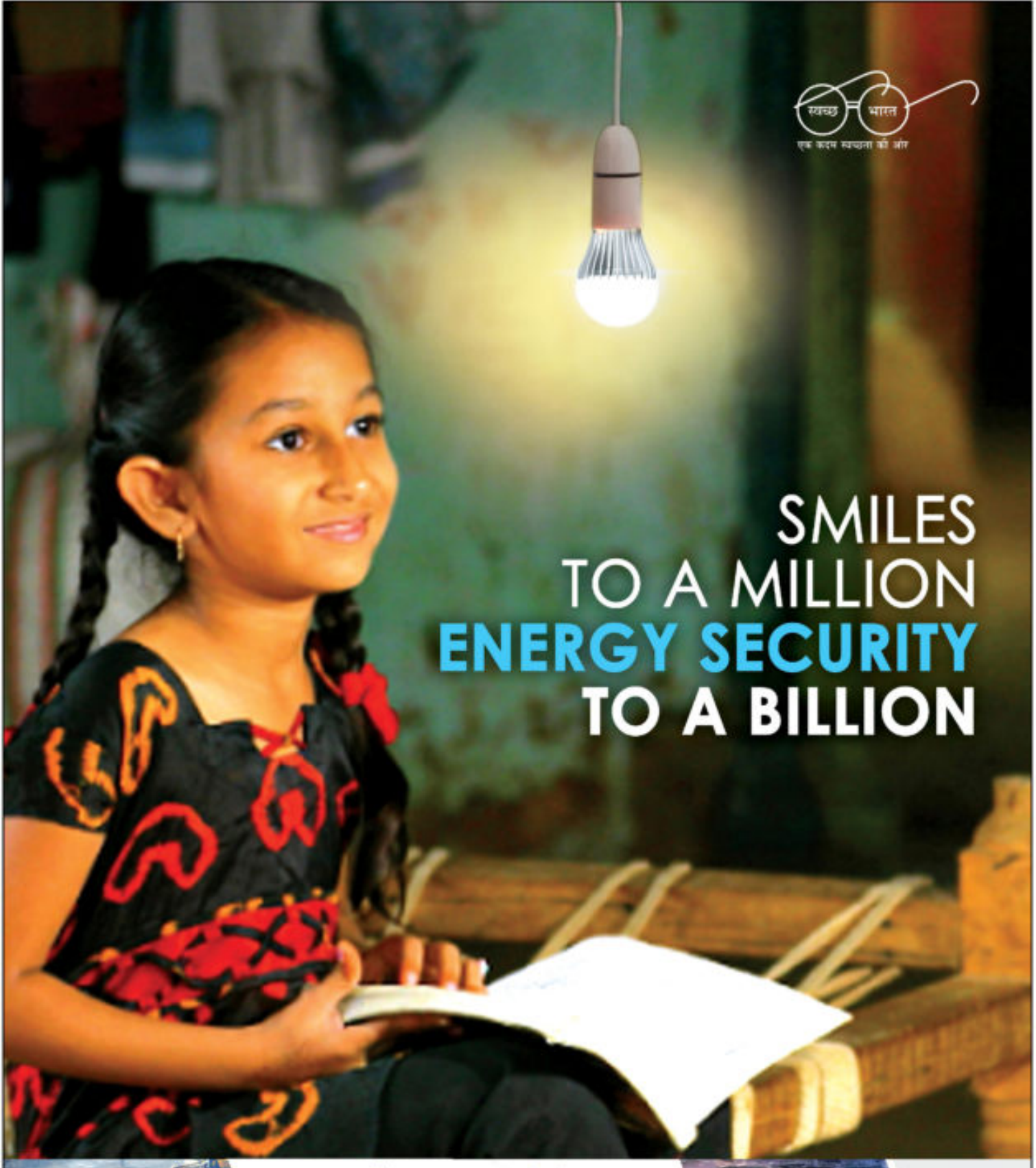

MCL

MAHANADI COALFIELDS LIMITED

(A Govt. of India Undertaking & Subsidiary of Coal India Limited)

Corporate Office: At/Po.- Jagruti Vihar, Burla, Sambalpur, Odisha-768 020

www.mahanadicoal.in   mahanadicoal   mahanadicoal